सूर्योदय 6.08 सूर्यास्त 6:22

आज का तापमान

शिमला	14.5 न्यू	24.4 अधि
धर्मशाला	18.8 न्यू	30.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,294
निफ्टी	23,346

सोना 1,54,000 चांदी 2,37,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 3 अश्विन, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 145, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

वोट चोरी के बाद अब पार्टी चोरी : राहुल गांधी

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न और नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है। वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब पार्टी चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा- पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस। हर बार एक ही पैटर्न- भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। उन्होंने लिखा- जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं। वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।

मोहन भागवत बोले- धर्म को पूजा तक सीमित न रखें, जीवन में उतारें

एजेंसी, उज्जैन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को उज्जैन में युवा धर्म संसद को संबोधित किया। उन्होंने धर्म, पर्यावरण, युवाओं के आचरण और पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत के प्रति उसके रवैये का उल्लेख किया। धर्म संसद में देशभर के 1700 युवा शामिल हो रहे हैं। भागवत ने युवाओं से अपील की कि वे धर्म को केवल पूजा-पद्धति तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन और आचरण में उतारें। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं का जीवन ऐसा होना चाहिए, जिससे पूरा विश्व प्रेरणा ले। भागवत ने कहा कि जब व्यक्ति अहंकार में आकर काम करता है और यह मानता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में। हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, तो उसे गलतफहमी हो जाती है। उन्होंने युवाओं से जीवन में धर्म के सिद्धांतों को समझने और उन्हें आचरण में उतारने की बात कही।

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, बच्चों को लेकर भी बदले नियम

एजेंसी, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अब 18 साल की उम्र या 5 साल तक वैध रहेगा। पहले पासपोर्ट वैधता की उम्र 15 साल थी। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी 5 साल या 18 साल की उम्र में से जो पहले आएगा, वही वैधता की अंतिम सीमा होगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया। इसके जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है।

नीट परीक्षा : पेपर लीक रोकने की तैयारियां परखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज

एनटीए दफ्तर जाएंगे, एजेंसी ने कहा था- एग्जाम सिस्टम फूलप्रूफ बनाया

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर नीट परीक्षा सिस्टम की जांच के लिए जज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के ऑफिस का दौरा करेंगे। वे देखेंगे कि परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने के इंतजाम वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की बेंच यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, फेमा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसमें एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम की मांग की गई है। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नीट परीक्षा सिस्टम फूलप्रूफ है। इसमें सेंध लगाना मुश्किल है।

स्थायी कर्मचारी रखे जाएं

एनटीए के लिए पर्याप्त स्थायी कर्मचारी और विशेषज्ञ स्टाफ रखने की जरूरत पर चर्चा हुई। कोर्ट ने बेहतर मैनपावर, प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। एनटीए को मजबूत कानूनी आधार देने के लिए वैधानिक व्यवस्था पर भी विचार किया गया। कोर्ट ने कहा कि लिखित परीक्षा से डिजिटल परीक्षा की ओर बदलाव अचानक नहीं किया जा सकता। इसे धीरे-धीरे लागू करना होगा, ताकि नई व्यवस्था में परेशानी न हो।

सुप्रीम कोर्ट की सलाह- युवा वकील सीनियर्स से ट्रेनिंग लें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को युवा वकीलों से कहा कि सीनियरों के साथ ट्रेनिंग के बिना वे पेशे की बारीकियां नहीं सीख पाएंगे। जस्टिस बी वी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि युवा वकीलों को कोर्ट में क्या बोलना है और क्या नहीं, यह पता होना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कुछ युवा बिना ट्रेनिंग सीधे अपना ऑफिस शुरू कर रहे हैं। यह बिलकुल सही नहीं है। सीनियरों के साथ काम करने से ही वकालत के असली कौशल और पेशे के तौर-तरीके सीखे जा सकते हैं। ये टिप्पणियां बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि युवा वकीलों को सीनियरों के पास जाना चाहिए। सीनियर उन्हें सही दिशा दिखाएंगे। उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि आजकल युवा महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन सीनियरों के साथ ट्रेनिंग के बिना वे पेशे की बारीकियां नहीं सीख पाएंगे।' उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती आ रही है।

ममता की पार्टी का नाम 'ममता टीएमसी', सिंबल फुटबॉल प्लेयर

एजेंसी, कोलकाता। बंगाल में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से 18 दिन पहले चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं। ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का चिह्न मिला है, जबकि दूसरे गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'लिफाफा' दिया गया है।

इससे एक दिन पहले आयोग ने दोनों गुटों को 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फूल-घास' वाला मूल चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने से रोक दिया था। यह अंतरिम व्यवस्था है। मूल नाम और चिह्न पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, अब दोनों गुट उपचुनाव में नई पार्टी नाम और सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम और रेजीनगर पर 6 अक्तूबर को वोटिंग हैं और रिजल्ट 9 अक्तूबर को आएगा। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 अलग हो गए हैं। अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं।

◆ **बागी गुट 'डेमोक्रेटिक टीएमसी' कहलाएगा, 6 अक्तूबर को होगा उपचुनाव**

टीएमसी के दोनों गुट उम्मीदवार उतार चुके

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्तूबर को उपचुनाव हैं। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी टीएमसी धड़े से मोहम्मद एतेशामुल हक नंदीग्राम और सफीउद्दीन शेख रेजीनगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं, पूर्व सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी ने रविवार को नंदीग्राम से संचिता प्रधान (डे) और रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया था।

राज्यसभा की बात करें तो 13 में से दो सांसद इस्तीफा दे चुके हैं यानी सिर्फ 11 राज्यसभा सांसद बचे हैं। विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 सीटें जीतीं थीं। जिसमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं।

अरब सागर में टक्कर पर भारत ने पाक के आरोप किए खारिज

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ने अरब सागर में भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता और पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज पीएनएस हुनैन के बीच हुई टक्कर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि आईएनएस कोलकाता पश्चिमी अरब सागर में नियमित तैनाती पर था, जबकि पाकिस्तानी जहाज ने अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर तरीके से पैंतरेबाजी की, जिसके कारण टक्कर हुई। उन्होंने कहा कि आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और वह समुद्र में तैनात है। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी जहाज ने सुरक्षित समुद्री संचालन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों और दोनों देशों के बीच 1991 में हुए समझौते का उल्लंघन किया। समझौते के तहत दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों को एक-दूसरे से तीन नॉटिकल मील से कम दूरी पर नहीं आना चाहिए।

सीएम रेखा ने 75 सीएम श्री सरकारी विद्यालयों में हेरिटेज क्लबों की स्थापना का किया शुभारंभ

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 75 सीएम श्री सरकारी विद्यालयों में हेरिटेज क्लबों की स्थापना का शुभारंभ किया।

दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग तथा दिल्ली अभिलेखागार द्वारा हेरिटेज क्लबों के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावहारिक और छात्र-केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल में होने वाली प्रत्येक गतिविधि, हर पहल और किताब का एक-एक पन्ना बच्चे के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी सोच के साथ शुरू किए जा रहे हेरिटेज क्लब विद्यार्थियों को दिल्ली की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य और दस्तावेजी विरासत से सीधे जोड़ने का माध्यम बनेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और उनके लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। देश की दिल्ली का इतिहास अत्यंत समृद्ध है। यहां विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों, सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक स्थलों, स्मारकों और स्थापत्य विरासत से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण स्मृतियां मौजूद हैं।

धौलासिद्ध परियोजना एसजेवीएनएल से वापस लेगी सरकार : सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा- कांगड़ा पर्यटन और हमीरपुर बनेगा शिक्षा की राजधानी

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को एसजेवीएनएल से वापस लेने के लिए 800 करोड़ रुपए देगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी पर 31.19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 250 मीटर लंबे डबललेन सधोड़ा पत्तन पुल के शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुल नादौन के दोबड़ कलां को ज्वालामुखी के सिल्ह गांव से जोड़ेगा। इससे नादौन और ज्वालामुखी की 15 पंचायतों के 30 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा तथा दोनों क्षेत्रों के बीच दूरी और यात्रा समय कम होगा।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर के दावों पर कहा कि इसकी अधिसूचना 22 जनवरी 2014 को हुई थी और तत्कालीन केंद्र सरकार ने 180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कॉलेज के निर्माण पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहां करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से जापान के सहयोग से कैंसर संस्थान और 150 करोड़ रुपए से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में करीब 28-28 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। सरकार कांगड़ा को पर्यटन और हमीरपुर को शिक्षा राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। नादौन में खेल उत्कृष्टता केंद्र तथा ब्यास किनारे 400 करोड़ रुपए से रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश की संपदा के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता 1.50 लाख से बढ़ाकर 8.50 लाख रुपए की गई। इस दौरान ज्वालामुखी विधायक संजय रतन, विधायक कमलेश ठाकुर समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

हरियाणा में 19.91 लाख पशुओं का बीमा 32,679 दावों में 123.68 करोड़ का भुगतान

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा में 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना' के तहत 31 अगस्त 2026 तक 19.91 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 से 31 अगस्त 2026 तक 32,679 पशु बीमा दावों का निपटारा कर पशुपालकों को 123.68 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

योजना के तहत सामान्य श्रेणी के पशुपालकों के लिए प्रीमियम राशि पर 85 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 100 प्रतिशत सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक मजबूत कर रही है। सरकार का लक्ष्य केवल पशुपालकों की आय बढ़ाना ही नहीं, बल्कि पशुधन की उत्पादकता, स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और ग्रामीण परिवारों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सुनिश्चित करना है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ आधुनिक पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

◆ **पशुपालकों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता : सीएम सैनी**

सरकार की नीतियों का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के डेयरी क्षेत्र पर साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, पशुधन की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में हरियाणा देश में पंजाब और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है।

एयरफोर्स के पायलट अब स्वदेशी विमान से लेंगे ट्रेनिंग

इसका 57% सामान भारत में बना, पवन हंस कंपनी को 4 ध्रुव हेलिकॉप्टर मिले

एजेंसी, बेंगलुरु। इंडियन एयरफोर्स को शुक्रवार को स्वदेशी ट्रेनर विमान एचटीटी-40 मिला है। इसका नाम 'अंकुर' रखा गया है। इस विमान को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है।

वायुसेना ने 2023 में 70 एचटीटी -40 विमानों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। समझौते के मुताबिक डिलीवरी सितंबर 2025 से शुरू होनी थी। हालांकि इसमें करीब एक साल की देरी हुई। इसके अलावा एचएएल ने 2 तेजस ट्रेनर विमान भी एयरफोर्स को सौंपे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में शुक्रवार को विमानों के हैंडओवर प्रोग्राम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने विमानों की पूजा की। कार्यक्रम में

एचएएल ने चार नए ध्रुव हेलिकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड को सौंपे। राजनाथ हेलिकॉप्टर के कॉकपिट में भी बैठे। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को दो एलसीए एफओसी ट्रेनर विमान सौंप दिए। इससे एफओसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत चार ट्विन-सीटर विमानों की डिलीवरी पूरी हो गई। इन विमानों में बेहतर रडार, ऑटोपायलट, फ्यूल सिस्टम, सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग प्रोब जैसी सुविधाएं हैं। एचएएल ने पवन हंस कंपनी को चार ध्रुव एनजी हेलिकॉप्टर सौंपे। यह पहली बार होगा जब सिविल सर्टिफाइड ध्रुव एनजी को सिविल एविएशन क्षेत्र में शामिल किया गया। यह एचएएल द्वारा डिजाइन और निर्मित 5.5 टन का हल्का ट्विन-इंजन मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर है।

ममता के समर्थन के 2 घंटे बाद कांग्रेस कैंडिडेट गिरफ्तार

एजेंसी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से 18 दिन पहले ममता गुट की महिला कैंडिडेट संचिता प्रधान डे ने शुक्रवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन वापस ले लिया है। संचिता ने इससे पहले बंगाल सीएम शुभेंदु से मुलाकात की थी। हालांकि, रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी मैदान में बने रहेंगे। ममता ने 13 सितंबर को दोनों कैंडीडेट के नामों की घोषणा की थी। इसके बाद ममता ने नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने की बात कही। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने दावा किया कि इसके 2 घंटे बाद बंगाल पुलिस ने मिलन को एक पुराने केस में अरेस्ट कर लिया। नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खाली की थी।

पंजाब के सरकारी मुलाजिमों को 50% डीए मिलेगा सीएम मान की मीटिंग में 8% बढ़ौतरी पर सहमति

एजेंसी, लुधियाना। पंजाब के सरकारी मुलाजिमों को 50% डीए मिलेगा, इसका फैसला शुक्रवार को मुलाजिम यूनियन की चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान के साथ मीटिंग में हुआ। यहां ये भी तय हुआ कि सरकार मुलाजिमों का बकाया 8% डीए जारी करेगी। 8% डीए देने से सरकार पर करीब 248 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

मुलाजिम यूनियन के नेताओं के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अगले महीने की सैलरी से बढ़ा हुआ डीए मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम के साथ मीटिंग के बाद मुलाजिमों का डेडलॉक टूट गया है। मुलाजिम हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का हक है और सरकार को उसको

◆ **मंत्री बोले- अगले महीने की सैलरी में जुड़ेगा**

◆ **सीएम मान से बैठक के बाद कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति**

सुनना चाहिए। इससे पहले जालंधर में सीएम भगवंत मान ने मुलाजिम यूनियन से मीटिंग से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पहले हड़ताल खत्म करो, उसके बाद ही बात होगी। जब मुलाजिम नेता नहीं माने तो सीएम वहां से बिना बातचीत किए चले गए। अमन अरोड़ा ने कहा कि मीटिंग में सीएम भगवंत मान ने कर्मचारियों की सभी मांगें विस्तार से सुनी हैं। उन्होंने कहा कि 99% मुद्दे पिछली सरकारों की देन हैं। कर्मचारियों के साथ आगे भी बैठकें जारी रहेंगी और करीब दो सप्ताह बाद सीएम के साथ फिर मीटिंग होगी। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि बैठक में दो मेन पॉइंट्स पर सहमति बनी है, एक डीए और दूसरा किसी भी मुद्दे को आपस में बैठकर सुलझाने का। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की बनाई गई गांठें अब खोलना शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों और सरकार के बीच कोर्ट-कचहरी तक पहुंचे विवादों को भी बातचीत के जरिए खत्म करने की कोशिश की जाएगी।

योगी आदित्यनाथ से भूपेंद्र यादव ने की शिष्टाचार भेंट

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को उनके सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग, लखनऊ पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच हुई मुलाकात के दौरान पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्र के विकास और जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। मुलाकात के दौरान प्रदेश में हरित क्षेत्र के विस्तार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की जानकारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

◆ **पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र के विकास पर हुआ मंथन**

कार्यक्रम मां यमुना की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, हरि घाट का उद्घाटन, आस्था और संस्कृति को मिली नई पहचान

यमुना भारतीय आस्था व संस्कृति की महत्वपूर्ण धारा: सीएम धामी

विकास बलोनी, भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। हरिपुर कालसी में यमुना तट पर विकसित हरि घाट व मां यमुना की भव्य 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए यमुना घाट का उद्घाटन किया और मां यमुना की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान यमुना तट पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें साधु-संतों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने यमुना आरती में भी सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान यमुना-कृष्ण मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी गई। हरि घाट, मां यमुना की प्रतिमा और प्रस्तावित मंदिर के विकास से हरिपुर-कालसी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। इससे क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक

पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण आधार है। यमुना तट से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में भी सहायक हो सकता है। आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम और विशेष प्रार्थना भी आकर्षण का केंद्र रही। साधु-संतों की मौजूदगी, यमुना आरती और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में नजर आया। स्थानीय लोगों की भागीदारी और टिकाऊ पर्यटन को प्राथमिकता देकर क्षेत्र का विकास किया जाना इस परियोजना को दीर्घकालिक रूप से उपयोगी बना सकता है।

हरि घाट के विकास में अधिकारियों और टीम का रहा अहम योगदान

इस विकास यात्रा में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी (आईएएस), डॉ. आशीष चौहान (आईएएस) तथा सूचना अधिकारी प्रियंका जोशी (डीआईओ) के प्रयासों और व्यवस्थागत सहयोग का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। घाट के सौंदर्यीकरण और निर्माण से जुड़ी व्यवस्थाओं को गति देने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयास महत्वपूर्ण रहे। हरिपुर कालसी में मां यमुना की भव्य प्रतिमा आस्था का प्रतीक बनी है, जबकि हरि घाट धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। क्षेत्र के समग्र विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय हितों को प्राथमिकता देकर इसे आने वाले समय में प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

बंशीधर तिवारी की निगरानी में विकसित हुआ भव्य स्नान घाट

हरिपुर कालसी के यमुना तट को विकसित करने की परियोजना में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। करीब 7.52 करोड़ रुपए की लागत से विकसित स्नान घाट में श्रद्धालुओं के लिए स्नान, बैठने, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। परियोजना की निगरानी और समन्वय में भी तिवारी की भूमिका उल्लेखनीय रही। उन्होंने कहा कि नए घाट के निर्माण से हरिपुर कालसी का यमुना तट अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक स्वरूप में विकसित हुआ है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की सराहना की।

2029 तक नशामुक्त भारत के लिए तैयार हुआ रोडमैप

युवाओं को नशे से बचाने के साथ उपचार सुविधाएं बढ़ाने की बनाई गई योजना

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने के लिए तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार इस रोडमैप में स्पष्ट समय-सीमा, नियमित निगरानी, मापनीय परिणाम और कार्ययोजना निर्धारित की गई है। इसी के तहत शिमला में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।

पत्र सूचना कार्यालय, शिमला की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान-2026 पर आयोजित 'वार्तालाप' कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर महानिदेशक (मीडिया) राज कुमार ने रोडमैप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 26 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 10वीं शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में 'विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029' जारी किया था। इसे तैयार करने के लिए 35 से अधिक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा राज्यों की एनसीओआरडी बैठकों और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सम्मेलनों से भी सुझाव लिए गए।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चंडीगढ़ और अमृतसर के जोनल निदेशक अमनजीत सिंह ने प्रस्तुति के माध्यम से अभियान के लक्ष्यों और अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2019 से जुलाई 2026 तक 93,33,987 किलोग्राम मादक एवं मन:प्रभावी पदार्थ जब्त किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य 1,53,212 करोड़ रुपये है। इसी अवधि में 44,88,576 किलोग्राम जब्त पदार्थ नष्ट किए गए। करीब 3,992 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां फ्रीज या जब्त की गईं और 128 अवैध गुप्त प्रयोगशालाओं को ध्वस्त किया गया।

◆ तीन साल की कार्ययोजना में प्रवर्तन, पुनर्वास और जागरूकता को दी गई प्राथमिकता

उन्होंने बताया कि भारतपोल के माध्यम से 195 देशों के साथ इंटरपोल संपर्क स्थापित हुआ है, जबकि मानस हेल्पलाइन 1933 से 3.33 लाख से अधिक नागरिक जुड़े हैं। रोडमैप चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है—खुफिया जानकारी एवं अभियान आधारित प्रवर्तन, प्रीकर्सर व सिंथेटिक ड्रग्स नियंत्रण, मांग एवं नुकसान में कमी तथा क्षमता निर्माण एवं समन्वय।

रोडमैप में नशे के स्रोत, तस्करी के मार्ग, पेडलरों, भुगतान माध्यमों और सरगनाओं की पहचान पर जोर दिया गया है। साथ ही परिवहन, डार्कनेट नेटवर्क, हवाला और मादक पदार्थों के वित्तपोषण को बाधित करने तथा अवैध प्रयोगशालाओं, अवैध खेती और तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की योजना है। इसमें 25 घटक और 200 से अधिक कार्य बिंदु शामिल हैं।

नशीली दवाओं की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी गई है। मार्च 2029 तक नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 334 से बढ़ाकर 1751 करने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं विकसित करने तथा प्रत्येक राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में समर्पित विभाग स्थापित करने की योजना है। अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाते हुए इसकी पहुंच 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ लोगों तक करने का लक्ष्य है। एनसीसी, एनएसएस और माय भारत के माध्यम से एक लाख 'नशा मुक्त भारत मित्र' तैयार किए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजों को नशे के खिलाफ जागरूकता की पहली पंक्ति बनाने पर भी जोर दिया गया है।

नशे के विरुद्ध अभियान में प्रशासन और एनसीबी के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

शिमला में एनसीबी कार्यालय के लिए जल्द मिलेगी भूमि

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक राज कुमार एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक अमनजीत सिंह ने शुक्रवार को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गृह मंत्रालय एवं एनसीबी की ओर से किए जा रहे विभिन्न प्रयासों और गतिविधियों की जानकारी उपायुक्त को दी। उन्होंने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। उपायुक्त ने अधिकारियों को जिला प्रशासन की ओर से नशे की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया।

नशे के खिलाफ जागरूकता गतिविधियों को विस्तार देने पर जोर : उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ युवाओं एवं आमजन की भागीदारी से जन-जागरूकता गतिविधियों को और व्यापक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। प्रशासन की ओर से विद्यालयों और अन्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नशा विरोधी गतिविधियों में प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

स्कूलों में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए किया जा रहा प्रेरित

अनुपम कश्यप ने बताया कि जिला प्रशासन के लगभग सभी अधिकारियों ने स्कूल गोद लिए हुए हैं। अधिकारी समय-समय पर संबंधित विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करते हैं और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए समय रहते जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इस दिशा में विद्यालय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के साथ अभिभावकों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

जोनल कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह

एनसीबी अधिकारियों ने शिमला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल कार्यालय स्थापित करने के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस संबंध में जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान को जिला में व्यापक स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय एवं एनसीबी को जिला प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान करने की बात कही। इस अवसर पर प्रेस सूचना ब्यूरो शिमला के सहायक निदेशक संजीव कुमार शर्मा तथा पीआईबी चंडीगढ़ के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान भी उपस्थित रहे।

अनिरुद्ध सिंह ने किया नवनिर्मित पटगेहर पंचायत घर का शुभारंभ

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पटगेहर में 7.36 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने 1.14 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवनिर्मित पटगेहर पंचायत घर का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह पंचायत भवन ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। भवन में पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

मंत्री ने कहा कि पटगेहर क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया गया है। लंबा जुब्बड़ से करयाली सड़क को चौड़ा और पक्का करने पर 1.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पेहला नंबर नाला से गांव गवाही तक सड़क निर्माण के लिए 1.43 करोड़ रुपये तथा गजेन से भराड़ी नाला वाया लधोड़ा संपर्क सड़क के लिए 3.29 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के छोटे-बड़े गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 14.58 करोड़ रुपये के सड़क एवं भवन निर्माण कार्य भी जारी हैं।

◆ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने पटगेहर में किए 7.36 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पटगेहर से जगरोटी सड़क को आगे सुराला सड़क से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीणों से पंचायत की छोटी सड़कों के लिए आवश्यक भूमि की गिफ्ट डीड जल्द उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, ताकि निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा सके।

सेंट बीड्स कॉलेज में युवाओं ने नशामुक्ति का लिया संकल्प

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। सेंट बीड्स कॉलेज, शिमला की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से मेरा युवा भारत, शिमला और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 'माय भारत' पोर्टल एवं 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' विषय पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को युवा गतिविधियों, स्वयंसेवी अवसरों और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा।

कार्यक्रम में माय भारत के उप निदेशक विपिन कुमार ने विद्यार्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण, प्रोफाइल तैयार करने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को विकसित भारत युवा नेता संवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच युवाओं को अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने के अवसर देते हैं।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में युवा स्वयंसेवक आशीता शर्मा ने नशे के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।

हर पंचायत को आदर्श बनाने के लिए विकास कार्य तेज करने के निर्देश : अनुपम कश्यप

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता , शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने शुक्रवार को जिले के चार विकास खंड मशोबरा, जुब्बल, नारकंडा और बसंतपुर के खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और समन्वित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सुदृढ़ कार्य-तंत्र तैयार किया गया है। सांसद निधि, विधायक निधि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय बजट के माध्यम से स्कूल भवनों, अस्पताल भवनों तथा अन्य आधारभूत और जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में हाल ही में निर्वाचित नए जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है।

पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं : उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को योजनाओं और सुविधाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जिसके कारण उन्हें अपने कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पंचायत स्तर पर लोगों को योजनाओं, पात्रता और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में चार विकास खंडों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है।

अपना परिवार सुखी परिवार योजना पर जोर

उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' दो अक्टूबर, 2026 को शुरू की जाएगी। अधिकारियों को योजना के तहत पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें इससे जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ना सरकार का संकल्प है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

छोटा शिमला में आयुष्मान आरोग्य शिविर में 122 मरीजों की हुई जांच

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला शिमला की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र), छोटा शिमला के सामुदायिक भवन में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें नजदीक और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। शिविर में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इस दौरान रक्तचाप, रक्त शर्करा, सामान्य स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं।

हिम बस प्लस कार्ड पर भाजपा ने सरकार से मांगा जवाब

नई व्यवस्था में रियायतों और कैशबैक की शर्तों को लेकर उठाए सवाल, पारदर्शिता की मांग

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की नई कार्ड व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड की जगह हिम बस प्लस कार्ड लागू करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नई व्यवस्था से आम यात्रियों को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि पुराने कार्डों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को 10 से 30 प्रतिशत तक किराया रियायत मिलती थी। अब इनकी जगह 365 रुपये की वार्षिक वैधता वाला हिम बस प्लस कार्ड लाया गया है। इसमें सामान्य यात्रियों को पांच प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 15 प्रतिशत छूट का प्रावधान बताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पुराने और नए कार्ड के तहत मिलने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।

उन्होंने कैशबैक योजना की शर्तों पर भी सवाल उठाए। योजना के तहत मासिक यात्रा खर्च के आधार पर 100 से 2,000 रुपये तक कैशबैक देने का प्रावधान बताया गया है। भारद्वाज ने पूछा कि कितने सामान्य यात्री हर महीने बस यात्रा पर पांच हजार या दस हजार रुपये खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि कम यात्रा करने वाले यात्रियों को इस योजना का कितना लाभ मिलेगा, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में टिकट लेते समय ही निर्धारित रियायत मिल जाती थी, जबकि नई व्यवस्था में पहले निर्धारित राशि खर्च करनी होगी और उसके बाद कैशबैक मिलेगा।

◆ नई योजना में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भाजपा ने मांगा स्पष्ट जवाब

बताया गया है कि कैशबैक की राशि अगले महीने की 10 तारीख को खाते में भेजी जाएगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए एचआरटीसी महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। ऐसे में रियायतों में बदलाव का सीधा असर यात्रियों के बजट पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से पुराने कार्डधारकों की संख्या, मिलने वाली रियायत और नई व्यवस्था से संभावित लाभ का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।

सेब मंडियों में नियम तोड़ने पर 12 आढ़तियों के हुए चालान

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) शिमला एवं किन्नौर तथा एपीएमसी सोलन ने अपनी-अपनी सेब मंडियों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत मंडियों में सेब की खरीद-बिक्री से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। अधिकारियों की ओर से मंडी परिसर में नियमों के अनुपालन की जांच करने के साथ अनियमितता मिलने पर संबंधित कमीशन एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के दौरान एपीएमसी सोलन ने नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में सात कमीशन एजेंटों यानी आढ़तियों के चालान किए हैं। वहीं, एपीएमसी शिमला एवं किन्नौर की ओर से नियमों के उल्लंघन पर पांच कमीशन एजेंटों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई है। इस तरह अब तक तीनों मंडी समितियों की ओर से कुल 12 कमीशन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मंडी समितियों का कहना है कि सेब कारोबार से जुड़े सभी पक्षों को निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है।

◆ किसानों से निर्धारित कार्टन में उपज लाने और मानकों का पालन करने की अपील

कृषकों से अपील की गई है कि वे अपनी सेब की उपज मंडियों में यूनिवर्सल कार्टन में ही लेकर आएं। साथ ही सेब की ग्रेडिंग निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप करने को कहा गया है। मंडी परिसरों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में किसान इसकी शिकायत कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सऐप नंबर 9459172727 जारी किया गया है।

खेलों से सजा आईटीएचएम का पर्यटन सप्ताह, विद्यार्थियों में उत्साह

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन संस्थान (आईटीएचएम) की ओर से विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पर्यटन सप्ताह 2026 का शुक्रवार को खेल प्रतियोगिताओं के साथ शानदार आगाज हुआ। इस वर्ष पर्यटन सप्ताह की थीम 'हिम विरासत—जहां विरासत जीवंत है, संस्कृति जुड़ती है और पर्यटन सतत बनता है' रखी गई है। पर्यटन सप्ताह के प्रथम चरण में 18 से 21 सितंबर तक टूरिज्म प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है।

टूरिज्म प्रीमियर लीग के पहले दिन विद्यार्थियों ने क्रिकेट, वॉलीबाल, रस्साकशी, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का परिचय दिया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को साथी विद्यार्थियों ने उत्साह बढ़ाकर प्रोत्साहित किया। खेल गतिविधियों से परिसर में उत्साह और ऊर्जा का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष मनोहर लाल रहे। सहायक आचार्य एवं क्रिकेट प्रशिक्षक विक्रांत भारद्वाज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

समापन छह दिवसीय सम्मेलन में लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर हुआ विस्तृत विचार-विमर्श

राष्ट्रमंडल सम्मेलन में पठानियां ने रखी हिमाचल की बात

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 13 से 18 सितंबर, 2026 तक आयोजित छह दिवसीय 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का शनिवार को भव्य समापन हुआ। सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के 56 देशों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि पठानियां ने 'राष्ट्रमंडल के लिए नेतृत्व के नए अवसर : लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्रवाई' विषय पर अपने विचार रखे।

अपने संबोधन में पठानियां ने कहा कि राष्ट्रमंडल स्वतंत्र और संप्रभु देशों का स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग, लोकतंत्र, सुशासन, मानवाधिकार, आर्थिक विकास, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि 1949 के लंदन घोषणापत्र के बाद राष्ट्रमंडल ने आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया और समय के साथ इसमें विभिन्न महाद्वीपों के अनेक देश शामिल होते गए।

पठानियां ने कहा कि राष्ट्रमंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सदस्य देश आकार, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से एक-दूसरे से काफी अलग हैं। इसके बावजूद लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन, समानता और सतत विकास जैसे साझा मूल्यों के आधार पर सभी देश एक मंच पर सहयोग करते हैं।

उन्होंने शिक्षा और युवा विकास में राष्ट्रमंडल की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रवृत्ति, कौशल विकास, युवा नेतृत्व और क्षमता निर्माण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल भी सदस्य देशों के बीच मैत्री और खेल भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। पठानियां ने कहा कि भारत के लिए राष्ट्रमंडल का विशेष महत्व है। भारत इस मंच के माध्यम से विकासशील देशों की प्राथमिकताओं, लोकतांत्रिक मूल्यों, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, व्यापार और युवाओं से जुड़े विषयों पर सहयोग करता है।

रेणुका क्षेत्र में अदरक की फसल में रोग की आशंका

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के विकास खंड संगड़ाह के काकोग गांव में अदरक की फसल में फाइलोस्टिक्टा ब्लाइट रोग का प्रकोप पाया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण कर किसानों को रोग की रोकथाम और प्रबंधन की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के सह निदेशक एवं वैज्ञानिक प्रभारी डॉ. पंकज मित्तल, उपनिदेशक कृषि डॉ. साहब सिंह, परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. नवदीप कौंडल सहित विशेषज्ञों ने खेतों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अदरक की पत्तियों पर भूरे और गहरे भूरे धब्बे पाए गए। विशेषज्ञों ने बताया कि अधिक संक्रमण में धब्बे फैलने से पत्तियां सूख सकती हैं और पौधे की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। किसानों को संक्रमित पत्तियां हटाकर नष्ट करने, खेत में जलभराव रोकने और उचित जल निकासी बनाए रखने की सलाह दी गई। साथ ही रोगग्रस्त अवशेष खेत में न छोड़ने तथा मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने को कहा गया।

आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि करे कांग्रेस : धामी

यूआईआईडीबी, बिजली खरीद पर कांग्रेस के आरोपों को धामी ने घेरा

अनिल थपलियाल

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष राजनीतिक मुद्दों के अभाव में झूठ, भ्रम और बेबुनियाद आरोपों के जरिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। शुक्रवार को कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांग्रेस के प्रत्येक आरोप का जवाब तथ्यों, दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आरोपों की वास्तविकता सामने आने के बाद कई दावे स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं।

हल्द्वानी की एक घटना को जातिगत भेदभाव से जोड़ने संबंधी कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में सामने आए तथ्यों में घटना से जुड़े पांच लोगों के अनुसूचित जाति समाज से होने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सामाजिक विषयों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि की जानी चाहिए।

भूमि आवंटन के आरोपों पर धामी ने दिया जवाब

यूआईआईडीबी के मुद्दे पर धामी ने कांग्रेस के 7,000 बीघा जमीन दिए जाने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बोर्ड को अब तक 45 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार पहले भी 7,000 बीघा भूमि के आवंटन के आरोप को तथ्यात्मक रूप से गलत बता चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूआईआईडीबी का उद्देश्य पर्यटन और आधारभूत ढांचे के विकास के जरिए निवेश तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर तैयार करना है।

बिजली खरीद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन उसे अपने शासनकाल में लिए गए फैसलों का भी हिसाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय हुए गैस पावर करार के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को गैस आधारित बिजली के लिए 31.71 रुपये प्रति यूनिट तक भुगतान करना पड़ा। इसके मुकाबले वर्तमान सरकार ने 1,320 मेगावाट बिजली की व्यवस्था करीब 5.74 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए सुनिश्चित की है।

धामी बोले, पारदर्शिता से काम कर रही सरकार

उन्होंने कहा कि पीक आॅवर में राज्य को कई बार महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, इसलिए दीर्घकालिक बिजली व्यवस्था ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

अंकिता भंडारी प्रकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले में शुरुआत से कानूनी कार्रवाई की। तीनों दोषियों को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अगस्त 2026 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी तीनों दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता के माता-पिता की मांग पर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी और आगे भी कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

धामी ने कहा कि संवेदनशील मामलों में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के सामने हर विषय पर तथ्य और दस्तावेज रखने के लिए तैयार है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसे सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक बहस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा जनकल्याण से जुड़े विषयों पर अपने निर्णयों का विवरण जनता के सामने रखने से पीछे नहीं हटेगी।

धामी ने नेपाल राहत दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अनिल थपलियाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से गोर्खाली सुधार सभा के केंद्रीय अध्यक्ष पदम सिंह थापा के नेतृत्व में आठ सदस्यीय नेपाल आपदा राहत सहायता दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नेपाल भारत का पड़ोसी होने के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी गहरे संबंध रखने वाला देश है। प्राकृतिक आपदा की कठिन घड़ी में उत्तराखंड और भारत के लोग नेपाल के प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने राहत दल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय जरूरतमंदों की सहायता करना मानवीय जिम्मेदारी है।

गोर्खाली सुधार सभा के केंद्रीय अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने बताया कि राहत दल नेपाल में प्रभावित लोगों की सहायता के साथ एक गांव को गोद लेकर प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहयोग देगा। इसके अलावा बच्चों के लिए स्कूल भवन निर्माण में सहयोग करने के साथ विद्यार्थियों को पुस्तकें और पठन-पाठन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। राहत कार्यों के लिए नेपाल सरकार और वहां की स्वयंसेवी संस्थाओं से लगातार समन्वय किया जा रहा है।

दलहन उत्पादन बढ़ाने को प्रभावी कार्ययोजना बनाएगा उत्तराखंड

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में उत्पादित दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नैफेड एवं एनसीडीसी के माध्यम से खरीद का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने और अनुमोदन प्राप्त करने को कहा।

शुक्रवार को सचिवालय सभागार में भारत सरकार की दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सेल गठित करने और इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संगठित किसान समूहों के माध्यम से दलहन के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने दलहन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाकर 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा। इसके लिए उन्नत बीज, बेहतर कृषि तकनीक, फसल प्रदर्शन और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

गढ़वाल विश्वविद्यालय में 200 विद्यार्थियों ने लिया नशामुक्ति का संकल्प

नशामुक्त भारत, विकसित भारत और युवा कनेक्ट कार्यक्रमों से जुड़ेंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय के युवा

अनिल थपलियाल

श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर में शुक्रवार को नशामुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों और एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में करीब 200 विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉ. राकेश सिंह नेगी ने विद्यार्थियों एवं एनएसएस स्वयंसेवकों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने, स्वयं जागरूक रहने और समाज के अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ

जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे के कारण होने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान संबंधित मंत्रालय के साथ आॅनलाइन संवाद भी आयोजित किया गया। इसमें विकसित भारत युवा संवाद, नशामुक्त भारत और युवा कनेक्ट जैसे कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। अधिक से अधिक युवाओं को इन गतिविधियों से जोड़ने और माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। युवाओं से कहा गया कि वे अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग सकारात्मक गतिविधियों में करें तथा समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।

विश्वविद्यालय परिसर को नशामुक्त बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया कि परिसर में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों से परिसर में स्वस्थ और अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने का आह्वान किया गया।

डॉ. राकेश सिंह नेगी ने कहा कि देश के विकास और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहते हुए शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा अपनी सकारात्मक सोच और ऊर्जा के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं।

कुंभ की तैयारियों को लेकर एडीजी ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने सीसीआर सभागार में पुलिस विभाग की प्रारंभिक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला द्वारा अब तक की तैयारियों और आगामी कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया। एडीजी ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन, संचार व्यवस्था, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और चरणवार पुलिस बल की तैनाती को लेकर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी योजनाओं को अंतिम रूप देकर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

एडीजी डॉ. मुरुगेशन ने कहा कि कुंभ मेला धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। इसे निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र में बनाए जा रहे जोन और सेक्टर की व्यवस्थाओं को समय रहते फाइनल किया जाए। यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए स्पष्ट व प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए।

ईशा शर्मा बनीं उत्तराखंड क्रांति दल की महिला जिला अध्यक्ष

महिला कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने और गतिविधियां बढ़ाने की मिली जिम्मेदारी

अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अधिवक्ता मनोज कंडवाल ने संगठन को मजबूत करने और महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ईशा शर्मा को महिला जिला अध्यक्ष, देहरादून के पद पर मनोनीत किया है। उनके मनोनयन से संगठन में महिला नेतृत्व को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है।

मनोज कंडवाल ने ईशा शर्मा के मनोनयन पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वह संगठन की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के साथ अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए सक्रियता से कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों में आगे लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ईशा शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने से देहरादून जिले में महिला प्रकोष्ठ की गतिविधियों को और गति मिलेगी। वह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगी। साथ ही महिलाओं से जुड़े मुद्दों को संगठन के माध्यम से प्रमुखता से उठाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

मनोज कंडवाल ने उम्मीद जताई कि नई जिम्मेदारी के माध्यम से संगठन की गतिविधियों को ग्रामीण और

शहरी क्षेत्रों तक विस्तार देने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन के साथ जोड़कर उन्हें सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ईशा शर्मा के मनोनयन पर उत्तराखंड क्रांति दल के और पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि वह नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ करेंगी। उनके नेतृत्व में देहरादून जिले में महिला संगठन को नई मजबूती मिलने के साथ पार्टी की गतिविधियों को भी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

थलीसैंण में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान शुरू

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। नगर पंचायत थलीसैंण में शुक्रवार को 'स्वच्छता ही सेवा-2026' अभियान का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ स्वच्छता और जनभागीदारी का संकल्प लेते हुए नगर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी कृष्णा त्रिपाठी ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता किसी एक अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने घरों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने का आह्वान किया।

एसडीएम ने कहा कि अभियान के तहत नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी, ताकि स्वच्छता को जनआंदोलन का रूप दिया जा सके।

नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक प्रताप ने नगरवासियों से कूड़ा इधर-उधर न फेंकने और कचरे का उचित निस्तारण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए आमजन की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत रामलीला मैदान में लगा स्वास्थ्य शिविर

स्वास्थ्य शिविर में 145 मरीजों की जांच, जरूरतमंदों को मिली निशुल्क दवाएं

अनिल थपलियाल

पिथौरागढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 83 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान जरूरतमंद मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श देने के साथ निशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच कराई और चिकित्सकों से आवश्यक परामर्श लिया।

शिविर के दौरान संभावित टीबी और श्वसन संबंधी रोगों की पहचान के लिए 18 लोगों के चेस्ट एक्स-रे किए गए। इसके अलावा 84 लोगों के रक्तचाप और ब्लड शुगर की जांच की गई। जांच के बाद चिकित्सकों ने मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार

उन्हें आवश्यक सलाह दी। कुल 33 मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को विभिन्न बीमारियों के शुरुआती लक्षणों के प्रति जागरूक करते हुए समय पर जांच कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से कई बीमारियों की समय रहते पहचान की जा सकती है और उनका उपचार शुरू किया जा सकता है। विशेष रूप से टीबी और श्वसन संबंधी समस्याओं को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।

शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को संतुलित जीवनशैली अपनाने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार उपचार लेने के लिए प्रेरित किया। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों का उद्देश्य लोगों को उनके आसपास ही जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना है।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर महिला आयोग उपाध्यक्ष चंद्रकला तिवारी ने किया तुलसी पूजन

प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ जीवन की चंद्रकला तिवारी ने की कामना

गिरीश चंदोला

चमोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को उत्तराखंड में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चंद्रकला तिवारी ने अपने निजी आवास पर दीप प्रज्वलित कर तुलसी पूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की और देशवासियों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

चंद्रकला तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से समाज के अलग-अलग वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

चमोली में पीएम के जन्मदिन पर मंदिरों में हुए आयोजन

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सभी लोगों को देश की प्रगति और जनकल्याण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी से ही विकास की प्रक्रिया को और गति दी जा सकती है। इस अवसर पर उन्होंने देश में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर चमोली जिले के विभिन्न स्थानों और मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वेदनी कुंड में स्नान-पूजन के बाद नंदादेवी बड़ी जात यात्रा आगे बढ़ी

15वें पड़ाव पर पहुंची नंदादेवी बड़ी जात यात्रा

अनिल थपलियाल

थराली। अनुकूल मौसम के बीच श्री नंदादेवी बड़ी जात यात्रा शुक्रवार को अपने 15वें पड़ाव पातरनचौनिया और बगवाबासा पहुंच गई। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी मार्ग के बावजूद श्रद्धालु आस्था और उत्साह के साथ यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों और पूजा-अर्चना का सिलसिला भी जारी है।

दशोली, बंड और ज्वाल्पा क्षेत्र की देवी डोलियों, छंतोलियों और चौसिंगा खाडू के साथ श्रद्धालुओं ने वेदनी कुंड पहुंचकर स्नान किया। इसके बाद नंदादेवी मंदिर में विधिविधान के साथ पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने मां नंदादेवी से क्षेत्र और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद यात्रा ने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

शनिवार को यात्रा का अगला चरण और अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। श्रद्धालु रहस्यमयी रूपकुंड क्षेत्र और कठिन ज्यूरागली मार्ग को पार करते हुए यात्रा के 16वें पड़ाव शीला समुद्र पहुंचेंगे। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और कठिन

गांव-गांव गूंजा नंदादेवी का जयकारा

इधर, बधाण क्षेत्र की श्री नंदादेवी राजराजेश्वरी की डोली ने भी वेदनी कुंड में पूजा-अर्चना के बाद वापसी यात्रा शुरू कर दी। पूजा संपन्न होने के बाद डोली अपने पारंपरिक मार्ग से आगे बढ़ते हुए बांकी गांव पहुंची। यहां श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने डोली का स्वागत किया। यात्रा के दौरान जगह-जगह लोगों ने देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नंदादेवी बड़ी जात यात्रा को क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों से देवी डोलियों और छंतोलियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं का यह सफर आस्था, परंपरा और सामुदायिक सहभागिता का परिचायक है। यात्रा के आगे बढ़ने के साथ मार्ग में पड़ने वाले गांवों में भी धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है।

चढ़ाई के कारण यह यात्रा का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। श्रद्धालु पूरी आस्था और अनुशासन के साथ इस कठिन मार्ग को पार करने की तैयारी में हैं।

किसानों का रेल रोको आंदोलन खत्म 24 सितंबर को सरकार से होगी वार्ता

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

किसान-मजदूर मोर्चा चैप्टर पंजाब के आह्वान पर गुरुवार को राज्य में पांच स्थानों पर शुरू किया गया रेल रोको आंदोलन करीब छह घंटे बाद शाम छह बजे समाप्त हो गया। किसानों और खेत मजदूरों ने दोपहर 12 बजे से रेलवे ट्रैक पर धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। आंदोलन अमृतसर के देवीदासपुरा, पठानकोट के चाखू लड़ी रेलवे फाटक, मोगा के डगरू, फिरोजपुर के मल्लांवाला और संगरूर के सुनाम में हुआ।

मोर्चे की प्रमुख मांगों में पांच फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों की कर्जमाफी, लैंड पूलिंग नीति वापस लेना, शंभू-खनौरी मोर्चे से जुड़े मामलों का समाधान और करीब 23 सूत्रीय मांगपत्र पर कार्रवाई शामिल है। इन मांगों पर 24 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में कृषि मंत्री के साथ होने वाली बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। बैठक के नतीजों और सरकार के रुख के आधार पर मोर्चा अपनी अगली रणनीति तय करेगा।

रेल रोको आंदोलन के बाद सरकार ने बातचीत की पहल की। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, बाबा गुरबचन सिंह चब्बा और सतनाम सिंह मनोचाहल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अमृतसर के देवीदासपुरा के पास गांव वडाला में अधिकारियों के साथ करीब तीन घंटे बैठक की। इसमें आइजी बॉर्डर रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर, उपायुक्त दलविंदर सिंह, एसएसपी कंवलजीत सिंह और एआइजी हरपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

बैठक में अधिकारियों ने कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों और खेत मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया। उपायुक्त ने कहा कि पात्र किसान परिवारों को तीन लाख और पात्र खेत मजदूर परिवारों को दो लाख रुपये की सहायता एक महीने के भीतर दी जाएगी। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और मजदूरों के परिवारों से जुड़े सरकारी नौकरी और मुआवजे के लंबित मामलों को भी एक महीने में निपटाने का आश्वासन दिया गया।

पायलट ने युवा नेताओं से मांगा चुनावी फीडबैक

बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता और युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर किया मंथन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पंजाब कांग्रेस ने संगठन की दूसरी पंक्ति को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट ने वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद के बाद अब यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों और युवा नेताओं से फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू की है। पार्टी स्तर पर इस कवायद का उद्देश्य विधानसभा क्षेत्रों की जमीनी स्थिति समझने के साथ बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाना और युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच मजबूत करना है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, पायलट दिल्ली और आगामी चंडीगढ़ दौरे के दौरान पंजाब यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा अन्य संगठनात्मक नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विधानसभा क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति, संगठन की सक्रियता, स्थानीय नेताओं का पिछले चार वर्षों में जनता के साथ संपर्क, युवाओं के बीच पकड़ और संभावित नए चेहरों को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। इसके आधार पर संगठन को आगामी चुनाव के लिए अधिक सक्रिय करने की रणनीति तैयार की जाएगी।

सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने की तैयारी : पंजाब कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करने की बात कही गई है। ऐसे में संगठन में विभिन्न स्तरों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस बार कई युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी विधानसभा की बड़ी संख्या में सीटों पर नए चेहरों को मौका देने की बात कह चुके हैं। युवा नेताओं से लिया जा रहा फीडबैक इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

जेन जी मतदाताओं पर पार्टी की नजर : पंजाब कांग्रेस अपने चुनावी घोषणापत्र में जेन जी से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देने की तैयारी कर रही है। घोषणापत्र समिति शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार सहित युवाओं से जुड़े विषयों पर सीधे सुझाव लेने की योजना पर काम कर रही है। पार्टी इसे 'पीपुल्स मैनिफेस्टो' के रूप में तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

अमृतसर और तरनतारन में घोषणापत्र को लेकर टीम की ओर से फीडबैक लिया जा चुका है। इसके अलावा पार्टी संगठन की डिजिटल सक्रियता पर भी ध्यान दे रही है। राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान को पंजाब में आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश नेताओं की इंटरनेट मीडिया गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई है।

यूथ कांग्रेस की ओर से जून में पंजाब-री-रूट अभियान भी शुरू किया गया था। इसके माध्यम से युवाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी अपेक्षाओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पायलट की युवा नेताओं के साथ प्रस्तावित बैठकों को संगठन और युवा मतदाताओं के बीच संवाद बढ़ाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। 15 सितंबर को पायलट के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत विभिन्न खेमों के नेता एक मंच पर दिखाई दिए थे।

न्यूज ब्रीफ

62 वर्षीय शमशेर संधू ने 14,500 फीट ऊंचा हमटा किया पास

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में नई ऊर्जा और रोमांच भरने की मिसाल पेश करते हुए चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त लेक्चरर शमशेर संधू ने 62 वर्ष की उम्र में हमटा पास ट्रैक पूरा किया। छह सदस्यीय टीम के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जाबरी से चत्रु तक का करीब चुनौतीपूर्ण सफर तय किया। टीम में अधिकतर सदस्य 20 से 30 वर्ष की उम्र के थे। 13 सितंबर को शुरू हुए ट्रैक के दौरान संधू ने तेज बारिश और ठंड के बीच करीब 11 हजार फीट ऊंचाई पर चिका में रात बिताई। अगले दिन बाली का घेरा पहुंचने के बाद करीब आठ किलो वजन पीठ पर लेकर कठिन चढ़ाई की और 14,500 फीट ऊंचे हमटा पास को पार किया। कम ऑक्सीजन और खड़ी ढलानों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। संधू ने बताया कि उन्हें इस रोमांचक यात्रा के लिए पत्नी ने प्रेरित किया। सेवानिवृत्ति के बाद अकादमी शुरू करने के बजाय उन्होंने पहाड़ों को चुना। उनका कहना है कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है।

ओडिशा की संस्कृति संग विज्ञान और कृषि नवाचारों से रूबरू हुए पत्रकार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पीआईबी चंडीगढ़ ने पीआईबी भुवनेश्वर के सहयोग से देशभर के पत्रकारों के लिए अंतरराज्यीय पत्रकार दौरे का आयोजन किया। 13 सितंबर से शुरू हुए दौरे में पत्रकारों ने ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक शोध और कृषि नवाचारों को करीब से जाना। दौरे के दौरान सिद्धेश्वर, मुक्तेश्वर, कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर का भ्रमण कराया गया। पत्रकारों को इन स्थलों की स्थापत्य कला, इतिहास और धार्मिक महत्व की जानकारी दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के उपचार और दवा विकास संबंधी शोध से परिचित कराया गया। वहीं सीटीटीसी में आधुनिक तकनीक, डिजाइन, विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्यों की जानकारी मिली। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान में महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों से भी अवगत कराया गया।

मोहाली में रंगदारी-फायरिंग के मामले में स्पेशल डीजीपी का भतीजा गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली पुलिस ने कारोबारियों से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर मॉड्यूल से जुड़े चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों में चंडीगढ़ निवासी आकाशदीप सिंह भी शामिल है, जो पंजाब के स्पेशल डीजीपी रैंक के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी की भाभी का बेटा बताया गया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से पांच पिस्तौल और 12 कारतूस बरामद किए हैं। जांच के अनुसार, आरोपित मोहाली के कारोबारियों से पांच-पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहे थे और दबाव बनाने के लिए उनके घरों पर फायरिंग करते थे। जसमनदीप सिंह पर वारदात से पहले रेकी करने और दुशंत शर्मा पर हथियार संभालने की जिम्मेदारी होने का आरोप है।

बिट्टू के काफिले पर पथराव, अंडे फेंकने से हंगामा

भारतेन्दु संवाददाता, बटाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर शुक्रवार सुबह बटाला के नजदीक घसीटपुर में अंडे और पत्थर फेंकने की घटना सामने आई। घटना के समय बिट्टू अमृतसर के श्री दरबार साहिब से माथा टेककर पठानकोट जा रहे थे। हमले में उन्हें चोट नहीं आई और सुरक्षा टीम ने उन्हें एक घर में सुरक्षित पहुंचाया। बिट्टू ने आरोप लगाया कि हमला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने बताया कि दो संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। हालांकि, आरोपों और संदिग्धों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद होगी। बिट्टू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से फोन पर बात करने की जानकारी दी।

पीयू सीनेट चुनाव में डॉ. अमरेंद्र मान के समर्थन में उतरे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी की 15 सीटों के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। 20 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों ने डीएवी कॉलेज सेक्टर-10 के प्रोफेसर डॉ. अमरेंद्र मान के समर्थन में डिजिटल संदेश जारी कर मतदाताओं से उन्हें वोट देने की अपील की है।

शूटर मनु भाकर, अर्जुन अवॉर्डी अंजुम मोदगिल, जिम्नास्ट पलक गुलिया और समीरा खान तथा फुटबॉलर देवांश देवास ने डॉ. मान के समर्थन में अपने संदेश साझा किए हैं। ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी से कुल 51 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चंडीगढ़ से डॉ. अमरेंद्र मान के अलावा सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. जगवंत सिंह, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल बीपी यादव, शिक्षक प्रवीण कौर मान सहित कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

डॉ. अमरेंद्र मान डीएवी कॉलेज सेक्टर-10 में करीब 20 वर्षों से प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वह डीएवी प्रबंधन की ओर से चुनाव मैदान में हैं। उनका कहना है कि सीनेट में चुने जाने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

विद्यार्थियों और शिक्षकों के मुद्दों पर जोर : डॉ. मान के अनुसार, विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, आधुनिक खेल सुविधाएं और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की जरूरत है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर और संबद्ध कॉलेजों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच पर उठाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। शिक्षकों के लिए अकादमिक विकास के अवसर और बेहतर कार्य परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं।

पंजाब रोडवेज कर्मियों ने 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया एलान

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर

शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता के दौरान पंजाब 25/11 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े चार साल से कर्मचारियों को नियमित करने और ठेका प्रथा समाप्त करने के नाम पर लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनके अनुसार, इस अवधि में करीब 60 से 65 बैठकें हो चुकी हैं।

यूनियन नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने ठेका कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें पूर्ण वेतन संबंधी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद परिवहन विभाग में अभी तक किसी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया। कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों के माध्यम से भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाने के बजाय किलोमीटर योजना को बढ़ावा दे रही है। यूनियन के मुताबिक, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में करीब 800 बसें कंडम हो चुकी हैं, जबकि नई बसों की खरीद पर्याप्त स्तर पर नहीं हुई है।

यूनियन नेताओं का कहना है कि बसों की कमी से सरकारी परिवहन के कई रूट प्रभावित हो रहे हैं और निजी बस संचालकों को इसका लाभ मिल रहा है।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और जेल में बंद कर्मचारियों को रिहा करने की मांग की। यूनियन ने स्पष्ट किया कि 22 सितंबर से बसों का चक्का जाम रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। नेताओं ने कहा कि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो सरकार की राजनीतिक रैलियों का बहिष्कार करने के साथ व्यापक विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।

18 से 30 सितंबर तक चलेगा अभियान, जालंधर में होगा चारों यात्राओं का समापन

पंजाब में नशामुक्ति अभियान के लिए भाजपा निकालेगी चार यात्राएं, 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगे कार्यकर्ता

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट

पंजाब में नशे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुक्रवार से शुरू होगी। 18 से 30 सितंबर तक चलने वाली इस अभियान यात्रा के तहत प्रदेश के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना है। चार अलग-अलग यात्राएं करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। पहली यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पठानकोट के माधोपुर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता स्थल से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

यात्रा के शुभारंभ को लेकर पठानकोट में व्यापक तैयारियां की गई हैं। भाजपा के अनुसार, कार्यक्रम में करीब 10 हजार लोगों के जुटने की संभावना है। रैली से पहले नितिन नवीन पंडाल के पीछे बनाए गए ग्रीन रूम में नशे से प्रभावित 50 परिवारों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के नेतृत्व के लिए 15 रथ तैयार किए गए हैं। माधोपुर में मुखर्जी स्मारक के पास बनाए गए विशाल पंडाल में करीब 5500 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है।

भाजपा पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की है। नितिन नवीन सुबह पठानकोट पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से माधोपुर जाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यात्रा को रवाना करेंगे।

माधोपुर से शुरू होने वाली पहली यात्रा थरियाल चौक और पंगोली चौक से होते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद पूर्व विधायक दिनेश सिंह बब्बू के निवास पर चाय के लिए रुकने का कार्यक्रम है। शाम को यात्रा खानपुर चौक, डाकखाना चौक, पटेल चौक और एशिया पैलेस होते हुए शहीद भगत सिंह चौक पहुंचेगी, जहां जनसभा होगी। यात्रा का पहला रात्रि विश्राम पठानकोट में होगा।

19 सितंबर को यात्रा भोआ विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी और सरना, कोटली, भोआ, सुंदरचक्क तथा सिहोड़ा होते हुए तारागढ़ पहुंचेगी। यहां जनसभा का आयोजन किया जाएगा।

पठानकोट से शुरू होने वाली पहली यात्रा जालंधर में समाप्त होगी। इसके मार्ग में सुजानपुर, पठानकोट, भोआ, दीनानगर, गुरदासपुर, कादियां, श्री हरगोबिंदपुर, बटाला, फतेहगढ़ चूड़ियां, डेरा बाबा नानक, अजनाला, राजा सांसी, अटारी और अमृतसर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा मजीठा, जंडियाला, बाबा बकाला, तरनतारन, खडूर साहिब, खेमकरण, पट्टी, फिरोजपुर, गुरुहरसहाय, जीरा, सुल्तानपुर लोधी, भोलाथ, कपूरथला, नकोदर, शाहकोट और जालंधर कैंट से होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी।

वड़िंग ने पंजाब में ड्रग्स तस्करी पर केंद्र से मांगा जवाब , बीएसएफ पर उठाए सवाल

वड़िंग बोले- नशे के खिलाफ भाजपा और आप के अभियान केवल राजनीतिक दिखावा हैं

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब में ड्रग्स तस्करी को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की सीमाओं के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी केंद्र की भी है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।

वड़िंग ने पंजाब में भाजपा की प्रस्तावित नशा मुक्ति यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार नशे की समस्या पर रोक लगाने में विफल रही है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। वड़िंग ने सवाल उठाया कि यदि सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है तो उसे रोकने में सीमा सुरक्षा बल कितनी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए पाकिस्तान के रास्ते आने वाली खेपों का भी मुद्दा सामने आता रहा है। वड़िंग ने भाजपा से पंजाब की जनता को इस संबंध में जवाब देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि देश के अन्य हिस्सों में, गुजरात के बंदरगाहों के जरिए तस्करी के मामले भी सामने आए हैं।

वड़िंग ने आरोप लगाया कि नशे के मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के अभियान राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित हैं। उन्होंने दोनों दलों पर एक-दूसरे के साथ 'फ्रेंडली मैच' खेलने का आरोप लगाया। उनका यह बयान भाजपा की 18 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 'नशा मुक्त पंजाब यात्राओं' से पहले आया है।

हालांकि, नशे की तस्करी के खिलाफ पंजाब पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की ओर से हाल में कार्रवाई भी की गई है।

डेपुटेशन कर्मचारियों के वेतन भुगतान की गृह मंत्रालय करेगा जांच

पंजाब-हरियाणा से आए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन प्रक्रिया और स्थानीय भर्ती को लेकर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब और हरियाणा से डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारियों, शिक्षकों और प्रिंसिपलों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया अब जांच के घेरे में आ गई है। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद को शिकायत भेजकर डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की प्रक्रिया की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारियों से जुड़े मामले में ऑडिट के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

यह मामला ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स (जेएसी) की ओर से भारत सरकार और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष की गई शिकायत के बाद सामने आया है। शिक्षक यूनियन ने डेपुटेशन व्यवस्था के साथ-साथ वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। शिकायत में यह जांच कराने की मांग की गई है कि डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारियों को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से किस नियम और स्वीकृत प्रक्रिया के तहत वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

भर्ती और पदोन्नति प्रभावित होने का आरोप : शिक्षक यूनियन का आरोप है कि लंबे समय तक पंजाब और हरियाणा से कर्मचारियों को डेपुटेशन पर चंडीगढ़ में बनाए रखने से स्थानीय स्तर पर नियमित भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यूनियन का कहना है कि चंडीगढ़ में उपलब्ध पदों पर स्थानीय कर्मचारियों को अवसर मिलने के बजाय डेपुटेशन व्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

शिकायतकर्ता शिक्षक यूनियन के सचिव शिव मूर्ति ने आरोप लगाया कि डेपुटेशन पर कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत अनुबंधित तथा अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जाता है। उनके अनुसार, अतिथि और अनुबंधित कर्मचारियों के आर्थिक लाभ रोकने, उन पर कार्रवाई करने और नौकरी से हटाने तक की शिकायतें सामने आती रही हैं।

शिव मूर्ति ने कहा कि अप्रैल 2022 से केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बावजूद डेपुटेशन पर कर्मचारियों को बुलाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं, चंडीगढ़ में नियमित भर्ती के लिए आवश्यक नियमों और डेपुटेशन व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।

60:40 अनुपात को लेकर भी सवाल : यूनियन ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का हवाला देते हुए कहा कि उस समय चंडीगढ़ के तत्कालीन पदों को पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों के लिए 60:40 के अनुपात में बांटा गया था। इसके बाद वर्ष 1975 से 1987 के बीच केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ की बदलती प्रशासनिक संरचना के अनुसार भर्ती और पदोन्नति से संबंधित नियम बनाए। यूनियन का दावा है कि इन नियमों में 60:40 के डेपुटेशन कोटे का उल्लेख नहीं था।

यूनियन के अनुसार, बाद में विभिन्न विभागों में 20 से 60 प्रतिशत तक के पदों के लिए कोटे तय किए गए और उन्हें पंजाब व हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात में बांटा गया। इसी व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं।

विशेष भर्ती समिति की भूमिका भी जांच के दायरे में : वर्ष 1987 से 1992 के बीच पंजाब के राज्यपाल, जो उस समय चंडीगढ़ के प्रशासक का कार्यभार भी संभालते थे, की ओर से बी और सी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में विशेष भर्ती समिति गठित की गई थी। यूनियन का आरोप है कि समिति ने केंद्र से स्वीकृत पदों पर पहले 20 से 40 प्रतिशत तक कोटे तय किए और बाद में उन्हें पंजाब तथा हरियाणा के लिए 60:40 के अनुपात में बांटा।

यूनियन का कहना है कि इस व्यवस्था से चंडीगढ़ के स्थानीय कर्मचारियों की पदोन्नति और नियमित भर्ती प्रभावित हुई। अब गृह मंत्रालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाना है कि डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया किन नियमों और स्वीकृत प्रावधानों के तहत संचालित हो रही है।

पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से 5.10 लाख श्रद्धालु हुए लाभान्वित

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 50 वर्ष से अधिक आयु के 5,10,807 श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जा चुके हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने वीरवार को पंजाब भवन में प्रेस वार्ता के दौरान योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें निशुल्क और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा उपलब्ध करा रही है।

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नौ नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत पंजाब के 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जा रही है। योजना में श्री दरबार साहिब, दुर्गियाना मंदिर और श्री रामतीर्थ सहित कई प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं।

सौंद ने बताया कि 12 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीर्थ यात्रा के लिए तीन नए धार्मिक यात्रा मार्ग भी शुरू किए। इनमें खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, मथुरा-वृंदावन, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं। इन नए मार्गों के जुड़ने से वरिष्ठ नागरिकों को देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर भी मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि अब तक 12,450 से अधिक बसों के माध्यम से विभिन्न संगठनों से जुड़े श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों तक पहुंचाया जा चुका है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। यात्रियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था के साथ चिकित्सा दल तथा मार्गदर्शक भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को काशी यानी वाराणसी ले जाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष रेलगाड़ियां चलाने का आग्रह किया गया है। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के माध्यम से तीर्थ यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के विकल्प पर भी पंजाब सरकार विचार करेगी।

न्यूज ब्रीफ

नकली निवेश मंच से करोड़ों की ठगी, कठुआ के पांच जालसाज फरार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर कठुआ के पांच युवकों द्वारा कई राज्यों के लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। गुजरात पुलिस की जांच में गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद कठुआ में भी छापेमारी की जा रही है। आरोपितों ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए नकली वेबसाइट और ऑनलाइन मंच तैयार किए थे। इन पर निवेश की रकम और काल्पनिक मुनाफा लाइव दिखाई देता था, जिससे लोग बड़ी रकम लगाने के लिए आकर्षित होते थे। जांच के अनुसार गिरोह में करीब पांच अन्य युवकों की भी शामिल किया गया था। उन्हें प्रभावित करने के लिए 30 से 35 लाख रुपये कीमत की पांच लग्जरी कारें उपहार में देने की बात सामने आई है। पांचों मुख्य आरोपितों की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है और फिलहाल सभी भूमिगत हैं। गिरोह ने गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लोगों को निशाना बनाया। इसी बीच कठुआ में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जन्मदिन की पार्टी में खूनी झड़प, युवक की मौत

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू के रूप नगर में जन्मदिन की पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना 17 सितंबर की देर रात की है। लोअर रूप नगर के पास नीरज उर्फ अंशु जन्मदिन मना रहा था। पार्टी में उसके दोस्त जॉन सोत्रा, गौरव सिंह, सुगंध भट्टी और पवन नायर उर्फ समीर मौजूद थे। नीरज का भाई रिशु भी वहां था। केक काटने के दौरान पवन नायर ने नीरज के चेहरे पर केक लगा दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोस्तों ने विवाद शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन मामला बढ़ गया। आरोप है कि नीरज ने अपने पास रखी खोखरी से पवन नायर की गर्दन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पवन को उसके दोस्त उपचार के लिए जीएमसी जम्मू ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आय से अधिक संपत्ति और खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पर एसीबी की कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अलग-अलग मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं। इनमें आय से अधिक संपत्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं के मामले शामिल हैं। एसीबी जम्मू ने मोटर वाहन विभाग के कर्मचारी अश्विनी कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। सत्यापन में उसके और परिवार के सदस्यों के नाम पर दुकानें, प्लाट, फ्लैट और महंगे वाहन समेत कई संपत्तियां मिलने का दावा किया गया। अदालत से वारंट लेने के बाद उसके मुट्ठी स्थित आवास की तलाशी ली गई। वहीं, एसीबी बारामुला ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सिंहपोरा-पट्टन शीबा इनायत के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। जांच में बैंक जमा, सावधि जमा, बीमा पालिसियां, आभूषण और पांच मंजिला व्यावसायिक परिसर समेत कई संपत्तियों का पता चलने की बात कही गई है।

वुलर झील की गाद में छिपे हैं कश्मीर के भूगर्भीय अतीत के रहस्य

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर की प्रसिद्ध वुलर झील केवल जल का बड़ा भंडार नहीं, बल्कि क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास को संजोए प्राकृतिक अभिलेख के रूप में भी सामने आई है। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला है कि झील की तलछट मुख्य रूप से तीन प्रमुख भूगर्भीय स्रोतों से आती है। इनमें उच्च हिमालयी क्रिस्टलीय चट्टानें, पांजाल ट्रैप की ज्वालामुखीय चट्टानें और करेवा समूह शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने तलछट के नमूनों का भू-रासायनिक विश्लेषण करने के साथ आधुनिक मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। अध्ययन में 49 भू-रासायनिक संकेतकों की जांच की गई, जिनमें प्रमुख आक्साइड, सूक्ष्म तत्व और दुर्लभ मृदा तत्व शामिल हैं। खनिज जांच में क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, क्लोराइट और फेल्डस्पार प्रमुख पाए गए।

बडगाम में घर के भीतर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

भारतेंदु संवाददाता, बडगाम। बडगाम के कादी पोरा इलाके में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात 21 वर्षीय युवक अपने घर में मृत पाया गया। एक अधिकारी के अनुसार, युवक घर में बेहोशी की हालत में मिला था। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक की पहचान कादी पोरा निवासी शफात हुसैन (21) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अंतिम संस्कार से संबंधित आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

कश्मीरी छात्रा जर्का नसीर को दक्षिण कोरिया में पीएचडी करने का अवसर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर (स्कास्ट-के) की छात्रा जर्का नसीर खान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर जर्का का चयन दक्षिण कोरिया की जियोनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी में पूर्ण वित्त पोषित पीएचडी कार्यक्रम के लिए हुआ है। जर्का ने जुलाई 2026 में स्कास्ट-के से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की थी। सितंबर में उन्होंने जियोनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी के पशु चिकित्सा विभाग में दाखिला लिया। यहां वह संक्रामक रोग प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य करेंगी। उनका शोध प्रोफेसर ओम जे-कू के मार्गदर्शन में होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जर्का की सफलता को विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और शोध के बढ़ते अवसरों का प्रमाण बताया।

बुशरा बानो के तबादले पर महबूबा ने भाजपा को घेरा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पश्चिम बंगाल की आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो के तबादले को लेकर जम्मू-कश्मीर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर मुस्लिम पहचान और धार्मिक अभिव्यक्तियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बानो के 'अस्सलामु अलैकुम', 'इंशाअल्लाह' और 'जजाकल्लाह' जैसे शब्दों के इस्तेमाल के बाद उनका तबादला किया गया। बानो 2021 बैच की अधिकारी हैं और खड़गपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थीं। 14 सितंबर को उन्हें राज्य सशस्त्र पुलिस की चौथी बटालियन का डिप्टी कमांडेंट बनाया गया। हालांकि, सरकार के तबादला आदेश में वीडियो विवाद को कारण नहीं बताया गया और इसे प्रशासनिक बदलाव तथा जनहित में लिया गया फैसला बताया गया है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र में मनोनीत सीटों पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने

पांच सदस्यों के मनोनयन और मतदान अधिकार को लेकर संवैधानिक सवालों पर बढ़ी हलचल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार के गठन को करीब दो वर्ष होने के बावजूद सदन की पांच मनोनीत सीटें अभी तक रिक्त हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी लंबे समय से खाली है। ऐसे में आगामी सत्र के दौरान विधायी कामकाज के साथ मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति, उनके मतदान अधिकार और विधानसभा के बदलते संख्याबल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज होने के आसार हैं।

मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित विधायकों के समान मतदान अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए पांच सदस्यों का मनोनयन केवल रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे विधानसभा के प्रभावी संख्याबल और बहुमत के आंकड़े पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि मनोनयन का अधिकार जम्मू-कश्मीर की मौजूदा राजनीति में महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा बन गया है।

95 तक पहुंच सकता है प्रभावी संख्याबल : जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत विधानसभा में कुछ वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में दो महिलाओं को मनोनीत किया जा सकता है। इसके अलावा विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं और गुलाम जम्मू-कश्मीर से आए लोगों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है।

2024 में संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद इन वर्गों के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान प्रभावी हुआ। गुलाम जम्मू-कश्मीर के लिए आरक्षित 24 सीटों को अलग रखने पर विधानसभा का प्रभावी संख्याबल 95 तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा मौजूदा 46 से बढ़कर 48 हो जाएगा। इसलिए पांच मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

41 विधायकों के साथ नेकां सबसे बड़ा दल : मौजूदा 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कान्फ्रेंस के 41 विधायक हैं। भाजपा के नौ, कांग्रेस के छह और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चार विधायक हैं। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कान्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और माकपा के एक-एक विधायक हैं, जबकि सात निर्दलीय सदस्य भी सदन में हैं। नेशनल कान्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस और माकपा शामिल हैं। सरकार पांच निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा करती है। ऐसे में मनोनीत सदस्यों के आने के बाद सदन का संख्याबल बदलने की संभावना इस मुद्दे को और महत्वपूर्ण बनाती है।

पुनर्गठन अधिनियम के तहत मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास है और इसके लिए निर्वाचित सरकार से परामर्श अनिवार्य नहीं है। नेशनल कान्फ्रेंस चाहती है कि मनोनयन की प्रक्रिया में निर्वाचित सरकार की भूमिका सुनिश्चित हो।

संवैधानिक सुरक्षा की मांग भी बरकरार

पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लद्दाख में बढ़ी हलचल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों के बीच बातचीत में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के बाद लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने आंदोलन आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर 23 और 24 सितंबर को पदयात्रा की जाएगी। खराब मौसम के कारण पहले प्रस्तावित छह दिवसीय यात्रा की अवधि घटाई गई है।

9 सितंबर को गृह मंत्रालय की उपसमिति के साथ हुई बैठक में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर लद्दाख के प्रतिनिधियों ने निराशा जताई। क्षेत्र के संगठनों की प्रमुख मांगों में पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व शामिल हैं। उनका कहना है कि इससे भूमि, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय प्रशासन से जुड़े मामलों में क्षेत्र के लोगों को अधिक संवैधानिक सुरक्षा मिल सकेगी।

◆पूर्ण राज्य की मांग पर सोनम वांगचुक करेंगे दो दिवसीय पदयात्रा

पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर किसी क्षेत्र में निर्वाचित विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वाली राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार को संविधान के तहत राज्य सूची और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विषयों पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलती हैं। वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और वहां विधानसभा नहीं है।

लद्दाख के संगठन पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा की मांग भी करते रहे हैं। यह व्यवस्था पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और सांस्कृतिक हितों के संरक्षण से जुड़ी है।

नशे और तनाव से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया जोर

वैश्विक संघर्षों के बीच जामा मस्जिद में शांति की दुआ

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर में शुक्रवार को नमाज के बाद जम्मू-कश्मीर समेत दुनिया के विभिन्न संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अमन और शांति के लिए दुआ की गई। बड़ी संख्या में नमाजियों ने ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और यूक्रेन समेत प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष लोगों की पीड़ा समाप्त होने तथा राहत और इंसाफ की प्रार्थना की।

◆ईरान दौरे का जिक्र, राष्ट्रपति से मुलाकात की दी जानकारी

शुक्रवार की नमाज के दौरान मीरवाइज-ए-कश्मीर डा. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वैश्विक संघर्षों के बीच शांति की अपील की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सामाजिक सुधारों के लिए लोगों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। मीरवाइज ने कहा कि समाज की गंभीर समस्याओं पर केवल सम्मेलन आयोजित करने और प्रस्ताव पारित करने से बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए आम लोगों को स्वयं सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा।

उन्होंने हाल में मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा जम्मू-कश्मीर के उलेमा सम्मेलन का उल्लेख करते हुए नशे की बढ़ती लत, युवाओं में आत्महत्या और भावनात्मक तनाव, इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग, कमजोर होते पारिवारिक रिश्तों, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक सौहार्द जैसे मुद्दों को प्रमुख चिंता बताया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान परिवार, मस्जिद, मोहल्ले और समुदाय के स्तर पर ठोस पहल से किया जाना चाहिए।

93 लाख की जमीन धोखाधड़ी में एक साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

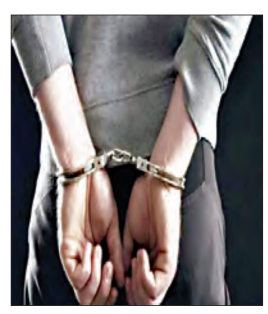

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर ने जमीन और संपत्ति से जुड़ी कथित 93 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलाम मोही-उद-दीन डार पुत्र अब्दुल खालिक डार निवासी जवालापोरा, सैमसन बडगाम के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी श्रीनगर की सब-जज अदालत से जारी आदेश और वारंट के आधार पर की गई। क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी करीब एक साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। उसके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा-स्पेशल क्राइम विंग कश्मीर थाने में कई मामले दर्ज हैं। मामला एफआइआर संख्या 17/2026 से संबंधित है। जांच के मुताबिक, डार कथित तौर पर जमीन का ब्रोकर है और उसने सह-आरोपी सोम नाथ कौल के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से 93 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। आरोप है कि दोनों ने पुलवामा के द्रुसु में पांच कनाल प्रवासी जमीन और बिजबेहाड़ा में 300 खड़े पेड़ों को बेचने का झांसा दिया।

विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में खिलाई फूलों की नई रंगीन तस्वीरें

फूलों की खेती से किसानों को मिलेगा नया अवसर

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लेह-लद्दाख जाने वाले पर्यटकों को अब बर्फीले पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के साथ फूलों की रंग-बिरंगी वादियां भी देखने को मिलेंगी। लद्दाख के चोगलमसर और स्टाकना में करीब 40 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए गए दो फूलों के खेतों का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वीरवार को लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम में इन फूलों के खेतों को जनता को समर्पित किया गया।

करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर विकसित किए गए इन दोनों फूलों के खेतों में 25 लाख से अधिक उच्च मूल्य वाले फूल लगाए गए हैं। इनमें करीब 24 लाख लिलियम और एक लाख ग्लैडियोलस के फूल शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों क्षेत्रों को लगभग दो महीने के रिकार्ड समय में विकसित किया गया है। फूलों के खिलने से क्षेत्र का प्राकृतिक आकर्षण बढ़ा है और इससे स्थानीय लोगों के साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करने की उम्मीद है।

परियोजना का प्रमुख उद्देश्य लद्दाख में पारंपरिक कृषि के साथ कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से किसानों को फूलों की खेती से अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर मिलेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि ये फूलों के खेत लद्दाख के प्रगतिशील किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करेंगे।

यहां आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के समन्वय से किसानों और युवाओं को फूलों की खेती की जानकारी दी जाएगी। उन्हें नई तकनीकों के इस्तेमाल, उत्पादन और फूलों से जुड़े उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

नव नियुक्त अधिकारियों को मिली जनसेवा की जिम्मेदारी

वर्दी अधिकार नहीं, नागरिक सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी : मनोज सिन्हा

◆नए अधिकारियों से बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच सजग रहने का आह्वान

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राजपत्रित सेवाओं में नव नियुक्त अधिकारियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्दी की गरिमा बनाए रखने और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। लोक भवन, श्रीनगर में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति आदेश सौंपे और उनके माता-पिता व परिवारों को भी बधाई दी।

उपराज्यपाल ने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, साहस, विनम्रता और मानवीय संवेदनशीलता को अपने कार्य का आधार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति केवल करियर की शुरुआत नहीं, बल्कि ऐसे मिशन में प्रवेश है, जिसमें अनुशासन, समर्पण और त्याग की जरूरत होती है।

सिन्हा ने कहा कि वर्दी का सम्मान उसे पहनने वाले अधिकारी के आचरण और सत्यनिष्ठा से कायम होता है। अधिकारियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल न्याय के लिए करना चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा तथा गरिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने पुलिस और जनता के बीच विश्वास को कानून के शासन की महत्वपूर्ण बुनियाद बताया।

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य लगातार बदल रहा है। पुलिस को पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ साइबर अपराध, आभासी क्षेत्र, कट्टरपंथ, आतंकवाद की फंडिंग, क्रिप्टोकरेंसी और धनशोधन जैसी नई चुनौतियों से भी निपटना होगा। उन्होंने अधिकारियों से आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को तैयार करने और नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।

कश्मीर में नशे के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न इलाकों में कार्रवाई करते हुए नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अनंतनाग, सोपोर, शोपियां, पुलवामा और कुलगाम में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चरस, गांजा और कैनाबिस जैसे पदार्थ बरामद किए। अनंतनाग के नईबस्ती खानाबल इलाके में नाका जांच के दौरान आदिल अहमद शाह और आदिल अहमद वानी को पकड़ा गया। इनके कब्जे से 10.31 ग्राम चरस बरामद हुई। सोपोर के मालगोनीपोरा में जकीर राशिद लोन को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। शोपियां के आडूरा रामपथरी में पुलिस ने अब अहद मोची को पकड़ा। उसके पास से 2.472 किलोग्राम कैनाबिस जैसा पदार्थ बरामद हुआ। पुलवामा के पुराने बस अड्डे पर अबरार अहमद याटू, ओवैस अहमद बाबा और मुदसिर अहमद डार को गिरफ्तार कर 286 ग्राम चरस पाउडर तथा 101.5 ग्राम चरस जैसा पदार्थ जब्त किया गया।

जम्मू-कश्मीर के चार तैराकों ने एशियन मास्टर्स में बनाई जगह

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के चार तैराकों ने मास्टर्स एशियन तैराकी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्वालीफाई किया है। इनमें तीन सगी बहनें बबीता रानी, बिंदू पठानिया और किरण जम्वाल शामिल हैं। पुरुष वर्ग में भारत भूषण गुप्ता ने भी प्रतियोगिता के लिए स्थान हासिल किया है।

◆तीन सगी बहनों समेत चार तैराक बेंगलुरु में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व

चारों तैराकों ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में आयोजित 22वीं नेशनल मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन प्रतियोगिता के लिए पात्रता हासिल की। आगामी मास्टर्स एशियन तैराकी प्रतियोगिता कर्नाटक के बेंगलुरु में 4 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इसमें चारों तैराक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

जम्मू-कश्मीर स्विमिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रमनदीप सिंह सूदन और महासचिव भारत कुमार शर्मा ने सभी चयनित तैराकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर एशियन प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करना प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

खास बात यह रही कि बबीता रानी, बिंदू पठानिया और किरण जम्वाल तीनों सगी बहनें हैं। तीनों ने एक साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उपलब्धि हासिल की है। तैराकों ने 35 से 80 वर्ष तक के विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिस्पर्धा की।

व्यवस्था अस्पतालों के पास बनी सुविधा से मरीजों और तीमारदारों को ठहरने में मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री उमर ने अमृतसर में जम्मू-कश्मीर हाउस का किया उद्घाटन

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर से इलाज, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए अमृतसर आने वाले लोगों को अब किफायती और सुविधाजनक ठहरने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को अमृतसर के 2-कोर्ट रोड स्थित नवीनीकृत जम्मू-कश्मीर हाउस का उद्घाटन किया। करीब 2.30 करोड़ रुपये की लागत से इस भवन को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया गया है। इसमें चार अतिथि कमरे, सामूहिक बैठक कक्ष, भोजन कक्ष और रसोई समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से नवीनीकृत किए गए इस भवन का मुख्य उद्देश्य पंजाब के अमृतसर आने वाले जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को बेहतर और सस्ता आवास उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अमृतसर के अस्पतालों का रुख करने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए यह सुविधा उपयोगी होगी। इसके अलावा छात्र, श्रद्धालु और अन्य आगंतुक भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

2.30 करोड़ की लागत से हुआ नवीनीकरण : जेएंडके हाउस के नवीनीकरण और उन्नयन का कार्य अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया था। करीब 2.30 करोड़ रुपये की लागत से हुए कार्य में भवन के सिविल और विद्युत कार्य, आंतरिक साज-सज्जा, अतिथि सुविधाओं, बाहरी विकास तथा अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया है। नवीनीकृत भवन में चार अतिथि कमरे बनाए गए हैं। प्रत्येक कमरे के साथ ड्रेसिंग क्षेत्र और स्नानघर की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सामूहिक बैठक कक्ष, भोजन कक्ष और रसोई भी तैयार की गई है।

सुविधाओं का निरीक्षण किया : उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भवन की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भवन में साफ-सफाई, आतिथ्य और रखरखाव के उच्च मानक बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से बाहर इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिवारों को कई बार ठहरने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जेएंडके हाउस उनके लिए सुविधाजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

नारानाग से हरमुख-गंगबल यात्रा रवाना, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

कठिन पहाड़ी मार्ग से होकर श्रद्धालु पवित्र गंगबल झील के करेंगे दर्शन

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कंगन के नारानाग से वार्षिक हरमुख-गंगबल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही गंदेरबल जिले के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित पवित्र गंगबल झील की पारंपरिक तीर्थयात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। यात्रा में जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हरमुख-गंगबल की पवित्र यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा से इसके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। उन्होंने कामना की कि यह तीर्थयात्रा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली का संदेश लेकर आए। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि जम्मू-कश्मीर शांति और विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे।

हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस वार्षिक यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित भी नारानाग पहुंचे। कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए इस यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। श्रद्धालु नारानाग के पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए हरमुख पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई पर स्थित गंगबल झील तक पहुंचते हैं।

यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में सांसद मियां अल्ताफ अहमद, कंगन के विधायक मियां मेहर अली तथा वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों की जानकारी भी दी।

समानता की राह में जातिवाद की दीवार, भेदभाव खत्म करने की चुनौती

सुखदेव सिंह
नूरपुर

जातिवाद आज भी भारतीय समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। संविधान समानता का अधिकार देता है और देश विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर भेदभाव की घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या वास्तव में समाज जातिगत पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त हो पाया है। आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग समय-समय पर उठती रही है, लेकिन जातिगत भेदभाव की मौजूदगी में इस मुद्दे पर व्यापक सामाजिक और राजनीतिक सहमति बनाना आसान नहीं है। जब सभी मनुष्यों को समान माना जाता है तो ऊंच-नीच, छुआछूत और जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

हाल के वर्षों में सामने आई कुछ घटनाओं ने इस बहस को फिर चर्चा में ला दिया है। दलित समाज से जुड़े लोगों के साथ कथित भेदभाव की घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सामाजिक बराबरी के लिए किए गए प्रयास अभी अधूरे हैं। मंदिर प्रवेश के बाद कथित शुद्धिकरण जैसी घटनाएं हों या किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बाद ऐसी ही कार्रवाई के आरोप, इनसे सामाजिक समरसता पर सवाल उठते हैं। यह भी चिंता का विषय है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों और योगदान को सम्मान देने के बावजूद समाज के कुछ हिस्सों में जातिगत पूर्वाग्रह अब भी दिखाई देते हैं।

हिमाचल प्रदेश में भी पंचायत चुनावों और अन्य सामाजिक गतिविधियों के दौरान जातिगत समीकरणों की चर्चा होती रही है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था में समान व्यवहार और संवेदनशीलता का महत्व और बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक विजय रघुवंशी से जुड़ा मामला भी चर्चा में है। रघुवंशी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष रखा है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार उन्हें 20 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश होना था। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

इस मामले में रघुवंशी की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि का प्रश्न अलग है, लेकिन शिकायत में उठाए गए प्रशासनिक व्यवहार से जुड़े सवाल गंभीर हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी शारीरिक परेशानी और निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में असमर्थता के संबंध में जिलाधिकारी, शिमला को पत्र लिखा था। उनका दावा है कि इसी पत्र को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की संस्तुति का आधार बनाया गया। यदि किसी अधिकारी ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की जानकारी सक्षम अधिकारी को दी है, तो यह जांच का विषय होना चाहिए कि उसे अनुशासनहीनता मानने का आधार क्या था और संबंधित सेवा नियम इस बारे में क्या कहते हैं।

वाहन सुविधा से वंचित किए जाने का आरोप भी इस प्रकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रघुवंशी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनसे सरकारी वाहन की सुविधा वापस ले ली गई और उन्हें लगभग सात किलोमीटर पैदल चलने की स्थिति का सामना करना पड़ा। यदि ऐसा हुआ है तो यह जानना जरूरी है कि वाहन सुविधा वापस लेने का प्रशासनिक आधार क्या था और क्या समान परिस्थितियों में सभी अधिकारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया। प्रशिक्षणरत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए नए वाहन उपलब्ध होने और कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक को वाहन सुविधा न मिलने के बीच तुलना भी इसी संदर्भ में उठाई जा रही है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

मां मनसा देवी शक्तिपीठ की पौराणिक गाथा और अटूट आस्था का अद्भुत संगम

विरेंद्र शर्मा
स्वतंत्र लेखक

यूं तो उत्तर भारत में स्थित हिमाचल प्रदेश देवभूमि देश-विदेश में धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रख्यात है, लेकिन इस राज्य के साथ सटा हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। वैसे भी हिमालय क्षेत्र सदा से मानवता का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों की तपोभूमि आज भी अपनी धार्मिक धरोहरों को चार चांद लगाती हैं। उत्तरी भारत के हरियाणा राज्य के पंचकूला में अवस्थित ऐतिहासिक व प्राचीन मां मनसा देवी का पुरातन मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। यही वजह है कि प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु मां के दर्शनार्थ हेतु यहां आते रहते हैं।

किंवदंतियों के अनुसार श्री माता मनसा देवी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना अन्य शक्तिपीठों का। इन शक्तिपीठों का कैसे और कब प्रादुर्भाव हुआ इसके बारे में शिवपुराण में विस्तृत वर्णन मिलता है। धर्मग्रंथ तंत्र चूड़ामणि के अनुसार ऐसे सिद्ध देवीपीठों की संख्या 51 है, जबकि देवी भगवत पुराण में 108 सिद्धपीठों का उल्लेख मिलता है जो सती के अंगों के गिरने से प्रकट हुए। शिवपुराण के अनुसार मां पार्वती राजा दक्ष की पुत्री थी और हिमालय पर उनका राज्य था। पार्वती अपने पति शिवजी के साथ कैलाश पर्वत पर उनका वास था।

एक बार राजा दक्ष ने अश्वमेघ यज्ञ रचाया और उसमें पिता दक्ष प्रजापति द्वारा पार्वती जी के प्राणेश्वर भगवान शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया। इसे पार्वती ने अपने प्राणेश्वर का अपमान समझा और क्रोधित होकर चल रहे उस यज्ञ में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिए। इस पर शिवजी ने उनके दग्ध शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करते हुए देश-देशांतर में विचरण करने लगे। भोले शंकर का यह उग्र रूप देखकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी। शिवाजी का अपनी पत्नी के प्रति अत्याधिक मोह को देखकर भगवान विष्णुजी ने अपने सुदर्शन चक्र से लक्ष्यभेद कर सती के शरीर को खंड-खंड कर दिया। यह अंग जहां-जहां गिरे वहीं 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई।

कहा जाता है कि हरियाणा के मनीमाजरा के निकट शिवालिक पर्वतमालाओं पर देवी के मष्तिष्क का अग्र भाग गिरने से मानसा देवी आदि शक्तिपीठ अवस्थित हुआ, जो लाखों भक्तों की अगाध श्रद्धा, विश्वास व पूजा स्थल बन गया। कहा जाता है कि माता मनसा देवी मंदिर का निर्माण तत्कालीन मनीमाजरा के राजा गोपाल सिंह जी ने मां के द्वार पर उनके द्वारा मां के चरणों में मांगी गई मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण अपनी देखरेख में 1815 ईस्वी में सम्पन्न करवाया था, जोकि लगभग चार वर्षों में बनकर तैयार हुआ था तथा आगे चलकर लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का केंद्र बन गया।

एक अन्य जनश्रुति अनुसार मनसा देवी का नाम महंत मंशा नाथ के नाम पर पड़ा बताया जाता है। मुग़लकालीन बादशाह सम्राट अकबर के दौरान लगभग 450 वर्ष पूर्व बिलासपुर गांव में मां देवी भक्त श्रद्धालु महंत मंशा नाथ रहता था। उस समय यहां देवी की पूजा अर्चना करने दूर-दूर से लोग आते थे। दिल्ली सूबे की ओर से यहां मेले पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एक रुपया कर टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। इसका महंत मंशा नाथ ने डटकर विरोध किया। हुकूमत के डर से राजपूतों ने उनकी मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी। माता का अनन्य भक्त होने के नाते उसने वर्तमान मंदिर से कुछ ही दूर पहाड़ों पर अपना डेरा जमा लिया और वहीं से माता की पूजा-अर्चना करने लगे। महंत मंशा नाथजी का धुना आज भी मनसा देवी की सीढ़ियों के प्रारम्भ में बाईं ओर अविरल जलता रहता है।

एक अन्य दंतकथा के मुताबिक मनीमाजरा से सटी शिवालिक पहाड़ियों पर एक गाय प्रतिदिन विचरण करने आती थी और पहाड़ियों पर सटे पत्थरों पर अपना दूध अर्पण करती थी। स्थानीय निवासियों ने जब इस अद्भुत दृश्य को देखा तो पता चला कि वहां तीन अनूठी पवित्र शिलाएं हैं जिन्हें देखकर लोगों में अगाध श्रद्धा समा गई और उन शिलाओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाने लगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

कामगारों के कल की चिंता

केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करना कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के अनुसार, इससे करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा यानी भविष्य निधि के दायरे में आ सकेंगे। इसके साथ ही भविष्य निधि में नियोक्ताओं के अंशदान में भी वृद्धि होगी। यह फैसला केवल वेतन सीमा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उन लाखों कामगारों के भविष्य से है, जिनकी आज की कमाई परिवार की जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जाती है, लेकिन आने वाले कल के लिए सुरक्षित बचत का पर्याप्त साधन नहीं बन पाती।

महीने की पहली तारीख को वेतन मिलते ही एक आम कामगार के सामने कई जरूरतें कतार में खड़ी होती हैं। घर का किराया, राशन, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली-पानी के बिल, आने-जाने का खर्च और दूसरी घरेलू जरूरतें उसकी आय का बड़ा हिस्सा ले लेती हैं। आज की कमाई से आज का घर चलाना उसकी पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन उसके साथ एक सवाल हर महीने चलता है कि कल का क्या होगा? बीमारी आने पर क्या होगा, काम प्रभावित हुआ तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा और उम्र ढलने के बाद आर्थिक सहारा कहां से मिलेगा? सामाजिक सुरक्षा का वास्तविक अर्थ इसी अनिश्चितता को कम करना और मेहनतकश व्यक्ति को भविष्य के प्रति भरोसा देना है।

इस बदलाव की जरूरत को समझने के लिए पिछले एक दशक में हुए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को देखना होगा। अनिवार्य कवरेज की मौजूदा सीमा वर्ष 2014 में 15 हजार रुपये निर्धारित की गई थी। तब से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और जीवन-यापन की लागत में भी बदलाव आया है। विनिर्माण, लाजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक है। पुरानी सीमा के कारण इनमें से एक वर्ग अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रह जाता था। यह अंतर केवल वेतन का नहीं था, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का भी था।

कई बार एक ही कार्यस्थल पर काम करने वाले दो कर्मचारियों की आय में मामूली अंतर होने के कारण उनके सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतर पैदा हो जाता था। नई सीमा इस अंतर को कम करने और अधिक संख्या में युवा तथा मध्य आय वर्ग के कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने का अवसर देती है। इससे न केवल सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा, बल्कि कामगारों के भविष्य का संस्थागत आधार भी मजबूत हो सकता है।

हालांकि, इस व्यवस्था का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान होने से उसके हाथ में आने वाले मासिक वेतन में कुछ कमी हो सकती है। लेकिन भविष्य निधि की मूल अवधारणा वर्तमान आय के एक हिस्से को भविष्य की वित्तीय सुरक्षा में बदलने की है। कर्मचारी के अंशदान के साथ नियोक्ता का योगदान भी जुड़ता है और समय के साथ यही राशि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक संबल बन सकती है। इसके साथ पेंशन और कर्मचारी बीमा से जुड़े प्रविधान सामाजिक सुरक्षा को व्यापक आधार देते हैं। इसीलिए सामाजिक सुरक्षा को केवल बचत के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता के माध्यम के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

कामगार अपने श्रम से परिवार की आज की जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन उनकी चिंता केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होती। वे यह भी चाहते हैं कि नियमित आय सीमित होने पर उनके पास भविष्य में अपना सहारा हो। बीमारी, दुर्घटना, रोजगार में बदलाव या वृद्धावस्था जैसी परिस्थितियां किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे समय में संस्थागत सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति और उसके परिवार को कठिन परिस्थितियों से उबरने में महत्वपूर्ण सहारा दे सकती है। इस अर्थ में सामाजिक सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राज्य, नियोक्ता और श्रमिक की साझा जिम्मेदारी है।

सामाजिक सुरक्षा का विस्तार केवल अधिक लोगों को व्यवस्था में शामिल करने से पूरा नहीं होगा। यह भी जरूरी है कि कामगारों को इसका लाभ आसानी, पारदर्शिता और सम्मान के साथ मिले। पिछले वर्षों में ईपीएफओ की सेवाओं में डिजिटल माध्यमों, सार्वभौमिक खाता संख्या और आनलाइन सेवाओं का विस्तार हुआ है। इससे भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी कई प्रक्रियाएं पहले की तुलना में सरल हुई हैं। लेकिन तकनीक की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब वह कामगारों के लिए व्यवस्था को समझने और इस्तेमाल करने में भी आसान बनाए।

जैसे-जैसे अधिक कामगार औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, वैसे-वैसे ऐसी संस्थागत व्यवस्थाओं की जरूरत भी बढ़ेगी, जो वर्तमान रोजगार से आगे उनके भविष्य को सुरक्षा दें। भविष्य निधि केवल जमा की गई रकम नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का आधार है कि वर्षों की मेहनत के बाद जमा हुई राशि जरूरत के समय कामगार और उसके परिवार के साथ खड़ी होगी।

-शिवांश धाकड़

कविता

जिंदगी, जीने का नाम है

(डॉ. उर्मिल कौंडल)

बुरे ख्यालों में क्यों रहते हो हर पल,
क्यों नहीं आते तुम दिन के उजालों में।
जिंदगी ने दिए होंगे गहरे जख्म तुम्हें,
क्यों कुरेदते रहते हो उन्हें बार-बार यादों में।
दर्द को सहना और उसे दबाना सीख लो,
अगर आजमाना है जिंदगी को, तो आजमा के देख लो।
निराश मत होना कभी इस जिंदगी से,
जिंदगी को जीने का नाम है, इसे मुस्कुराकर जी लो।
खुशी में जीना ही खुदा का फरमान है,
हर सांस में छिपा एक नया अरमान है।
जो बीत गया उसे जाने दो तुम,
आने वाले कल को खुशियों से सजाने दो तुम।
हम आए हैं इस जहां में खुदा से मिलने,
तो फिर क्यों भटकते हो उसे बाहर ढूंढने।
खुदा कहीं दूर नहीं, वह दिलों में रहता है,
हर इंसान के भीतर प्रेम बनकर बहता है।
अगर खुदा से मिलना चाहते हो दिल से,
तो इबादत कर लो सच्चे मन से।
उसे मंदिर-मस्जिद की दीवारों में मत ढूंढो,
अपने भीतर झांको और वहीं उसे महसूस करो।
दर्द आए तो हिम्मत से उसका सामना करो,
गिरो अगर राह में तो फिर उठकर चला करो।
जिंदगी अनमोल है, इसे यूं न गंवाओ,
हर पल को प्रेम, उम्मीद और मुस्कान से सजाओ।

पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के आरोपों के बीच भी आंदोलनकारियों का संघर्ष रहा जारी

विशाल कल्याण
स्वतंत्र लेखक

जंतर मंतर पर लगभग एक महीने तक चले छात्रों और युवाओं के आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आंदोलन के दौरान सरकार और उसके समर्थकों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने का हरसंभव प्रयास किया। आंदोलनकारियों को देशद्रोही, विदेशी ताकतों से धन लेने वाला, टुकड़े गैंग का सदस्य, पाकिस्तान समर्थक और देश के विकास में बाधा डालने वाला बताया गया। सोशल मीडिया पर भी आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। आंदोलनकारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन उन्हें लगातार संदेह की दृष्टि से देखा गया।

जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, छात्राएं और युवा पोस्टर तथा बैनर लेकर पहुंचे। कई छात्राएं अपने छात्रावास और घरों से निकलकर बिना किसी भय के आंदोलन में शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों ने खुले आसमान के नीचे रातें बिताईं, जमीन पर सोए, पुलिस की कार्रवाई और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि वे न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। हर सुबह नई ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने वाले युवाओं ने अपने धैर्य और संकल्प का परिचय दिया।

इस आंदोलन की एक विशेष बात यह रही कि नीट परीक्षा से जुड़े अनेक विद्यार्थियों के माता-पिता भी विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचे और अपने बच्चों की मांगों के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने भी भय का वातावरण छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। इसी दौरान सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की और लंबे समय तक अनशन पर रहे। आंदोलनकारियों का कहना था कि देशभर के लोग उनकी चिंता कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस के माध्यम से आंदोलन को दबाने, लाठीचार्ज करने और मुकदमे दर्ज करने जैसी कार्रवाइयों का सहारा लिया गया। आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई और विभिन्न प्रकार के नारे लगाए गए।

आंदोलनकारियों का कहना था कि उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग आगे आए, लेकिन कई स्थानों पर पुलिस ने सहायता पहुंचाने वालों को भी रोका। प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया। उनका प्रश्न था कि यदि छात्र अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके भोजन और पानी तक को रोकना किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है। आंदोलन के दौरान विपक्षी दलों के कई नेता भी समर्थन देने पहुंचे। किसी ने जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की तो किसी ने अलग स्थान पर धरना और अनशन किया। विपक्ष ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पेपर लीक पर कठोर कानून और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार की मांग की।

बीस जुलाई को जब प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आंदोलनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अनेक छात्र घायल हुए और कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। बाद में विपक्ष के सड़क पर उतरने के बाद सरकार ने तेज गति से कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक अदालत, नए कानून और विभिन्न सुधारों की घोषणाएं कीं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

रिश्वतखोरी केवल अपराध नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास को भीतर से खोखला करने वाली बीमारी

तारा ठाकुर
स्वतंत्र लेखक

रिश्वतखोरी केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास को भीतर ही भीतर खोखला करने वाली गंभीर बीमारी है। यह व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कमजोर करती है, ईमानदार लोगों का मनोबल तोड़ती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जब किसी सरकारी या निजी कार्य को नियमों के बजाय पैसे के बल पर करवाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, तब न्याय, समानता और पारदर्शिता जैसी लोकतांत्रिक मूल अवधारणाएं प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगता है और व्यवस्था के प्रति उसका विश्वास धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है।

रिश्वतखोरी का प्रभाव केवल व्यक्ति या किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ता है। जब किसी काम के लिए योग्यता और नियमों के बजाय धन तथा प्रभाव को अधिक महत्व मिलने लगे तो समाज में असमानता बढ़ती है। जिन लोगों के पास आर्थिक संसाधन होते हैं वे अपने काम आसानी से करवा लेते हैं, जबकि गरीब और कमजोर वर्ग अपने वैध अधिकारों के लिए भी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाता है। उसके पास रिश्वत देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते, इसलिए उसे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। इससे सामाजिक न्याय की भावना कमजोर होती है और नागरिकों में निराशा तथा असंतोष का वातावरण पैदा होता है।

रिश्वतखोरी का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव यह है कि यह योग्यता और ईमानदारी को पीछे धकेल देती है। किसी समाज में यदि मेहनत, प्रतिभा और नियमों के पालन से अधिक महत्व पैसे तथा संपर्कों को मिलने लगे तो प्रतिभाशाली युवाओं का विश्वास टूट सकता है। उन्हें लगने लगता है कि सफलता केवल योग्यता से नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव से हासिल की जा सकती है। ऐसी सोच किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बेहद नुकसानदायक है। देश की वास्तविक ताकत उसकी प्रतिभा, मेहनत और ईमानदार नागरिकों में होती है। यदि यही वर्ग व्यवस्था से निराश होने लगे तो विकास की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी।

आज रिश्वतखोरी का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, निर्माण कार्य, भर्ती प्रक्रियाओं, ठेकों, परिवहन और अनेक सरकारी सेवाओं तक दिखाई देता है। कई बार विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के कारण निर्धारित धनराशि का सही उपयोग नहीं हो पाता। परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है, गुणवत्ता प्रभावित होती है और जनता के लिए बनाई गई सुविधाएं अपेक्षित स्तर की नहीं रह पातीं। सड़कें जल्दी टूटती हैं, पुलों और भवनों की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तथा सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अंततः इसका आर्थिक बोझ भी आम नागरिकों को ही उठाना पड़ता है।

यदि विद्यालयों, अस्पतालों, सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में पारदर्शिता का अभाव रहेगा तो उसका सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना होता है, लेकिन भ्रष्टाचार इस उद्देश्य को कमजोर कर देता है। जिस धन का इस्तेमाल गरीबों, विद्यार्थियों, मरीजों या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए होना चाहिए, उसका एक हिस्सा गलत तरीके से निजी लाभ में चला जाए तो यह केवल सरकारी धन की हानि नहीं बल्कि जनता के अधिकारों का हनन भी है।

रिश्वतखोरी से निपटने के लिए केवल कठोर कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। कानूनों का निष्पक्ष और प्रभावी पालन भी उतना ही आवश्यक है। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के विरुद्ध समयबद्ध तथा निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या आर्थिक दबाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दोषियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि भ्रष्टाचार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

न्याय व्यवस्था की गति भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना व्यवस्था के प्रति गलत संदेश दे सकता है। यदि दोषी वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया में उलझे रहें और उन्हें समय पर दंड न मिले तो भ्रष्ट लोगों के मन में कानून का भय कम हो सकता है। इसलिए भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना आवश्यक है। कानून तभी प्रभावी होता है जब उसका क्रियान्वयन निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो।

रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने में डिजिटल व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकारी सेवाओं का अधिक से अधिक डिजिटलीकरण और ऑनलाइन व्यवस्था भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम कर सकती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

कम उम्र में शुरू किया अभिनय

नमिता प्रमोद
जन्म : 19 सितंबर 1996

नमिता प्रमोद का जन्म 19 सितंबर 1996 को हुआ था। वह मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री हैं। उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी प्रतिभा के दम पर दक्षिण भारतीय सिनेमा में पहचान बनाई। नमिता ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिकों से की थी। इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का अवसर मिला और उन्होंने अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाकर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

नमिता प्रमोद ने मलयालम सिनेमा में अभिनेत्री के तौर पर अपनी शुरुआत फिल्म 'ट्रैफिक' से की। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आईं और उनकी अभिनय क्षमता को दर्शकों ने पसंद किया। शुरुआती दौर में ही उन्हें लोकप्रिय कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिला। उनकी फिल्मों में रोमांस, पारिवारिक कहानी, हास्य और सामाजिक विषयों से जुड़ी भूमिकाएं देखने को मिलीं। उन्होंने अपनी सहज अदाकारी और स्क्रीन उपस्थिति के कारण कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई।

अभिनय के साथ नमिता ने विभिन्न प्रकार के किरदारों को निभाने की कोशिश की। यही वजह रही कि उनका करियर केवल एक ही तरह की भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने मलयालम के अलावा अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में अभिनय किया और युवा पीढ़ी की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में जगह बनाई।

नमिता प्रमोद की खासियत उनकी सरल और स्वाभाविक अभिनय शैली मानी जाती है। पर्दे पर वह अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने किरदार को सहजता से प्रस्तुत करती हैं। फिल्मी दुनिया में लगातार बदलती प्रतिस्पर्धा के बीच उन्होंने अपने काम के जरिए दर्शकों के बीच पहचान बनाए रखी। सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिलती है, जिससे उनके प्रशंसकों के साथ उनका जुड़ाव बना रहता है।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

भाजपा ने प्रकोष्ठ संकुल और सोशल मीडिया टीम का किया गठन

एजेंसी, लखनऊ

लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में नई जिम्मेदारियां तय करते हुए प्रकोष्ठ संकुल और सोशल मीडिया विभाग की टीम का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शुक्रवार को पदाधिकारियों की घोषणा की। प्रदेश भाजपा की ओर से जारी सूची में प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, सह-संयोजक, सोशल मीडिया प्रभारी, सह-संयोजक और सदस्यों के नाम शामिल हैं। जारी सूची के अनुसार ओम प्रकाश श्रीवास्तव को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। संतराम यादव और डॉ. मिथिलेश त्रिपाठी को प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुभाष यदुवंश को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया सह-संयोजक के पद पर गौरव वार्ष्णेय, विनीत मालवीय, अनुज चौधरी, मनोज मौर्य, निखिल सिन्हा और विवेक लवानिया को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जयंत शिवाच, वाई.के. शर्मा और अभिमन्यु सिंह को सोशल मीडिया सदस्य बनाया गया है।

प्रदेश भाजपा की ओर से जारी सूची में कुल 13 पदाधिकारियों के नाम घोषित किए गए हैं। नई नियुक्तियों के साथ पार्टी के प्रकोष्ठ संकुल और सोशल मीडिया विभाग में जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। प्रकोष्ठ संकुल के पदाधिकारियों को संगठन से जुड़े कार्यों में समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोशल मीडिया विभाग में नियुक्त पदाधिकारी पार्टी की डिजिटल गतिविधियों से जुड़े कार्यों को संभालेंगे। पदाधिकारियों की घोषणा के बाद संबंधित नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनकी नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। पार्टी की ओर से जारी सूची में सभी पदों और नियुक्त पदाधिकारियों के नाम स्पष्ट किए गए हैं। संगठनात्मक स्तर पर हुई इस घोषणा के बाद प्रकोष्ठ संकुल और सोशल मीडिया विभाग की गतिविधियों को नई टीम के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

विशाल गौतम की जमानत अर्जी ने बढ़ाया रहस्य, मां बोलीं- मैंने नहीं दी

एजेंसी, कानपुर। दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी विशाल गौतम की जमानत अर्जी सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। विशाल की मां सुशीला गौतम ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर जमानत अर्जी से अपना कोई संबंध होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने न तो जमानत के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया और न ही पैरवी के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया है। अचानक सामने आई अर्जी को लेकर परिवार भी हैरान है। सुशीला गौतम ने मामले में सुब्रत नाम के व्यक्ति पर आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। पुलिस आयुक्त ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विशाल की जमानत के लिए आवेदन किसने दिया और इसके पीछे किसका हाथ है।

विवेक तिवारी हत्याकांड में फैसला प्रशांत गैर इरादतन हत्या का दोषी

एजेंसी, लखनऊ। बहुचर्चित एपल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में अदालत ने बर्खास्त कांस्टेबल प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया। घटना के समय प्रशांत के साथ मौजूद कांस्टेबल संदीप कुमार को अभियोजन की ओर से पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया। अदालत ने माना कि प्रशांत चौधरी का विवेक तिवारी की हत्या करने का पहले से कोई उद्देश्य नहीं था। घटना अचानक उत्पन्न परिस्थितियों में हुई थी। इसी आधार पर अदालत ने प्रशांत को हत्या का दोषी नहीं माना और गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी ठहराया। मामले में प्रशांत को अब सजा कितनी होगी, इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं, संदीप कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी किए जाने का आदेश दिया गया है। फैसला आने के बाद मामले की कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण सजा निर्धारण पर केंद्रित रहेगा।

मारपीट के आरोप से दिग्विजय भाटी का यू-टर्न, कार्रवाई से किया इन्कार

एजेंसी, मेरठ। मेरठ में आइपीएस अविनाश पांडेय और तत्कालीन सिविल लाइन इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर मारपीट और यातना देने के आरोपों के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सपा नेता दिग्विजय भाटी ने जांच अधिकारी डीआइजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को शपथ पत्र देकर मामले में किसी तरह की कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। दिग्विजय भाटी ने पहले अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब अपने बयान में उन्होंने चोट लगने की वजह स्कूटी से गिरना बताई है। उनके इस रुख से मामले की जांच की दिशा बदल गई है। दिग्विजय के साथ रहे मोहित जाटव ने भी उनके इस यू-टर्न पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मामले को लेकर पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है और अधिकारियों की ओर से दिग्विजय के शपथ पत्र को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे पहले 19 अगस्त को दिग्विजय ने मारपीट के आरोप लगाए थे। अब कार्रवाई से पीछे हटने के बाद पूरे प्रकरण को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

2000 से ज्यादा के ईंधन पर कैश देना होगा, 15 अक्टूबर से लागू होगा नियम

एजेंसी, आगरा। आगरा में 15 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर दो हजार रुपये से अधिक के ईंधन भुगतान के लिए कैश रखना होगा। पेट्रोल पंप संचालकों ने पांच रुपये के फिक्स्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का विरोध करते हुए यह फैसला लिया है। दो हजार रुपये तक के ईंधन का भुगतान यूपीआई से किया जा सकेगा। जिले में 374 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें 75 शहरी क्षेत्र में हैं। वर्तमान में यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन नए नियम के तहत दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर पंप संचालकों को पांच रुपये शुल्क देना होगा। यह शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा।

यूपीपीएससी में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 168 पदों पर भर्ती

एजेंसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 168 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों से 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र 450 अंकों का होगा और इसे हल करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा। आयोग की ओर से जारी योजना के अनुसार परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। भर्ती को लेकर अभ्यर्थी परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कर सकेंगे।

पुराने और संकरे नालों का होगा कायाकल्प, 100 वार्डों में जल निकासी व्यवस्था होगी मजबूत

500 करोड़ से बदलेगा प्रयागराज का जल निकासी तंत्र

एजेंसी, प्रयागराज

शहर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम ने जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत शहर के सभी 100 वार्डों में नए नाले और नालियां बनाई जाएंगी। इस पूरी योजना पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की तैयारी है। योजना के अमल में आने के बाद बारिश के पानी की निकासी को गति मिलेगी और जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को होने वाली परेशानी कम होने की उम्मीद है।

नगर निगम की ओर से तैयार किए गए खाके में शहर की मौजूदा जल निकासी व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में कई इलाकों में नाले पुराने और संकरे हैं। इनकी क्षमता कम होने के कारण तेज बारिश के समय पानी की निकासी प्रभावित होती है। कई स्थानों पर नालियां पर्याप्त चौड़ी नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाता है। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है और कई बार घरों तथा दुकानों के आसपास भी पानी भर जाता है। नई कार्ययोजना में ऐसे क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जल निकासी ढांचे को मजबूत करने की तैयारी है।

नगर निगम का उद्देश्य केवल नए नाले और नालियां बनाना ही नहीं है, बल्कि पुराने जल निकासी ढांचे में भी आवश्यक सुधार करना है। जिन स्थानों पर पुराने नाले जर्जर या संकरे हो चुके हैं, वहां उनकी क्षमता बढ़ाने और उन्हें बेहतर बनाने की योजना है। इससे बारिश के दौरान पानी को तेजी से मुख्य निकासी मार्गों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जल निकासी व्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ शहर में पहले से मौजूद ढांचे की उपयोगिता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

प्रस्तावित परियोजना के तहत सभी 100 वार्डों को जल निकासी व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। अलग-अलग वार्डों में स्थानीय जरूरत और जलभराव की स्थिति के आधार पर नाले और नालियां विकसित किए जाने की योजना है। जिन क्षेत्रों में हर वर्ष बारिश के दौरान पानी जमा होने की समस्या सामने आती है, वहां निकासी व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जा सकता है।

इसके लिए नगर निगम स्तर पर व्यापक खाका तैयार किया गया है। शहर में जलभराव की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण रही है। बारिश के दौरान कई प्रमुख सड़कों, गलियों और रिहायशी क्षेत्रों में पानी जमा होने से यातायात प्रभावित होता है। पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट की मिस एप्रोच पायलट ने गो अराउंड कर उतारा विमान

एजेंसी, लखनऊ। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहुंचा इंडिगो का विमान पहली कोशिश में लैंड नहीं कर सका। पायलट को लैंडिंग के दौरान एप्रोच एरिया का सही आकलन करने में असुविधा हुई, जिसके बाद उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को गो अराउंड करा दिया। इसके बाद एटीसी से संपर्क कर दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

जानकारी के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट 6ई 2151 दिल्ली से उड़ान भरकर रात करीब 8:50 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची थी। विमान रनवे पर उतरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लैंडिंग के दौरान पायलट को एप्रोच एरिया को भांपने में दिक्कत महसूस हुई। किसी तरह का जोखिम लेने के बजाय पायलट ने गो अराउंड का निर्णय लिया। विमान को दोबारा उड़ान भराते हुए एटीसी से संपर्क किया गया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद विमान ने दूसरी कोशिश में रात 8:54 बजे सुरक्षित लैंडिंग की। बताया गया कि लखनऊ एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में इस तरह की एक और घटना सामने आ चुकी है।

आठ सितंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर आने वाले एअर इंडिया के विमान को भी पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो सकी थी। विमान ने दूसरे प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग की थी। इंडिगो विमान के मामले में भी पायलट के समय रहते गो अराउंड लेने से स्थिति सामान्य रही और सभी यात्री सुरक्षित उतर गए। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार घटना के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग होने से यात्रियों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एटीसी और पायलट के बीच समन्वय से स्थिति को संभाल लिया गया। एयरपोर्ट पर विमान के उतरने के बाद सामान्य परिचालन जारी रहा।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर 'आशीर्वाद का दीया' को लेकर राजभर का पलटवार

एजेंसी, लखनऊ

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित 'आशीर्वाद का दीया' अभियान को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि एक-दो दिन में अभियान में जलाए गए दीयों और इस्तेमाल हुए तेल को लेकर विपक्ष की ओर से हल्ला मचाया जाएगा।

राजभर ने कहा कि देशभर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया और अति पिछड़े तथा दलित समाज के लोगों ने सेवा संकल्प अभियान में भाग लिया। उनके अनुसार लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद का दीया जलाया और कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने अपने पोस्ट में कांग्रेस, सपा और वामपंथियों पर अभियान को लेकर सवाल उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने वामपंथी राजनीति की सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठाए और पिछड़े, दलित तथा बहुजन समाज के लोगों से इन मुद्दों पर विचार करने की अपील की।

राजभर ने आरोप लगाया कि गरीब और सामान्य परिवार से निकलकर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य पिछड़े तथा दलित नेताओं का उदाहरण देते हुए यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं की विचारधारा तथा नारों में समय के साथ बदलाव आया है।

नुरुल्लाह रोड पर पीडीए की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा

एजेंसी, प्रयागराज

शहर के नुरुल्लाह रोड पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की करीब तीन बीघा बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। जमीन पर कब्जा करके बड़ी संख्या में लोगों ने निर्माण कर लिया है। पीडीए ने अब इस जमीन को कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्थल का सर्वे पूरा कर लिया गया है।

सर्वे के दौरान करीब 40 से 50 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। इन निर्माणों के खिलाफ जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पीडीए अधिकारियों के अनुसार, नुरुल्लाह रोड स्थित जमीन प्राधिकरण की संपत्ति है। काफी समय से इस भूमि के कुछ हिस्सों पर लोगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं।

कब्जे के बाद यहां निर्माण भी कर लिए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने जमीन की स्थिति स्पष्ट करने और अवैध निर्माणों की पहचान के लिए सर्वे कराया। सर्वे में बड़ी संख्या में ऐसे निर्माण सामने आए हैं, जिन्हें प्राधिकरण ने अवैध श्रेणी में चिह्नित किया है। जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए पीडीए की ओर से आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

चिह्नित निर्माणों को नियमानुसार हटाने के लिए ध्वस्तीकर ण अभियान चलाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद रहेगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। पीडीए का उद्देश्य अपनी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है, ताकि उसका नियोजित तरीके से उपयोग किया जा सके। प्राधिकरण की योजना के अनुसार, जमीन को कब्जामुक्त कराने के बाद यहां भूखंड तैयार किए जाएंगे।

◆ **पीडीए** की योजना के अनुसार, अवैध निर्माण हटाने के बाद पूरी जमीन को कब्जामुक्त कराकर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां भूखंड तैयार किए जाएंगे और नियमानुसार उनकी बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे प्राधिकरण की बेशकीमती भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा और क्षेत्र में नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इसके बाद नियमानुसार इन भूखंडों को बेचने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे प्राधिकरण की भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही शहर में नियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नुरुल्लाह रोड शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है और यहां जमीन की कीमत काफी अधिक मानी जाती है। ऐसे में करीब तीन बीघा जमीन पर लंबे समय से हुए कब्जे को लेकर प्राधिकरण ने गंभीरता दिखाई है। सर्वे पूरा होने के बाद अब कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

संजय निषाद का विरोधियों पर हमला, बोले साढ़े चार साल बाद याद आया समाज

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मछुआरा समाज को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने मल्लाह, निषाद, केवट, कश्यप, बिंद, धीवर, कहार, बाथम, रायकवार और माझी समेत मछुआरा समुदाय के लोगों से चुनावी मौसम में सक्रिय होने वाले नेताओं से सतर्क रहने की अपील की।

संजय निषाद ने कहा कि जो लोग साढ़े चार साल तक समाज के सुख-दुख में शामिल नहीं हुए, वे अब पंचायत के बहाने उसके बीच पहुंचने लगे हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं को 'बरसाती मेंढक' और 'दरी बिछाने वाले सौदागर' बताते हुए निशाना साधा। उनके अनुसार चुनावी समय में अलग-अलग रूप में आने वाले ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है।

उन्होंने अपने पोस्ट में फूलन देवी का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि उनकी हत्या के जरिए मछुआरा समाज की अलग राजनीतिक पहचान को कमजोर करने का प्रयास किया गया। संजय निषाद ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाए हैं। ये आरोप उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं। संजय निषाद ने कहा कि मछुआरा समाज को अपने अधिकारों और राजनीतिक पहचान को लेकर एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में सक्रिय होने वाले नेताओं के दावों और वादों को परखने की जरूरत है।

यूपी में 11,508 सहायक अध्यापक भर्ती प्रतियोगी छात्र उत्साहित शिक्षामित्र निराश

एजेंसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी होने से प्रतियोगी छात्रों में उत्साह है, लेकिन लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षामित्रों को निराशा हाथ लगी है। शिक्षामित्रों का कहना है कि भर्ती विज्ञापन में उनके लिए भारांक और कोटे की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेजकर अपनी मांग रखी है। संघ के अनुसार, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षामित्र लंबे समय से कार्यरत हैं और सहायक अध्यापक भर्ती में उन्हें अनुभव का लाभ मिलने की उम्मीद थी। विज्ञापन में भारांक और आरक्षित कोटे का प्रावधान नहीं होने से उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। संघ ने शासन से भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं, 11,508 पदों पर भर्ती की घोषणा प्रतियोगी छात्रों के लिए रोजगार का अवसर लेकर आई है। लंबे समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती होने से उन्हें सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा। शिक्षामित्र संघ ने कहा है कि उनकी मांगों पर जल्द विचार किया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय से विद्यालयों में सेवाएं दे रहे शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के अनुरूप लाभ मिल सके।

सौरभ हत्याकांड में कोर्ट में बहस पूरी, मुस्कान और साहिल पर 30 सितंबर को फैसला

◆ **सौरभ राजपूत हत्याकांड के मामले में कोर्ट में बहस पूरी**

एजेंसी, मेरठ

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है। जिला जज न्यायालय में गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने फैसले की तारीख 30 सितंबर 2026 तय कर दी। अब अदालत के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हैं। मामले में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल आरोपी हैं।

दोनों इस समय जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर अपना पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को लेकर अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय के लिए तारीख निर्धारित कर दी। सुनवाई पूरी होने के बाद कचहरी परिसर में भी मामले को लेकर चर्चा होती रही। लोगों के बीच इस बात को लेकर उत्सुकता रही कि अदालत 30 सितंबर को क्या फैसला सुनाती है और आरोपियों को किस प्रकार की सजा मिलती है।

हालांकि, सजा का निर्धारण अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा। नीला ड्रम हत्याकांड सामने आने के बाद यह मामला काफी चर्चित रहा था। पुलिस जांच के बाद मुस्कान और साहिल को आरोपी बनाया गया था। मामले में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत में सुनवाई आगे बढ़ी। अब अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए 30 सितंबर की तारीख तय की है।

गोशाला | मेरठ रोड पर तैयार गोशाला में नगर क्षेत्र और आसपास के गांवों के गोवंशों को रखा जाएगा

दो करोड़ की कान्हा गोशाला तैयार, मेरठ में 500 से अधिक गोवंशियों को मिलेगी जगह

एजेंसी, मेरठ

बेसहारा गोवंशियों के संरक्षण के लिए नगर पालिका परिषद की ओर से मेरठ रोड पर बड़ा महादेव मंदिर के समीप आधुनिक कान्हा गोशाला का निर्माण कराया गया है। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई यह गोशाला अब जल्द ही 500 से अधिक बेसहारा गोवंशियों को आश्रय प्रदान करेगी। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और गोशाला को संचालित करने की तैयारियां की जा रही हैं।

नगर पालिका परिषद के अनुसार, गोशाला में नगर क्षेत्र के साथ आसपास के गांवों में घूमने वाले बेसहारा गोवंशियों को भी रखा जाएगा। यहां उनके लिए चारे और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। गोवंशियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। बीमार या घायल गोवंशियों के उपचार के लिए पशु चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। गोशाला के निर्माण का उद्देश्य बेसहारा गोवंशियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के साथ सड़कों पर उनके कारण होने वाली समस्याओं को कम करना भी है।

शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों पर घूमने वाले गोवंशियों के कारण कई बार यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। गोशाला शुरू होने के बाद ऐसे गोवंशियों को यहां लाकर सुरक्षित रखा जा सकेगा। नगर पालिका की ओर से गोशाला में साफ-सफाई, पेयजल, चारा, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, गोवंशियों की संख्या और जरूरत के अनुसार व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है।

स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आधुनिक सुविधाओं से तैयार इस गोशाला के संचालन से बेसहारा गोवंशियों को सुरक्षित स्थान मिलेगा और शहर की सड़कों पर उनकी मौजूदगी भी कम होगी। नगर पालिका परिषद जल्द ही गोशाला में गोवंशियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस परियोजना के माध्यम से नगर क्षेत्र और आसपास के गांवों में बेसहारा गोवंशियों के संरक्षण के लिए स्थायी व्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया गया है। दो करोड़ रुपये की लागत से बनी यह गोशाला 500 से अधिक गोवंशियों के लिए आश्रय का माध्यम बनेगी।

सड़कों से हटेंगे गोवंश

गोशाला शुरू होने के बाद नगर पालिका की ओर से गोवंशियों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए शहर के विभिन्न हिस्सों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले बेसहारा गोवंशियों को चिह्नित किया जा सकता है। गोशाला में पहुंचने के बाद उनके रहने, खाने और उपचार की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। इससे सड़कों पर खुले में घूमने वाले गोवंशियों की संख्या कम होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोशाला शुरू होने से यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा। वहीं, नगर पालिका के लिए गोशाला के संचालन और रखरखाव की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण होगी। अधिकारियों के अनुसार, जरूरत के अनुसार यहां अतिरिक्त सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं।

चलती रोडवेज बस में उठा धुआं यात्रियों में मची अफरातफरी

एजेंसी, कानपुर

कानपुर-हमीरपुर रोड पर पतारा के पास शुक्रवार को चलती रोडवेज बस के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। बस के अंदर और बाहर धुआं फैलने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। धुआं बढ़ता देखकर यात्रियों ने तत्काल बस से उतरकर सुरक्षित स्थान की ओर जाने की कोशिश की। हालांकि, घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित बस से बाहर निकल गए।

जानकारी के अनुसार, रोडवेज बस यात्रियों को लेकर कानपुर-हमीरपुर मार्ग पर जा रही थी। पतारा क्षेत्र में पहुंचने के दौरान बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में धुआं बस के अंदर तक पहुंच गया। इससे यात्रियों को परेशानी होने लगी और उनमें घबराहट फैल गई। चालक ने स्थिति को भांपते हुए बस को रोक दिया। इसके बाद यात्रियों को तत्काल नीचे उतारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस रुकते ही यात्री तेजी से बाहर निकलने लगे।

बस के आसपास भी धुआं दिखाई दे रहा था। यात्रियों के सुरक्षित उतर जाने के बाद मौके पर राहत की स्थिति बनी। समय रहते बस रोक दिए जाने से किसी बड़ी घटना की आशंका टल गई। रोडवेज बसों में लगातार सामने आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर यात्रियों में चिंता बढ़ रही है। इससे पहले भी बसों में टायर फटने और पंचर होने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं।

1857 की क्रांति का गवाह मंगाली, 12 अंग्रेजों को मार 300 देशभक्तों ने दिया बलिदान

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हिसार से करीब 15 किलोमीटर दूर नलवा विधानसभा क्षेत्र में स्थित मंगाली गांव इतिहास और वर्तमान की अनूठी तस्वीर पेश करता है। वर्ष 1488 में अस्तित्व में आए इस गांव का संबंध 1857 की क्रांति से भी रहा है। गांव के लोगों के बीच आज भी उस दौर के बलिदानियों की वीरगाथाएं और स्मृतियां जीवंत हैं। स्थानीय इतिहास के अनुसार, 1857 की क्रांति के दौरान मंगाली में अंग्रेजों और देशभक्तों के बीच संघर्ष हुआ था।

बताया जाता है कि संघर्ष में 12 अंग्रेज मारे गए थे। इसके बाद करीब 300 देशभक्तों ने कुएं में कूदकर बलिदान दिया था। गांव में आज भी इस घटना को साहस और बलिदान की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। समय के साथ मंगाली का विस्तार हुआ और यह पांच पंचायतों में विभाजित हो गया। इनमें मंगाली आकलान, मंगाली झारा, मंगाली सुरतिया, मंगाली मोहब्बत और ढाणी जाटान शामिल हैं। पांचों पंचायतों की कुल आबादी 20 हजार से अधिक बताई जाती है। गांव की एक अलग पहचान मनके के कारोबार से भी जुड़ी है। यहां तैयार होने वाले मनकों का व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है।

इतिहास के साथ शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में भी गांव ने अपनी पहचान बनाई है। फुटबाल में यहां के खिलाड़ियों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हालांकि गांव के सामने आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां हैं। पेयजल, जल निकासी और सड़क जैसी समस्याएं ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप गांव के विकास और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इतिहास की विरासत के साथ गांव में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी प्रतिभाएं उभर रही हैं।

शाहुपुरा में पूर्व सरपंच के घर डकैती, बदमाश 70 तोले सोना और नकदी लेकर फरार

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ क्षेत्र के शाहुपुरा गांव में पूर्व महिला सरपंच के घर देर रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चार-पांच बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे और परिवार के सदस्यों को कमरे में बंद कर लाखों रुपये के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान में करीब 70 तोले सोना, ढाई किलो चांदी और 3.5 लाख रुपये नकद शामिल बताए जा रहे हैं। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई है। जानकारी के अनुसार, पूर्व सरपंच राधा रानी अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थीं। रात के समय चार-पांच युवक अचानक दीवार फांदकर परिसर में दाखिल हुए। आरोप है कि बदमाशों ने कमरे में सो रहे परिवार के सदस्यों को किसी पदार्थ को सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने बाहर से कमरे की कुंडी लगा दी, ताकि परिवार के लोग बाहर न निकल सकें।

परिवार के सदस्य जब तक कुछ समझ पाते, आरोपी घर में रखी अलमारी तक पहुंच गए। बदमाशों ने अलमारी में रखे सोने और चांदी के आभूषणों के अलावा नकदी भी निकाल ली। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सुबह पूर्व सरपंच के पति देवी स्वरूप की नींद खुली तो उन्होंने अलमारी की जांच की। सामान गायब मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया है। वारदात के तरीके को देखते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वारदात में इस्तेमाल किए गए तरीके और आरोपियों की संख्या को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस जल्द आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

हरियाणा को दूरसंचार सुधारों के लिए मिलेगा 150 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन

6222 में से 5154 ग्राम पंचायतें भारतनेट से जुड़ीं, 1068 पंचायतों को जोड़ने की तैयारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों तक तेज इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की कुल 6,222 ग्राम पंचायतों में से 5,154 यानी 82.84 प्रतिशत पंचायतें भारतनेट के दायरे में आ चुकी हैं। वहीं, राज्य में 45,130 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन भी कार्यरत हैं। शेष 1,068 ग्राम पंचायतों को भी भारतनेट से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारतनेट, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियम, 2024, 5जी नेटवर्क विस्तार और दूरसंचार परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में ग्रामीण

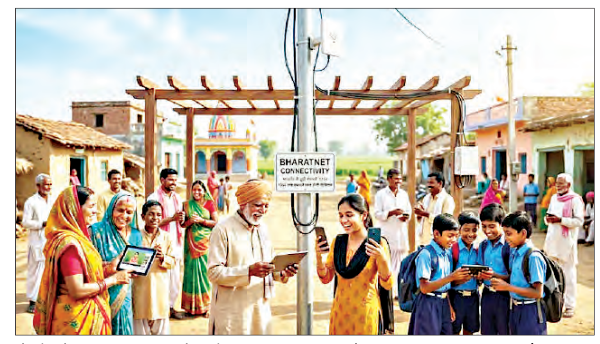

क्षेत्रों में डिजिटल ढांचे को मजबूत करने के साथ दूरसंचार परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

वित्त वर्ष 2026-27 में राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के भाग-छह के तहत हरियाणा के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। यह प्रोत्साहन दूरसंचार क्षेत्र में छह सुधार लक्ष्यों की उपलब्धि से जुड़ा है।

राज्य ने इनमें से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। 31 मार्च 2026 तक लंबित सभी आरओडब्ल्यू आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। 150 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज में आरओडब्ल्यू नियमों के क्रियान्वयन संबंधी आदेशों के लिए 45 करोड़ रुपये, राज्य आरओडब्ल्यू पोर्टल के लिए 22.5 करोड़ रुपये और पुराने लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए अधिकतम 22.5 करोड़ रुपये निर्धारित हैं।

इसके अलावा औसत निपटारा अवधि को 45 दिन या उससे कम करने के लिए 7.5 करोड़ रुपये, भारतनेट अनुपालन के लिए 37.5 करोड़ रुपये और बिजली क्षेत्र से संबंधित आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बैठक में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित 62,220 एफटीटीएच कनेक्शनों में से 45,130 यानी 72.53 प्रतिशत कनेक्शन वर्तमान में कार्यरत हैं।

एयूडीआई कार ट्रांसफर के नाम पर महिला अफसर से 76 हजार हड़पे

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

पंचकूला में साइबर ठगों ने महिला अफसर को आरटीओ अधिकारी बनकर 76 हजार रुपये का चूना लगा दिया। ठगों ने उनकी एयूडीआई कार को दिल्ली से हरदोई ट्रांसफर करवाने के नाम पर संपर्क किया और दस्तावेज मंगवाकर ठगी को अंजाम दिया। महिला अफसर ने मामले की शिकायत पंचकूला सेक्टर-20 स्थित साइबर क्राइम थाने में दर्ज करवाई है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, महिला अफसर अपनी एयूडीआई कार को दिल्ली से हरदोई ट्रांसफर करवाना चाहती थीं। इसी दौरान उनके पास कथित तौर पर आरटीओ अधिकारी बनकर फोन आया। फोन करने वाले ने कार के दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा। महिला अफसर ने अधिकारी समझकर उसके साथ दस्तावेज साझा कर दिए।

इसके बाद ठगों ने कार ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर अलग-अलग मदों में रुपये जमा करवाने को कहा। महिला अफसर उनकी बातों में आ गईं और बताए गए बैंक खाते में कुल 76 हजार रुपये भेज दिए। रकम ट्रांसफर होने के बाद कथित आरटीओ अधिकारी ने संपर्क करना बंद कर दिया। इसके बाद महिला अफसर को ठगी का पता चला। महिला अफसर ने तुरंत साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 में शिकायत दी।

पानीपत में पांच साल के आहद का अपहरण, तीन दिन से तलाश में जुटी पुलिस

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

पांच वर्षीय आहद के तीन दिन से लापता होने के बाद परिवार में चिंता का माहौल है। बेटे की तलाश में मां फिरदोस का रो-रोकर बुरा हाल है। वह लगातार बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठी हैं। परिजनों के अनुसार, तीन दिनों से मां ने ठीक से खाना नहीं खाया है और लगातार बेटे को तलाश रही हैं।

पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया है। सीआईए की तीन टीमें और करीब 40 जवान अलग-अलग इलाकों में बच्चे की तलाश कर रहे हैं। करीब पांच किलोमीटर के दायरे में गलियों, रास्तों और आसपास के क्षेत्रों को खंगाला जा रहा है। पुलिस की टीमें संभावित स्थानों पर जांच करने के साथ लोगों से भी जानकारी जुटा रही हैं। मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस जांच का अहम हिस्सा हैं।

फुटेज में एक युवक बच्चे को गोद में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके बाद पुलिस ने बच्चे के लापता होने की परिस्थितियों और युवक की पहचान को लेकर जांच शुरू की है। पुलिस आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि बच्चे के जाने की दिशा और उसके साथ मौजूद व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल सके। परिवार का कहना है कि आहद के बिना घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। मां हर आहट पर दरवाजे की ओर देखती हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि उनका बेटा वापस आ जाएगा।

परिजन पुलिस से बच्चे को जल्द सकुशल बरामद करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश और तलाश अभियान चला रही हैं। साथ ही बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और बच्चे की तलाश के लिए सभी संभावित पहलुओं पर काम किया जा रहा है।

पानीपत में अवैध थड़ों पर कार्रवाई, जेसीबी से ढहाए निर्माण

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। इसराना में ग्राम पंचायत की ओर से मुख्य रास्ते पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। एसडीएम के आदेश पर गुरुवार को प्रशासनिक टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और दुकानों के सामने बनाए गए अवैध थड़ों व अन्य निर्माण को हटाया। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुशील कुमार रोहिल्ला भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मुख्य रास्ते पर बनाए गए कई अवैध निर्माण जेसीबी से ढहाए गए। इससे रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि, कार्रवाई को लेकर कुछ ग्रामीणों ने दोबारा निशानदेही कराने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई से पहले पूरे क्षेत्र की सही तरीके से निशानदेही की जानी चाहिए, ताकि किसी वैध निर्माण को नुकसान न पहुंचे।

फरीदाबाद में टूटे बिजली तार की चपेट में आकर युवक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

सेक्टर-56 स्थित राजीव कॉलोनी में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए घर से निकला था। पंडित चौक के पास सड़क पर टूटकर पड़े बिजली के तार की चपेट में पहले कुत्ता आया। उसे बचाने के प्रयास में युवक भी करंट की चपेट में आ गया। हादसे में युवक और उसके पालतू कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान राजीव कॉलोनी निवासी अमन चौटाला के रूप में हुई है। अमन एक निजी कंपनी में काम करता था और रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह अपने पालतू कुत्ते के साथ सैर पर निकला था। स्थानीय लोगों के अनुसार, पंडित चौक के पास बिजली का तार रात में टूटकर

सड़क पर गिर गया था। सुबह तक तार वहीं पड़ा रहा।

परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते टूटे तार को हटाया जाता या घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग की जाती तो हादसा टल सकता था। परिजनों ने मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर-58 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

रेलवे की स्वच्छता व्यवस्था में बदलाव, अब यात्री बताएंगे ट्रेनों की सफाई का वास्तविक हाल

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

रेलवे अब ट्रेनों में सफाई व्यवस्था को लेकर यात्रियों से सीधे प्रतिक्रिया लेगा। 'स्वच्छता ही सेवा 2026' अभियान के तहत यात्रियों को सफाई व्यवस्था का हिस्सा बनाने की तैयारी की गई है। अब यात्री यह बता सकेंगे कि ट्रेन में उन्हें दिया गया कंबल और तकिया साफ था या नहीं, टॉयलेट की स्थिति कैसी थी और डिब्बे में नियमित सफाई हुई या नहीं।

रेलवे की इस पहल का उद्देश्य ट्रेनों में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। देशभर में प्रतिदिन दो करोड़ से अधिक यात्री रेल से सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे का मानना है कि सफाई की निगरानी केवल कर्मचारियों तक सीमित न रहकर यात्रियों की भागीदारी से अधिक प्रभावी हो सकती है। चलती ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा (ओबीएचएस) के पर्यवेक्षक और संबंधित ठेकेदार सफाई व्यवस्था की औचक जांच करेंगे। इस दौरान शौचालय, यात्री डिब्बों, लिनेन और पेंट्री कार की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। एसी कोच में यात्रियों

को उपलब्ध कराए जाने वाले चादर, कंबल और तकिये की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

यात्रियों से सफाई व्यवस्था के साथ-साथ उपलब्ध कराए गए लिनेन की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। इससे रेलवे को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि यात्रियों को जमीनी स्तर पर किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। अभियान के तहत औचक निरीक्षण और यात्री प्रतिक्रियाओं के आधार पर संबंधित अधिकारियों तथा सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। रेलवे का जोर सफाई व्यवस्था में लापरवाही को कम करने और यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित तथा बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने पर है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, फीडबैक के आधार पर सफाई सेवाओं में कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

यात्रियों की शिकायतों और सुझावों को संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सफाई व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा सके। अभियान के दौरान लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार कर्मचारियों और ठेकेदारों से जवाब मांगा जाएगा। रेलवे का मानना है कि यात्रियों की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा और ट्रेनों में साफ-सफाई के मानकों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।

झज्जर में सड़क निर्माण के बाद अधूरा टाइल कार्य बना परेशानी

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर

शहर के छिकारा चौक से धौड़ चौक तक करीब 1300 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद अब दोनों तरफ इंटरलॉक टाइल लगाने का काम धीमी गति से चल रहा है। इसके चलते बैंक रोड के दुकानदारों और यहां आने वाले ग्राहकों को पिछले करीब चार माह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली को लेकर स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी है।

यादव धर्मशाला से छिकारा चौक तक सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है। वहीं, छिकारा चौक से धौड़ चौक के बीच इंटरलॉक टाइल बिछाने की गति काफी सुस्त बनी हुई है। निर्माण कार्य के दौरान दुकानों के सामने बने नालों को तोड़ दिया गया था। दुकानदारों का कहना है कि नालों को तोड़ने के बाद उन्हें व्यवस्थित करने का काम भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय दुकानदार अमित, परीक्षित, रोहित, महेंद्र, दयानंद और देवेंद्र ने बताया कि

सड़क निर्माण शुरू होने के समय उम्मीद थी कि काम जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन कई महीने बीतने के बावजूद टाइल लगाने का कार्य अधूरा पड़ा है।

कई स्थानों पर अस्थायी रास्ते बनाए गए हैं, जिनसे पैदल चलने वालों के साथ दुकानदारों और ग्राहकों को भी परेशानी होती है। बारिश या भीड़ के दौरान स्थिति और मुश्किल हो जाती है। दुकानदारों के मुताबिक, अधूरे रास्तों और टूटे नालों के कारण ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में असुविधा हो रही है। कुछ स्थानों पर लोगों के गिरने का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने संबंधित विभाग से मांग की है कि इंटरलॉक टाइल लगाने और नालों को व्यवस्थित करने का काम तेज किया जाए।

गुरुग्राम में कंपनी मैनेजर की हत्या, पूर्व सहकर्मी और लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-70 स्थित नाले से मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान दिल्ली के सरिता विहार निवासी युवराज सिंह मनचंदा के रूप में हुई है। वह गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित अडानी रियल्टी कंपनी में मैनेजर था। पुलिस ने उसकी पूर्व सहकर्मी आन्या वत्स और उसके लिव-इन पार्टनर संयम सचदेवा को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, युवराज शादी की खरीदारी के लिए घर से निकला था। इसी दौरान उसकी आन्या और संयम से कहासुनी हुई। आरोप है कि दोनों ने युवराज की गर्दन में दो गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को करीब सात घंटे तक क्रेटा कार में रखा गया और बाद में सेक्टर-70 के नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने युवराज की कॉल डिटेल के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और दोनों आरोपियों तक पहुंची। दोनों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने का प्रयास कर रही है। मामले में पूछताछ जारी है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से हत्या के कारण, हथियार की व्यवस्था और वारदात के बाद शव ठिकाने लगाने को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार आरोपियों के पास कहां से आया था। इसके अलावा क्रेटा कार की भी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि वारदात की योजना पहले से बनाई गई हो सकती है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद है।

न्यूज ब्रीफ

हरियाणा के पेट्रोल पंपों पर बंद हो सकता है यूपीआई भुगतान शुल्क का विरोध

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। हरियाणा में पेट्रोल पंपों पर यूपीआई भुगतान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर पांच रुपये मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाए जाने के फैसले का ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि पेट्रोल पंपों को शुल्क से राहत नहीं मिली तो राज्यभर में कैशलेस भुगतान सुविधा बंद कर दी जाएगी और ग्राहकों से केवल नकद भुगतान लिया जाएगा। हिसार एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार सलेमगढ़ ने बताया कि 17 सितंबर को वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजा गया है। डीलरों के अनुसार, 2017 के बाद से कमीशन नहीं बढ़ा है।

दादी के निधन के बाद भी देश सेवा में जुटीं मनु भाकर, जापान पहुंचीं

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर। झज्जर की निशानेबाज मनु भाकर इन दिनों जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी बीच वह निजी जीवन में भावुक दौर से गुजर रही हैं। 8 सितंबर को उनकी दादी का निधन हो गया था। दादी की रस्म क्रिया में शामिल नहीं हो पाने के बावजूद मनु भाकर ने देश के लिए मैदान पर उतरने का फैसला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं साझा कीं। परिवार के इस दुखद समय के बीच वह भारतीय दल के साथ प्रतियोगिता में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। मनु के प्रशंसक उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं।

रोहतक में नर्सरी छात्रा से दुष्कर्म पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। रोहतक के निजी स्कूल में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पीजीआई की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज में पांचवीं कक्षा का छात्र बच्ची की कक्षा में करीब आधे घंटे तक दिखाई दिया। पुलिस अब स्कूल स्टाफ और छात्र से पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस बच्ची के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

हरियाणा की 5,154 ग्राम पंचायतें भारतनेट के दायरे में

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा की 6,222 ग्राम पंचायतों में से 5,154 यानी 82.84 प्रतिशत भारतनेट के दायरे में आ चुकी हैं। राज्य में 45,130 एफटीटीएच कनेक्शन कार्यरत हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में भारतनेट, 5जी नेटवर्क विस्तार और राइट ऑफ वे नियमों की समीक्षा की। वित्त वर्ष 2026-27 में दूरसंचार क्षेत्र के सुधारों के लिए राज्य को 150 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित है। 31 मार्च 2026 तक लंबित सभी आरओडब्ल्यू आवेदनों का निपटारा हो चुका है। रस्तोगी ने शेष सुधार लक्ष्यों को समय पर पूरा करने, स्वीकृति प्रक्रिया तेज करने और सरकारी संपत्तियों पर 5जी नेटवर्क विस्तार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर रोक बढ़ी हाई कोर्ट ने 25 सितंबर तक आदेश जारी रखा

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम स्थित लग्जरी आवासीय परियोजना ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर लगी रोक को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक परियोजना में किसी नए आवंटन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। यह परियोजना ओबेरॉय रियल्टी की ओर से विकसित की जा रही है। मामले में एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिका में संबंधित विभाग की ओर से 17 अगस्त को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज और न्यायमूर्ति पूजा चोपड़ा की खंडपीठ ने 16 सितंबर को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके तहत ओबेरॉय 360 नॉर्थ परियोजना में नए आवंटन पर लगी रोक 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। कोर्ट ने

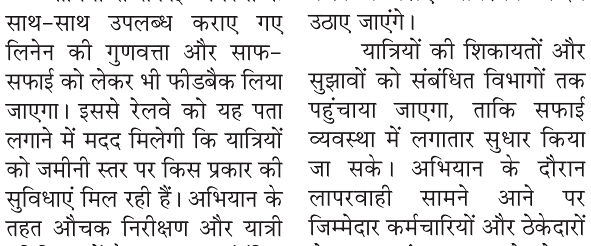

स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक परियोजना में कोई नया आवंटन नहीं किया जाएगा।

इससे परियोजना से जुड़े नए आवंटन की प्रक्रिया फिलहाल रोक के दायरे में रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को प्रस्तावित है, जिसमें कोर्ट आगे की स्थिति पर विचार करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित विभाग के 17 अगस्त के आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद यह मामला हाई कोर्ट के समक्ष आया है। अदालत ने फिलहाल मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष दिए बिना अंतरिम व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। ओबेरॉय 360 नॉर्थ गुरुग्राम की प्रमुख लग्जरी आवासीय परियोजनाओं में शामिल है। नए आवंटन पर रोक से परियोजना में आगे की आवंटन प्रक्रिया प्रभावित रहेगी।

अब मामले में अगली सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पक्षकारों की दलीलें और संबंधित दस्तावेज रखे जाएंगे। इसके आधार पर अंतरिम आदेश को आगे जारी रखने या उसमें बदलाव को लेकर अदालत निर्णय ले सकती है। फिलहाल 25 सितंबर तक परियोजना में नए आवंटन पर रोक जारी रहेगी। हाई कोर्ट के अगले आदेश के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि परियोजना में नए आवंटन की प्रक्रिया कब शुरू हो सकेगी।

पड़ाव क्षेत्र में तीन दुकानदारों का सामान जब्त, प्रमुख बाजारों और मार्गों से हटाया अतिक्रमण

हिसार में अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई तेज

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

शहर की सड़कों और बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम की तहबाजारी टीम ने वीरवार को शहर के विभिन्न प्रमुख बाजारों और मार्गों पर अभियान चलाया। इस दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थान पर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पड़ाव क्षेत्र में टीम ने दो-तीन दुकानदारों का सामान जब्त किया।

नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर आवागमन को सुचारु बनाए रखना है। शहर के कई हिस्सों में दुकानदारों की ओर से दुकानों के बाहर सामान रखने के कारण सड़क और फुटपाथ का हिस्सा घिर जाता है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण के कारण कई स्थानों पर बाजारों में भीड़ की स्थिति बन जाती है। इसी को देखते हुए निगम की तहबाजारी टीम लगातार अभियान चला रही है। वीरवार को टीम ने पड़ाव क्षेत्र समेत शहर के अन्य प्रमुख बाजारों और मार्गों का

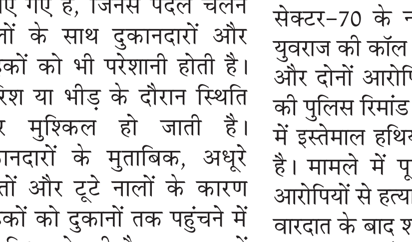

◆ सड़क और सार्वजनिक स्थान से सामान हटाती तहबाजारी टीम

निरीक्षण किया। इस दौरान जहां भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर सामान रखकर अतिक्रमण किया गया था, वहां कार्रवाई की गई। पड़ाव क्षेत्र में कुछ दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया और उनका सामान जब्त कर लिया गया।

निगम की टीम ने दुकानदारों को सार्वजनिक स्थान पर सामान न रखने की हिदायत भी दी। अभियान के दौरान टीम ने बाजारों की स्थिति का जायजा लिया और अतिक्रमण वाले स्थानों को खाली करवाया। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। शहर में अभियान आगे भी जारी रहने की संभावना है। नगर निगम की तहबाजारी टीम की कार्रवाई से उन दुकानदारों में भी हलचल है, जो दुकानों के बाहर सामान रखकर रास्ते को घेर लेते हैं। निगम का प्रयास है कि दुकानदार अपनी निर्धारित सीमा के भीतर ही सामान रखें, ताकि बाजारों में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। विशेष रूप से व्यस्त बाजारों और मार्गों पर अतिक्रमण हटाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

अतिक्रमण हटाने के लिए निगम की टीम समय-समय पर बाजारों का निरीक्षण कर रही है। अधिकारियों के निर्देश पर टीम द्वारा ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है, जहां सड़क या फुटपाथ पर दुकानदारों ने सामान रख रखा है। कार्रवाई के दौरान सामान जब्त करने के साथ संबंधित दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी जा रही है। शहरवासियों का कहना है कि प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। सड़क किनारे सामान रखे होने से पैदल चलने वालों के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बचती।

2027 से कक्षा छह में त्रि-भाषा नीति लागू करने पर विचार करे सीबीएसई : सुप्रीम कोर्ट

मौजूदा विद्यार्थियों को नए प्रावधान से राहत देने की जरूरत पर जोर

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कक्षा छह के विद्यार्थियों के लिए त्रि-भाषा नीति को 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने यह सुझाव वर्तमान शैक्षणिक सत्र के बीच विद्यार्थियों पर अचानक अतिरिक्त भाषा का दबाव नहीं डालने के उद्देश्य से दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मौजूदा कक्षा छह के विद्यार्थी यदि इसी वर्ष तीन भाषाएं पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जा सकती है।

सीबीएसई ने सुझाव पर जताई सहमति : मामले की सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय के सुझाव पर सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श कर बोर्ड अपना जवाब देगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका सुझाव नीति की वैधता पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि वर्तमान कक्षा छह के विद्यार्थियों और उनके परिवारों को शैक्षणिक वर्ष के बीच अचानक बदलाव से राहत देने के उद्देश्य से है।

त्रि-भाषा व्यवस्था में भारतीय भाषाओं पर जोर : सीबीएसई की नई व्यवस्था में तीन भाषाओं के अध्ययन का प्रावधान है, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। बोर्ड ने इस व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 के अनुरूप तैयार किया है। सीबीएसई के अनुसार, कक्षा नौ में एक जुलाई 2026 से तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है और इनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। विदेशी भाषा को तीसरी भाषा या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में चुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का मुख्य केंद्र इस समय कक्षा छह में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं।

नीति लागू करने की तैयारी जारी

सीबीएसई पहले ही तीन-भाषा नीति से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। बोर्ड की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्कूलों में भाषा शिक्षण को भारतीय भाषाओं के अध्ययन के साथ जोड़ने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। भाषा विकल्पों के साथ पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सीबीएसई ने तीन-भाषा नीति पर जून 2026 में दिशा-निर्देश जारी किए थे।

नीति पर न्यायालय में चल रही सुनवाई

तीन-भाषा व्यवस्था को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले 27 मई को न्यायालय ने केंद्र, सीबीएसई और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से जवाब मांगा था। अब अदालत के सुझाव के बाद सीबीएसई को मौजूदा कक्षा छह के विद्यार्थियों के लिए नीति लागू करने की समय-सीमा पर विचार करना है।

दक्षिणी दिल्ली में 60 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

निवेश का झांसा देकर महिला से आभूषण और नकदी लेकर हुआ था फरार

एजेंसी, नई दिल्ली

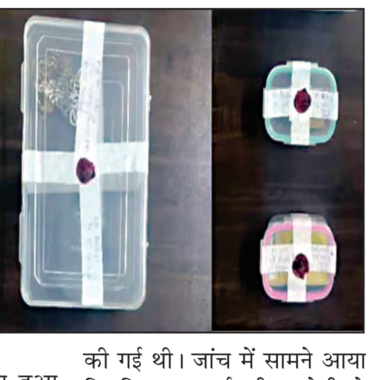

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव थाना पुलिस ने करीब 60 लाख रुपये की ज्वेलरी और नकदी की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी यश कैलाश बुलचंदानी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 96 ग्राम पिघला हुआ सोना, सोने के दो सिक्के, सोने की एक चेन, हीरे का एक सेट और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताकर शिकायतकर्ता का विश्वास जीता और उसे निवेश के लिए रुपये और आभूषण देने के लिए राजी किया था।

सोशल मीडिया के जरिए महिला से बढ़ाया संपर्क : दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के अनुसार, 17 जुलाई को सफदरजंग एन्क्लेव थाने में करीब 60 लाख रुपये की ज्वेलरी और नकदी की धोखाधड़ी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता की आरोपी से सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई थी। आरोपी ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताया और निवेश में लाभ दिलाने का भरोसा देकर उससे रुपये और आभूषण हासिल कर लिए।

पुलिस के मुताबिक, नौ जुलाई को आरोपी दिल्ली में शिकायतकर्ता से मिला था। इस दौरान वह उसका मोबाइल फोन, ज्वेलरी और एक बैग लेकर फरार हो गया। बैग में करीब 14 लाख रुपये नकद और एक क्रेडिट कार्ड भी रखा था। घटना के बाद शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

तकनीकी जांच से गुजरात तक पहुंची पुलिस

मामले की जांच के लिए सफदरजंग एन्क्लेव थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम में उपनिरीक्षक पंकज कुमार, हेड कांस्टेबल भवानी सिंह और कांस्टेबल अभिषेक शामिल थे। सहायक पुलिस आयुक्त मेल्विन वर्गीज की निगरानी में टीम ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध अभिलेखों का विश्लेषण किया। संबंधित एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं से भी जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की पहचान और उसके ठिकाने से संबंधित अहम जानकारी मिली। इसके आधार पर टीम ने मेहसाणा, गुजरात में छापा मारकर खेड़ा निवासी यश कैलाश बुलचंदानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 96 ग्राम पिघला हुआ सोना, दो सोने के सिक्के, एक सोने की चेन, हीरे का एक सेट और मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और बरामद सामान तथा कथित धोखाधड़ी से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ठगी की रकम और आभूषणों को कहां रखा गया था तथा इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। जांच टीम बरामद किए गए सोने और हीरे के सामान के स्रोत और उनकी खरीद-बिक्री से संबंधित जानकारी भी जुटा रही है। पुलिस ने संबंधित दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी जांच के दायरे में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फतेहाबाद में 672 मतदाताओं का पांच साल से इंतजार, अब प्रशासन को चेतावनी

एजेंसी, नई दिल्ली

◆ एसडीएम को मांगपत्र सौंपते नई बस्ती के ग्रामीण

नई बस्ती के 672 मतदाताओं और करीब दो हजार की आबादी को पंचायत व्यवस्था में शामिल करने का मामला एक बार फिर सामने आया है। पिछले करीब पांच वर्षों से प्रशासनिक व्यवस्था के बीच फंसे बस्तीवासियों ने अब अपनी मांग को लेकर सरकार और प्रशासन के समक्ष स्पष्ट रुख अपनाया है। ग्रामीणों ने टोहाना के एसडीएम को मांगपत्र सौंपकर नई बस्ती को जाखल ग्राम पंचायत में शामिल करने अथवा अलग पंचायत बनाने की मांग की है।

बस्तीवासियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। इससे क्षेत्र के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले का समाधान करने की मांग की है, ताकि नई बस्ती के लोगों को उचित पंचायत व्यवस्था का लाभ मिल सके।

मांगपत्र सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि नई बस्ती में करीब दो हजार लोग रहते हैं और यहां 672 मतदाता हैं। इन लोगों को पंचायत व्यवस्था में शामिल किए जाने को लेकर पिछले पांच वर्षों से मामला लंबित है।

ग्रामीणों ने कहा कि वे चाहते हैं कि नई बस्ती को जाखल ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए। यदि यह संभव नहीं है तो उनके लिए अलग पंचायत का गठन किया जाए। ग्रामीणों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नई बस्ती को नगरपालिका में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है, तो वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने गुरुद्वारा बस्ती अंडरपास पर धरना देने की चेतावनी दी है। बस्तीवासियों का कहना है कि उनकी प्राथमिक मांग पंचायत व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट स्थान को लेकर है।

गुरुग्राम बाइकर हादसे को जातिगत रंग देने का महिला ने किया विरोध

एजेंसी, नई दिल्ली। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने का मामला अब जाति और समुदाय की बहस तक पहुंच गया है। आरोपी कल्याण सिंह बैंसला के समर्थन में पलवल के कुशलीपुर स्थित गुर्जर धर्मशाला में महापंचायत बुलाए जाने की सूचना है। सोशल मीडिया पर इसके पोस्टर भी प्रसारित किए गए हैं। वहीं महिला बाइकर ने हादसे को जाति या समुदाय से जोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि इससे मूल मुद्दे से ध्यान भटक रहा है।

◆ **पीड़िता ने सड़क सुरक्षा और न्याय का मुद्दा बताते हुए महापंचायत पर उठाए सवाल**

महिला बाइकर का कहना है कि घटना का संबंध आरोपी की जाति, समुदाय या राज्य से नहीं है। हादसे के समय उन्हें आरोपी का नाम, पता या जाति तक मालूम नहीं थी। उन्होंने कहा कि सड़क पर किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। इसलिए मामले को जातिगत नजरिए से देखने के बजाय सड़क सुरक्षा और न्याय के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल उन्हें न्याय दिलाना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना भी है।

पुलिस के अनुसार 13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई घटना में कल्याण बैंसला कार चला रहा था और कार में अन्य लोग भी मौजूद थे। जांच में सामने आया कि कार ने महिला बाइकर की बाइक का करीब दो किलोमीटर तक पीछा किया और बाद में उसे टक्कर मारी गई। घटना के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में धाराएं बढ़ाईं। आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत पीछा करने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गईं।

नोएडा के सेक्टर-63 गारमेंट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए का सामान जला

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा के सेक्टर-63 एफ ब्लाक स्थित जय साई फैशन नाम की गारमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे अचानक आग लग गई। फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से धुआं उठता देखकर वहां तैनात गार्ड ने तत्काल फैक्ट्री प्रबंधन और अग्निशमन विभाग के कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। देखते ही देखते आग ने तीसरी मंजिल के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में रूई, कपड़ा और धागा समेत अन्य सामग्री रखी होने के कारण आग तेजी से भड़कने लगी। इससे मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। दमकलकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए पानी की बौछार शुरू की और आग को फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकने का प्रयास किया। दमकल विभाग की टीम ने करीब एक घंटे तक मशक्कत की। लगातार पानी की बौछार करने के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। राहत की बात रही कि हादसे के समय फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति फंसा नहीं था। घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना भी नहीं है।

◆ **गारमेंट फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से उठा धुआं, आग बुझाने में जुटी दमकल टीम**

◆ **नोएडा में गारमेंट फैक्ट्री में आग, रूई कपड़े से तेजी से भड़की लपटें**

आग से फैक्ट्री में रखा कपड़ा, रूई, धागा और अन्य सामान प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक तौर पर लाखों रुपये के माल के नुकसान की बात सामने आई है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन फैक्ट्री प्रबंधन और संबंधित विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। दमकल विभाग ने आग बुझाने के बाद फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया। अधिकारियों की ओर से आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का प्रारंभिक कारण बताया गया है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं।

निठारी कांड का राज फिर रहस्य, सुरेंद्र कोली की मौत से सवाल

2006 में सामने आए नरकंकाल कांड की जांच पर उठे सवाल, कोली की मौत से कई अनसुलझे प्रश्न

एजेंसी, नई दिल्ली

बहुचर्चित निठारी कांड एक बार फिर चर्चा में है। मामले के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार को उसके फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना सामने आई। करीब दो दशक पुराने इस मामले में कोली की मौत ने उन सवालों को फिर सामने ला दिया है, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश जांच एजेंसियों और अदालतों के स्तर पर लंबे समय तक होती रही।

निठारी कांड वर्ष 2006 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब नोएडा के निठारी क्षेत्र में नरकंकाल और मानव अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी। मामले की जांच आगे बढ़ने पर सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंधेर के नाम सामने आए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। कई बच्चों के लापता होने और उनके अवशेष मिलने के बाद पुलिस और बाद में सीबीआई ने मामले की जांच की।

निठारी कांड में सामने आए मानव अवशेषों ने मचाई थी सनसनी।

मामले की सुनवाई के दौरान सुरेंद्र कोली को कई मामलों में दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड तक सुनाया गया। लंबे समय तक वह जेल में रहा। हालांकि, बाद की न्यायिक प्रक्रिया में उसकी दोषसिद्धि पर गंभीर सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को सुरेंद्र कोली को भी दोषमुक्त कर दिया था।

इससे पहले मोनिंदर पंधेर को भी अदालत से राहत मिल चुकी थी। दोषमुक्ति के पीछे अदालत के समक्ष साक्ष्यों की कमजोरी अहम रही। इसके बाद निठारी कांड से जुड़े कई सवाल एक बार फिर अनुत्तरित रह गए। जांच के दौरान पुलिस और सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठते रहे।

निठारी कांड के राज फिर गहराए

अब सुरेंद्र कोली की मौत के बाद निठारी कांड से जुड़े सवालों का जवाब मिलना और मुश्किल हो गया है। मामले में जिन घटनाओं को लेकर वर्षों तक जांच और अदालती कार्रवाई चली, उनकी पूरी तस्वीर अब भी स्पष्ट नहीं है। मृतक बच्चों के परिजनों के लिए यह मामला आज भी पीड़ा और न्याय की प्रतीक्षा से जुड़ा हुआ है। कोली की मौत के बाद यह सवाल फिर उठ रहा है कि आखिर उन बच्चों की मौत के पीछे वास्तविक घटनाक्रम क्या था और जांच में सामने आए तथ्यों की पूरी कड़ी क्यों नहीं जुड़ सकी। इससे मामले की पुरानी जांच और साक्ष्यों को लेकर बहस भी फिर तेज हो सकती है।

जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत

एजेंसी, नई दिल्ली। नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मारपीट के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की अदालत ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललर ने 50 हजार रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया। आदेश के बाद भारद्वाज गुरुवार देर रात तिहाड़ जेल से बाहर आया। अदालत ने अंतरिम जमानत के दौरान उसे मामले से संबंधित जानकारी, बचाव रणनीति या शिकायतकर्ता के परिवार के बारे में सामाजिक या अन्य माध्यमों पर चर्चा करने से रोक दिया है। उसे शिकायतकर्ता, उसकी बेटी और गवाहों से संपर्क नहीं करने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने का निर्देश भी दिया गया है।

डूसू चुनाव हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त, बिना नंबर प्लेट गाड़ियों पर पुलिस से मांगा जवाब

एजेंसी, नई दिल्ली

डूसू चुनावों के दौरान हुई कथित हिंसा से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने नॉर्थ कैंपस में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के कथित काफिले को लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल किए। अदालत ने पूछा कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति कैसे मिली। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।

रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसके बाद बेंच ने नॉर्थ कैंपस में चुनाव के दौरान नजर आए बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के काफिले का मुद्दा उठाया। अदालत ने पुलिस की ओर से इस संबंध में दी गई स्थिति पर सवाल करते हुए कहा कि तस्वीरों में दिखाई दे रही गाड़ियों से इनकार नहीं किया जा सकता। बेंच ने यह भी पूछा कि जब मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे, तब ऐसे वाहनों के काफिले को वहां आने की अनुमति कैसे दी गई। डूसू चुनाव के दौरान कथित हिंसा को लेकर दायर याचिका में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की भूमिका से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। इसी क्रम में अदालत ने नॉर्थ कैंपस में वाहनों की आवाजाही और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के कथित काफिले पर पुलिस से जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान अदालत का मुख्य जोर इस बात पर रहा कि चुनाव के दौरान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह लागू की गई और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ऐसे वाहनों को प्रवेश कैसे मिला। अदालत के सवालों के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट मामले में महत्वपूर्ण हो गई है। याचिका पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। अदालत के समक्ष पुलिस की रिपोर्ट और नॉर्थ कैंपस में वाहनों की कथित गतिविधियों से जुड़े पहलुओं पर आगे चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल हाई कोर्ट ने पुलिस से बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के काफिले को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

रोहतक से दिल्ली 63 मिनट में पहुंचा डोनर हार्ट, ग्रीन कॉरिडोर से बची मरीज की जान

एजेंसी, नई दिल्ली

रोहतक से दिल्ली तक 95 किलोमीटर की दूरी डोनर हार्ट ने महज 63 मिनट में तय की। हरियाणा और दिल्ली पुलिस के समन्वय से बनाए गए अंतरराज्यीय ग्रीन कॉरिडोर के जरिए हार्ट को समय पर शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया। गुरुवार शाम रोहतक स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीजीआइएमएस) से हार्ट निकाला गया था।

ग्रीन कॉरिडोर के कारण हार्ट को लेकर चल रहे वाहन को रास्ते में यातायात संबंधी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस ने दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए मार्ग को सुगम रखा। पीजीआइएमएस से रवाना हुआ हार्ट रात 8:43 बजे फोर्टिस अस्पताल पहुंचा। महज 63 मिनट में 95 किलोमीटर का सफर पूरा होने से प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण समय बचाया गया।

फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग में हार्ट प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक तैयारियां की गई थीं। डोनर हार्ट के पहुंचने के बाद चिकित्सकों की टीम ने आगे की चिकित्सा प्रक्रिया शुरू की। प्रत्यारोपण के जरिए गंभीर रूप से बीमार मरीज को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। डोनर हार्ट पहुंचने के बाद मरीज के प्रत्यारोपण की तैयारी पूरी हुई।

हार्ट पहुंचते ही डॉक्टरों ने संभाली कमान

डोनर हार्ट के अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग में चिकित्सकों की टीम पहले से तैयार थी। हार्ट के पहुंचते ही विशेषज्ञों ने आवश्यक चिकित्सकीय जांच और प्रत्यारोपण से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दीं। ग्रीन कॉरिडोर के कारण रोहतक से दिल्ली तक का सफर कम समय में पूरा हो सका। पुलिस की ओर से पूरे मार्ग पर यातायात को सुचारू रखा गया, जिससे हार्ट को ले जा रहे वाहन को कहीं रुकना नहीं पड़ा।

स्वच्छता

महाप्रबंधक ने श्रमदान में भाग लेकर यात्रियों से स्वच्छता में सहयोग की अपील की

रेलवे स्टेशनों पर दो अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान

एजेंसी, नई दिल्ली

रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत दो अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान रेलवे परिसरों की नियमित सफाई के साथ खानपान केंद्रों, पेयजल स्थलों, शौचालयों और यात्रियों के आवागमन वाले अन्य स्थानों की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जहां भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ रखने के साथ यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

महाप्रबंधक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई शपथ : स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत के अवसर पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडेय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके बाद महाप्रबंधक सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर श्रमदान में भाग लिया। उन्होंने स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को स्वच्छता से जुड़े कार्यों को नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान यात्रियों को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

नुक्कड़ नाटक के जरिये दिया स्वच्छता का संदेश : रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। कलाकारों ने प्रस्तुति के माध्यम से स्टेशन परिसर में कूड़ा न फैलाने, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने और स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग देने का संदेश दिया।

यात्रियों की भागीदारी पर दिया गया जोर

महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि यदि यात्रियों में स्वच्छता के संस्कार विकसित किए जाएं तो स्वच्छ भारत के लक्ष्य को और प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाने का भी माध्यम है। अभियान के दौरान रेलवे कर्मचारी, अधिकारी और अन्य संबंधित एजेंसियां मिलकर स्टेशन परिसरों की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, दो अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के दौरान स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी सहित उत्तर रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

न्यूज ब्रीफ

अवैध खनन के खिलाफ नूरपुर पुलिस की कार्रवाई, दो जेसीबी और पांच टिप्पर जब्त

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नूरपुर पुलिस की ओर से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सीआईए नूरपुर की टीम ने चक्की खड्ड क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो जेसीबी मशीनों, एक ट्रैक्टर और पांच टिप्परों को कब्जे में लिया। एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि सीआईए नूरपुर की टीम गश्त और अवैध गतिविधियों की निगरानी पर तैनात थी। इस दौरान कंडवाल स्थित चक्की पुल के समीप चक्की खड्ड में भारी मशीनरी से अनधिकृत खनन किए जाने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और खनन में प्रयुक्त मशीनरी व वाहनों को कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि जब्त सभी वाहन और मशीनरी आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना नूरपुर के सुपुर्द कर दिए गए हैं। संबंधित अधिनियम के तहत चालान और अन्य विधिक प्रक्रियाएं अमल में लाई जा रही हैं। पुलिस ने कहा कि प्राकृतिक संपदा के अवैध दोहन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

पठानकोट में नौकरी का झांसा देकर 1.40 लाख ठगे

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। नौकरी की तलाश कर रहे एक युवक से साइबर ठगों ने ऑनलाइन लिंक के जरिए 1,40,690 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करवाई। इसके बाद साइबर क्राइम थाना पठानकोट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घरथौली मोहल्ला निवासी प्रीतम कुमार के अनुसार वह कार्यालय में मोबाइल पर नौकरी तलाश रहा था। इस दौरान उसने एक ऑनलाइन लिंक खोला। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए आवेदन पूरा करने के लिए पंजीकरण शुल्क जमा करने की बात कही। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने उसके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। लिंक खोलते ही उसके क्रेडिट कार्ड से 1,40,690 रुपए कट गए। पुलिस कॉल डिटेल और बैंक लेनदेन के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। मामले की जांच साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कर रहे हैं।

विद्यार्थियों को करियर, रोजगार, कौशल विकास व सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाखड़ा और नकराणा में करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को करियर विकल्पों, आवश्यक योग्यताओं और संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मैहता ने बताया कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप करियर चुनने में मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों के साथ कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। सत्र में अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, रोजगार, उपभोक्ता मामले, आयुष और यूको आरसेटी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्हें विभागीय सेवाओं, रोजगार संभावनाओं और कौशल विकास की जानकारी देते हुए बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया।

उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डंगार में शुक्रवार को उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक (आईपीएस) ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। दीप प्रज्वलन के बाद उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइबर सुरक्षा तथा सामाजिक मूल्यों पर जानकारी दी। एसपी अभिषेक ने कहा कि वैज्ञानिक सोच केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समस्याओं का तार्किक समाधान तलाशने का माध्यम बननी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से हर बात के पीछे 'क्यों' और 'कैसे' जानने की जिज्ञासा बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज को भी इससे सुरक्षित रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की सीख दी। साइबर अपराधों से बचाव के लिए सोशल मीडिया का सतर्क और सीमित उपयोग करने तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतने का संदेश भी दिया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री 20 से घुमारवीं के प्रवास पर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी 20 से 23 सितंबर तक घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राजेश धर्माणी 20 सितंबर को सुबह 8:30 बजे लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे और दोपहर दो बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं में अंडर-19 जिला स्तरीय मेजर गेम्स के समापन समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शामिल होंगे। 21 सितंबर को वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में जिला स्तरीय अंडर-14 छात्राओं की माइनर गेम्स के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। 22 सितंबर को भराड़ी और 23 सितंबर को दधोल स्कूल में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे।

मारपीट के तीन दोषियों को सात साल की कैद

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर के सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने भोरंज तहसील के मारपीट मामले में तीन दोषियों को सात-सात साल की साधारण कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान अनिल कुमार, विवेक और नीरज, निवासी भोरंज, के रूप में हुई है। मामला 24 जून 2021 की रात का है। कंडयोह में तीनों ने पीड़ितों पर मुक्कों और लकड़ी के डंडों से हमला किया था, जिससे उन्हें चोटें आई थीं। इस संबंध में 25 जून 2021 को भोरंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की पैरवी लोक अभियोजक संदीप अग्निहोत्री ने की। अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों के बयान करवाए। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 323, 325, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराया। धारा 326 के तहत सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा व जुर्माना लगाया गया। अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया।

एनआईटी हमीरपुर को मिले नए बीओजी चेयरमैन

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर सहित देश के 17 एनआईटी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के अध्यक्षों की नियुक्ति न होने के चलते अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 17 सितंबर को राष्ट्रपति के आदेश पर इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार एनआईटी हमीरपुर के बीओजी अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार मिजोरम स्थित एनआईटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन नेओतिया को सौंपा गया है। यह व्यवस्था छह माह या नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक प्रभावी रहेगी। एनआईटी हमीरपुर में नियमित बीओजी अध्यक्ष का पद लंबे समय से रिक्त है। इससे संस्थान से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लंबित बताए जा रहे हैं। एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र एनआईटी है और यहां करीब पांच हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इससे पहले भी संस्थान में कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इस दौरान बीओजी की महत्वपूर्ण बैठकें और बड़े निर्णय नहीं हो सके। इधर, देश के विभिन्न एनआईटी में निदेशक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। वर्तमान निदेशकों का कार्यकाल आगामी फरवरी के आसपास पूरा होने की संभावना है।

सुक्खू सरकार में विकास ठप, भ्रष्टाचार चरम पर और कर्ज का नया रिकॉर्ड : जयराम ठाकुर

कहा- भाजपा सरकार के विकास कार्यों को जनता आज भी याद करती है

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिलाई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार भले ही कांग्रेस की है, लेकिन जनता के जहन में आज भी भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई विकास योजनाओं का ही जिक्र होता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार ने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में कोई नई योजना बनाई ही नहीं, ऐसे में जनता भला क्या याद रखेगी। हम सत्ता में हैं या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में रहना बड़ी बात है। जब हाटी ने रिश्ता जोड़ लिया है तो हम उसे पूरी शिद्दत से निभाएंगे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सुक्खू सरकार काम करने के लिए नहीं, बल्कि बदले की भावना से विकास कार्यों को बंद करने और तालाबंदी करने के लिए जानी जा रही है। सरकार ने बजट प्रावधान और जनता की मांग पर खोले गए लगभग ढाई हजार शैक्षणिक व प्रशासनिक संस्थानों को ताले लटका दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को लगता है कि जब सत्ता में वापस लौटना ही नहीं है तो विकास क्यों कराया जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री सुक्खू केवल भाजपा के गुट गिनते रह गए, जबकि भाजपा ने अपनी विचारधारा के 80 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों को जीत दिलाई और 11 में से 10 जिला परिषदों व तीन नगर निगमों पर परचम लहराया। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया कि चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान खड़गे और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की क्लास ली, जिसमें अपनी विफलता छिपाने के लिए सुक्खू ने मंत्रियों पर कसूर मढ़ा, लेकिन मंत्रियों ने सीधे मुख्यमंत्री को हार का जिम्मेदार ठहराकर उन्हें पद से हटाने तक की सिफारिश कर दी है।

उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना छह राज्यों की सहमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद पूरी हुई, लेकिन सुक्खू जी बिना वजह अपना गुणगान कर रहे हैं। कर्ज के आंकड़ों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पूरे कार्यकाल में मात्र 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था, जिससे लगातार विकास कार्य हुए, लेकिन सुक्खू सरकार ने साढ़े तीन साल में ही 50,000 करोड़ रुपए का नया ऋण लेकर प्रदेश का कुल कर्ज 69,600 करोड़ से सीधे 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपए पहुंचा दिया है, फिर भी ज़मीन पर कोई विकास नजर नहीं आ रहा।

70 एनसीसी कैडेट्स ने गोबिंद सागर में तय की 330 किमी दूरी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। गोबिंद सागर जलाशय में आयोजित 12 दिवसीय 'संकल्प सेलिंग एक्सपेडिशन-2026' का शुक्रवार को लुहणू घाट पर सफलतापूर्वक समापन हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ध्वजारोहण कर अभियान के समापन की घोषणा की। अभियान में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के करीब 70 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। कैडेट्स ने जलाशय में लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय कर साहस, अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना का परिचय दिया।

शिक्षा मंत्री ने कैडेट्स को बधाई देते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कैडेट्स से अभियान के दौरान अर्जित अनुभवों और जीवन मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ वीरभूमि के रूप में भी पहचान मिली है। मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार मेजर धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और मेजर जोरावर सिंह जैसे वीरों का साहस युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। रोहित ठाकुर ने अभियान के दौरान स्वच्छता, नशामुक्ति, टीबी मुक्त भारत, नारी सशक्तिकरण और स्वस्थ समाज का संदेश देने के प्रयासों की सराहना की।

◆ **उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स हुए सम्मानित**

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास के अवसर भी मिलने चाहिए। समापन समारोह में विभिन्न राज्यों के कैडेट्स ने हिमाचली नाटी, हरियाणवी नृत्य और गिद्दा प्रस्तुत कर सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, बंबर ठाकुर, ब्रिगेडियर हरप्रीत सिंह सहित एनसीसी अधिकारी और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

कबड्डी में सिरमौर ने ममलीग को हराकर जीता खिताब

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की में आयोजित तीन दिवसीय राज्यस्तरीय सायरोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हुए।

खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कबड्डी के फाइनल मुकाबले में पुलिस अधीक्षक सोलन एसडी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कबड्डी का फाइनल मुकाबला सिरमौर और ममलीग की टीमों के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में सिरमौर की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ममलीग को हराकर सायरोत्सव कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बैडमिंटन की अंडर-14 प्रतियोगिता में शिमला के गोविंद ने अपने ही जिले के शौर्य को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मंडी की टीम विजेता रही, जबकि अर्की की टीम को उपविजेता के स्थान से संतोष करना पड़ा। शतरंज की अंडर-14 प्रतियोगिता में हर्षित बंसल ने ऋत्विक कौशल को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। शतरंज की ओपन प्रतियोगिता में ममलीग के नितिन शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि सक्षम ठाकुर दूसरे स्थान पर रहे।

◆ **मंडी ने जीता बास्केटबॉल खिताब, अर्की रहा उपविजेता**

महिला रस्साकस्सी प्रतियोगिता में मांगू की टीम ने चईंयाधार की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिताओं के समापन पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कश्यप ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों व टीमों को नकद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बखालग के प्रधान सुरेंद्र पाठक और भूमती पंचायत के उपप्रधान विनय शर्मा मौजूद रहे। खेल समिति के सदस्य संजय ठाकुर, भीम सिंह ठाकुर, ओम प्रकाश भारद्वाज, भास्कर ठाकुर, रमन कंवर, हेमंत पाठक, नागेश शर्मा, नवनीत महाजन, जोगिंदर, धर्मदत्त, किशोरीलाल, रेणु बाला और नीमा शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। तीन दिवसीय सायरोत्सव में खेल प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला।

अगले एक वर्ष में 100 से अधिक कोच नियुक्त करेगा हिमाचल ओलंपिक संघ : अनुराग ठाकुर

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, सांसद तथा हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित 'जज्बा: जड़ों से शिखर तक' कॉन्क्लेव में भारत के खेल तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2036 ओलंपिक में भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ खेल महासंघों, कॉरपोरेट क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा।

ठाकुर ने कहा कि खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनके निरंतर विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र खेल विभाग, समर्पित सचिव और अलग बजट व्यवस्था की आवश्यकता बताई। उन्होंने खेल बजट को आधारभूत ढांचे, कोचिंग और घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए अलग-अलग निर्धारित करने का सुझाव दिया। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ की पहल की जानकारी देते हुए अनुराग ने कहा कि अगले एक वर्ष में विभिन्न खेलों के 100 से अधिक कोच नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही विश्वस्तरीय कोच, खेल विज्ञान विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण देना जरूरी है। 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में शुरुआती स्तर पर प्रतिभा पहचान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य, महासंघ, कॉरपोरेट और स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वित प्रयास से मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सकता है।

निरमंड में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। थाना निरमंड के अंतर्गत सेरी के पास वीरवार देर रात एक ऑल्टो कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार दुराह की ओर आ रही थी। इसी दौरान सेरी के पास एक मोड़ पर चालक ने कार पर नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित होकर कार सड़क से नीचे गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी कुल्लू अभिषेक शेखर ने बताया कि हादसे में हरि सिंह निवासी गांव शाह, ग्राम पंचायत लोट और श्याम लाल निवासी गांव डवार्च, ग्राम पंचायत दुराह, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू की मौत हुई है।

प्रेस क्लब भवन व घुमारवीं केंद्रीय विद्यालय के निर्माण कार्यों को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। डीसी राहुल कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बचत भवन में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण, जल शक्ति, सूचना एवं जनसंपर्क, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि बिलासपुर जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को भवन निर्माण से संबंधित आगामी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय भवन के निर्माण के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। संबंधित विभागों को निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

बैठक में एम्स कोठीपुरा में ट्रांसमिशन लाइन निर्माण से संबंधित एफसीए मामले की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी विभागों को एफसीए मामलों में आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार करने और स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर सहित वन, शिक्षा, जल शक्ति, लोक निर्माण, पुलिस और उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

महिलाओं को वित्तीय योजनाओं की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सौली खड्ड की ओर से नाबार्ड के सौजन्य से गांव नेला में एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शाखा प्रबंधक अनिल धरवाल ने महिलाओं को बैंक की विभिन्न बचत और ऋण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नई महिला सशक्तिकरण ऋण योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए महिलाओं से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता व लाभों की जानकारी दी। महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग के फायदों तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के प्रति भी जागरूक किया गया। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल लेन-देन करने और किसी अनजान व्यक्ति से बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करने की सलाह दी। इस दौरान महिलाओं की बैंकिंग संबंधी शंकाओं का समाधान भी किया गया।

विज्ञान केवल प्रयोगशाला और किताबों तक सीमित नहीं : केवल सिंह पठानिया

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में आयोजित की जा रही दो दिवसीय 33वें उपमंडल स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का शुभारंभ शुक्रवार को शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने किया।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नन्हे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों से संवाद कर उनके प्रयोगों एवं मॉडलों के बारे में जानकारी ली। प्रतियोगिता में शाहपुर उपमंडल के 52 मिडल, दसवीं एवं जमा दो स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला और किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घर, विद्यालय, खेत, जंगल, नदियों और पूरे प्राकृतिक वातावरण में मौजूद है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य में जैव विविधता, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन और सतत विकास जैसे अनेक विषयों पर सीखने और शोध करने के व्यापक अवसर हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि बच्चों को दिशा देने वाले मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत भी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर, शोधकर्ता और राष्ट्र निर्माता बनेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की छोटी-सी खोज भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने अध्यापकों से विद्यार्थियों को नवीं और दसवीं कक्षा से ही करियर संबंधी मार्गदर्शन देने का आग्रह किया, ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विषयों के चयन में सुविधा मिले और वे अपने लक्ष्य की ओर बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकें। उन्होंने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में एसडीएम शाहपुर गणेश ठाकुर एटीसी प्रभारी एवं वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुनंदा पठानिया सहित प्रवक्ता एवं अध्यापक वर्ग, बच्चों के अभिभावक, स्कूली विद्यार्थी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री आज अर्की के प्रवास पर

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 19 सितम्बर को सोलन जिला के अर्की के प्रवास पर आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू 19 सितम्बर को शाम अर्की विधानसभा क्षेत्र के चौगान मैदान स्थित ऐतिहासिक काली माता मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। उसके बाद वह चौगान मैदान से ही सरयांज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंडी के खेल मैदान का लोकार्पण करेंगे।

सुक्खू चौगान मैदान से ही कुनिहार में फल व सब्जी उप यार्ड तथा दाड़लाघाट स्थित आई.एस.बी.टी. बस अड्डे का लोकार्पण भी करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू दानोघाट साहजादा से नेरी प्लाटा सम्पर्क मार्ग, सिनटीघाट से बानधार एंबुलेंस मार्ग की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री तदोपरांत मांगू स्थित 33 के.वी. जी.आई.एस. विद्युत उप केन्द्र ग्याणा तथा 33 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके उपरांत राज्य स्तरीय सायर मेला समापन समारोह में मुख्यातिथि होंगे।

साक्षरता में दूसरे स्थान पर हिमाचल का गौरव अब 100 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य : शांता

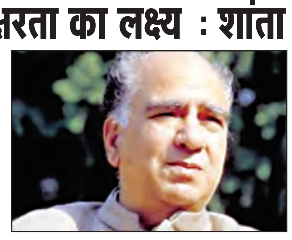

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि साक्षरता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल करना प्रदेश के लिए गौरव और प्रसन्नता की बात है।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार और जनता को बधाई दी। शांता कुमार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि देश में साक्षरता दर 99.5 प्रतिशत हो गई है, जबकि गोवा 99.7 प्रतिशत साक्षरता के साथ प्रथम स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश को साक्षरता के क्षेत्र में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला पहाड़ी और सीमांत प्रदेश है। प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों में आज भी सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगों को पैदल आवागमन करना पड़ता है। इसके अलावा प्रदेश की सीमाएं चीन से लगती हैं तथा लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे कठिन एवं सीमांत क्षेत्र भी हिमाचल का हिस्सा हैं। शांता कुमार ने कहा कि इन तमाम भौगोलिक एवं कठिन परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने साक्षरता के क्षेत्र में देश के अधिकांश राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गर्व की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि प्रदेश शीघ्र ही 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश भविष्य में गोवा को पीछे छोड़कर देश में साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल करेगा।

◆ **दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद साक्षरता में हिमाचल दूसरे पायदान पर**

भाजपा जिला अध्यक्ष सिरमौर विनय गुप्ता का निधन, बिंदल सहित नेताओं ने जताया शोक

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। सिरमौर भाजपा के वरिष्ठ एवं समर्पित नेता विनय गुप्ता के निधन से समूचा भाजपा परिवार शोकाकुल है। आज नाहन में उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप, ,भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं नगरजनों ने अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।भाजपा की ओर से दिवंगत विनय गुप्ता जी के पार्थिव शरीर को पार्टी के झंडे में लपेटकर उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान वातावरण अत्यंत भावुक हो गया और उपस्थित सभी लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय साथी को अंतिम विदाई दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि विनय गुप्ता का निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना जीवन संगठन और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। वे सरल, सहज, मिलनसार एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे और कार्यकर्ताओं के साथ उनका आत्मीय संबंध सदैव स्मरण किया जाएगा।

बीडीटीएस हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, मांगों पर अड़े ट्रक ऑपरेटर

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बरमाणा। बरमाणा सीमेंट संयंत्र में सीमेंट ढुलाई से जुड़े बीडीटीएस सदस्यों की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के मंच से ट्रक ऑपरेटरों ने एसीसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग उठाई।

बीडीटीएस प्रधान जीतराम गौतम ने कहा कि गुरुवार को एसीसी प्रबंधन के साथ बातचीत हुई है। प्रबंधन ने बताया कि बंद संयंत्र को चालू कर दिया गया है और करीब 72 घंटे में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटरों के तीन प्रमुख मुद्दे हैं। इनमें पांच वर्षीय ढुलाई समझौते का नवीनीकरण, बंद संयंत्र में उत्पादन शुरू कर ढुलाई का काम बढ़ाना तथा अप्रैल से लंबित वार्षिक बढ़ोतरी शामिल है। गौतम ने कहा कि मांगों को लेकर प्रबंधन से कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठोस समाधान नहीं निकला। कंपनी के सीईओ के विदेश से लौटने के बाद लंबित मुद्दों पर बातचीत का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सोमवार या मंगलवार तक सकारात्मक पहल नहीं हुई तो एसीसी गेट पर धरना देने का निर्णय लिया जा सकता है।

पूर्व बीडीटीएस अध्यक्ष लेखराम वर्मा ने कहा कि 21 निर्वाचित प्रतिनिधि ऑपरेटरों के हितों के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने प्रबंधन और बीडीटीएस के बीच वार्ता के माध्यम से समाधान की मांग की। साथ ही जिला प्रशासन से मध्यस्थता कर विवाद सुलझाने का आग्रह किया। इस दौरान महासचिव प्रदीप ठाकुर, सुरेश चौधरी समेत कई ट्रक ऑपरेटर मौजूद रहे।

न्यूज ब्रीफ

इंदौरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के 37 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। बाल विकास परियोजना अधिकारी, इंदौरा के कार्यालय की ओर से उपमंडल इंदौरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 9 तथा सहायिकाओं के 28 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 14 अक्तूबर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडिंग क्षेत्र से ही स्वीकार किए जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा अंतिम तिथि तक आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। दोनों पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास या समकक्ष निर्धारित की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पद ढांगू, बसंतपुर, उलेहरियां, मझवाह, सिरत, वाई अटरियां, डगाला और तड़ियां चमारा सहित विभिन्न केंद्रों में हैं। वहीं सहायिकाओं के पद भदरोया, डमटाल, गंगवाल, मलाहड़ी, मोहटली, सूरजपुर, चन्होड़, मण्डोली, मंगवाल, भलाख, अटाहड़ा, ठाकुरद्वारा, टप्पा, इंदौरा कॉलोनी सहित अन्य केंद्रों में रिक्त हैं। साक्षात्कार की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के गुर सीख 100 विद्यार्थियों ने बढ़ाया आत्मविश्वास

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के करियर काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल की ओर से विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए विशेष करियर परामर्श सत्र आयोजित किया गया। 'सिविल्सटैप आईएएस अध्ययन केंद्र' चंडीगढ़ व शिमला के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सिविल्सटैप आईएएस के विशेषज्ञ रवि आर्यन और तरुण ने विद्यार्थियों को स्नातक के बाद उपलब्ध अवसरों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध रणनीति के साथ तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी शंकाओं का समाधान भी प्राप्त किया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने विद्यार्थियों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया। इस दौरान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें मीनाक्षी, मधुबाला, आभा चंदेल, दीपिका, रितिका, आयुषी, तेजस्विनी शर्मा और यश गौतम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कई शिक्षक मौजूद रहे।

1044 विद्यार्थियों को बांटी कृमिनाशक दवाइयां

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में स्वास्थ्य विभाग, बीएमओ घुमारवीं और कॉलेज के स्वास्थ्य जागरूकता व नशा निरोधक प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में डी-वर्मिंग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृमि संक्रमण से बचाव, स्वच्छता और स्वस्थ खान-पान के प्रति जागरूक करना रहा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉलेज परिसर में 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को कृमिनाशक दवाइयां वितरित कीं। इस दौरान कुल 1044 विद्यार्थियों को दवा दी गई, जिनमें 422 छात्र और 622 छात्राएं शामिल रहीं। स्वास्थ्य कर्मियों ने विद्यार्थियों को दवा के सेवन और व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर आवश्यक जानकारी भी दी। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. जीवेश नड्डा रहे। आयोजन में डॉ. बसु देव, डॉ. अंजना, प्रो. राकेश, डॉ. आदर्श और प्रो. अमरपाल सहित शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने सहयोग किया। कॉलेज प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने स्वास्थ्य विभाग और बीएमओ टीम का आभार जताया।

यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे व्यापारी

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला व्यापार मंडल हमीरपुर ने प्रस्तावित यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क/एमडीआर के विरोध में बड़ा निर्णय लिया है। व्यापार मंडल ने कहा कि यदि 15 अक्तूबर 2026 से पहले सरकार अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं लेती है, तो जिले के व्यापारी 15 अक्तूबर के बाद यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। व्यापार मंडल के अनुसार महंगाई, ऑनलाइन कारोबार और बढ़ती लागत के कारण व्यापारी पहले ही आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में एमडीआर के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी का अतिरिक्त भार व्यापारियों पर पड़ेगा। व्यापार मंडल ने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए शुल्क वापस लेने की मांग की। व्यापार मंडल का कहना है कि यूपीआई शुरू करते समय शुल्क नहीं लगाने की बात कही गई थी, जिसके चलते व्यापारियों ने इसके प्रचार-प्रसार में सहयोग दिया। अब शुल्क लगाने से व्यापारी और उपभोक्ता दोनों प्रभावित होंगे। संगठन ने आरोप लगाया कि इसका अंतिम भार ग्राहकों पर पड़ सकता है। व्यापार मंडल ने बताया कि एमडीआर के विरोध में जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बैठकों का दौर जारी है तथा आंदोलन की रूपरेखा जल्द तय की जाएगी।

पंचायतों में तकनीकी सहायकों, जेई व रोजगार सेवकों के पद रिक्त, विकास कार्य प्रभावित

भारतेन्दु संवाददाता, सितंबर। जिला की 182 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की भारी कमी ग्रामीण विकास कार्यों में बाधा बन रही है। हाल ही में चुने गए पंचायत प्रधानों को पर्याप्त स्टाफ न मिलने से विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें धरातल पर उतारने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सचिव, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवकों के कई पद रिक्त होने से मनरेगा सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की गति प्रभावित हुई है। पंचायत प्रधान संघ विकास खंड घुमारवीं के अध्यक्ष देश राज शर्मा ने कहा कि एक-एक कर्मचारी को पांच से छह पंचायतों का अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को प्रमाणपत्र बनवाने और योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन के लिए भी कई सप्ताह इंतजार करना पड़ रहा है। संघ ने सरकार से रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 93,508 बच्चों को खिलाई कृमिनाशक दवा

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जिला बिलासपुर में 1 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। अभियान के तहत जिले के 846 सरकारी विद्यालयों, 161 निजी विद्यालयों और 1,113 आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 93,508 बच्चों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया था। अभियान के दौरान करीब 98 प्रतिशत बच्चों को दवा खिलाई गई। जो बच्चे अभियान के दौरान दवा लेने से वंचित रह गए हैं, उन्हें मॉप-अप राउंड के दौरान दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाव के उपायों, स्वच्छता और नियमित रूप से हाथ धोने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। विभाग ने अभिभावकों से बच्चों के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की।

बिलासपुर में मारपीट, सड़क हादसे और रास्ता रोकने पर तीन केस दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटों में मारपीट, सड़क हादसे व सार्वजनिक मार्ग बाधित करने के मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग अभियोग दर्ज किए हैं। थाना तलाई के तहत बरठीं निवासी अर्जुन सिंह की शिकायत पर बेटे, बहू और पत्नी के खिलाफ गाली-गलौज व मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। सदर थाना क्षेत्र में बॉयज स्कूल के पास थ्री-व्हीलर और बाइक की टक्कर के मामले में चालक राजपाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार चालक ने आवारा बैल से बचने के दौरान वाहन गलत दिशा में मोड़ दिया था, जिससे बाइक सवार घायल हुआ। वहीं, एम्स कोठीपुरा के पास सार्वजनिक सड़क पर रेहड़ी लगाकर रास्ता बाधित करने पर अमित चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि तीनों मामलों में नियमानुसार आगामी कार्रवाई जारी है।

हिमाचल में सितंबर में अक्तूबर जैसी ठंड

5 शहरों का तापमान 10°C से नीचे गिरा, केलांग का 3.8°C तक लुढ़का

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के 2 शहरों का पारा 5 डिग्री से कम और 5 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर चुका है। केलांग का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री तक लुढ़क गया है।

वीरवार को लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। इससे ऊंचे क्षेत्रों में सुबह-शाम और रात के समय ठंड में इजाफा हुआ है। राहत की बात यह है कि शुक्रवार को राज्य के ज्यादातर भागों में सुबह से ही अच्छी धूप खिली रही। इससे ऊंचे क्षेत्रों में लोगों ने ठंड से राहत की सांस ली है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। कई शहरों का पारा बीते 24 घंटे में 5 से 8 डिग्री तक नीचे गिरा है। कल्पा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 8.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के बाद अधिकतम तापमान अब 14.2 डिग्री रह गया है। मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी कर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर, मंडी, शिमला और लाहौल स्पीति जिला के कुछेक स्थानों पर शाम 6 बजे तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। IMD के अनुसार, 19 सितंबर से मानसून कमजोर पड़ेगा। इसके बाद 22 सितंबर तक ज्यादातर भागों में धूप खिलेगी। इस दौरान इक्का-दुक्का स्थानों पर ही हल्की बारिश की संभावना है।

सुबह-शाम व रात को बढ़ी ठंड

इसी तरह, ताबो का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री गिरने के बाद 3.9 डिग्री सेल्सियस रह गया है। भुंतर का अधिकतम तापमान 7.5 डिग्री गिरकर 24.1 डिग्री, ताबो में 7.1 डिग्री गिरकर 18.5 डिग्री और मंडी में 6 डिग्री गिरकर 26.6 डिग्री सेल्सियस रह गया। राजधानी शिमला में भी अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री गिरने के बाद 21.5 डिग्री सेल्सियस रह गया है। अन्य शहरों में भी अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। इससे सुबह-शाम और रात के वक्त पहाड़ों पर ठंडक बढ़ी है।

मानसून में सामान्य से 10% कम बारिश

हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश हुई है। जिलावार स्थिति देखें तो चंबा में सामान्य से 5% कम, हमीरपुर में 31% कम, कांगड़ा में 4% कम, लाहौल-स्पीति में 64% कम, मंडी में 13% कम, सोलन में 13% कम और ऊना में 1% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं, बिलासपुर में सामान्य से 11% ज्यादा, किन्नौर में 3% अधिक, कुल्लू में 7% अधिक, शिमला में 15% अधिक और सिरमौर में 7% अधिक बारिश हुई है। बारिश-बाढ़ और लैंडस्लाइड से 3,212 करोड़ की सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान हुआ है।

दो साल बाद फिर सजी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, 596 विद्यार्थियों ने लिया भाग

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय औंध, नूरपुर में 33वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का उपमंडल स्तरीय आयोजन किया गया। दो वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में नूरपुर, इंदौरा और फतेहपुर उपमंडलों के 106 विद्यालयों से 596 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया। आयोजन में 100 एस्कॉर्ट शिक्षक और 17 रिसोर्स पर्सन भी शामिल रहे।

मुख्यातिथि तहसीलदार नूरपुर राधिका सैनी ने बाल वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान को केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान की शुरुआत बच्चे के मन में उठने वाले सवाल से होती है। विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, एयरोस्पेस, जैव प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों की जानकारी हासिल करने के लिए प्रेरित किया। राधिका सैनी ने कहा कि बच्चों के सवालों को दबाने के बजाय उनकी जिज्ञासा को सही दिशा देना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने और प्रयोग के माध्यम से सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और नई चीजें खोजने के पर्याप्त अवसर देने का आग्रह किया। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों को केवल अच्छे अंक और परीक्षा की प्रतिस्पर्धा तक सीमित न रखने की अपील की। घर और विद्यालय का सहयोग बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नूरपुर, इंदौरा और फतेहपुर जैसे क्षेत्रों के विद्यालयों से भी भविष्य के वैज्ञानिक तैयार हो सकते हैं। दो वर्ष बाद हुए आयोजन में विद्यार्थियों की बड़ी भागीदारी और उत्साह देखने को मिला।

संजय अवस्थी ने सायरोत्सव की प्रथम सांस्कृतिक संध्या का किया शुभारंभ

388 वर्षों पुरानी परंपरा का प्रतीक है सायरोत्सव

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राज्य स्तरीय सायरोत्सव मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले और त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन के परिचायक हैं। इनके माध्यम से समाज में आपसी मेल-जोल बढ़ता है और लोगों को अपनी लोक संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलता है।

संजय अवस्थी ने क्षेत्रवासियों को राज्य स्तरीय सायरोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी पुरातन परंपराओं को संजोकर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेलों और त्योहारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अर्की का सायरोत्सव बेहद प्राचीन है और करीब 388 वर्षों से मनाया जा रहा है। आज भी यह मेला क्षेत्र के लोगों की आस्था और परंपरा का प्रमुख प्रतीक बना हुआ है। विधायक ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रथम सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गायक गौरव कौंडल, हेमंत शर्मा, काकू ठाकुर सहित अन्य स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे। इस अवसर पर विधायक की धर्मपत्नी मीनाक्षी अवस्थी, खंड कांग्रेस अर्की अध्यक्ष सतीश कश्यप, नगर पंचायत अर्की अध्यक्ष सीमा शर्मा, पार्षदगण, अडानी सीमेंट संयंत्र के मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार, उपमंडलाधिकारी अर्की निशांत तोमर, उप पुलिस अधीक्षक दाड़लाघाट नवीन झालटा, उप पुलिस अधीक्षक सोलन अशोक चौहान, तहसीलदार अर्की विपिन वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

स्मॉल हाइव बीटल से मधुमक्खियों को बचाने के लिए मौन पालकों को किया गया जागरूक

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। उद्यान विभाग के एपीकल्चर उत्तरी क्षेत्र कांगड़ा की ओर से मधुमक्खी पालकों को स्मॉल हाइव बीटल से होने वाले नुकसान और इसकी रोकथाम के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सहौड़ा में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 85 मौन पालकों ने भाग लिया। शिविर में जिला परिषद सदस्य विजय कुमार उर्फ वीजू और पंचायत प्रधान समीर सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने मौन पालकों को स्मॉल हाइव बीटल की समस्या, इससे मधुमक्खियों और शहद को होने वाले नुकसान तथा रोकथाम के प्रभावी उपायों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस कीट के कारण मौन पालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसके नियंत्रण के लिए अभी ऐसी कोई दवा निर्धारित नहीं है, जिसका मधुमक्खियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अधिकारियों ने मौन पालकों को बिना विशेषज्ञ सलाह के कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि कीटनाशक मधुमक्खियों के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। विभाग ने स्मॉल हाइव बीटल की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है और मौन पालकों से दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। शिविर में संयुक्त निदेशक उद्यान डॉ. कमलशील नेगी, उप निदेशक डॉ. अलक्ष पठानिया, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. निशा कुमारी मेहरा और उद्यान विकास अधिकारी डॉ. राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

युवा नशे से दूर रहकर देश की अमूल्य विरासत को रखें सुरक्षित

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तत्वावधान में चलाए जा रहे 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के तहत वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डीएसपी दिनेश कुमार ने युवाओं को साथियों के दबाव से बचने और नशे से दूर रहने के उपाय बताए। उन्होंने विद्यार्थियों से अच्छे साथियों का चयन करने तथा नशे के लिए प्रेरित करने वालों का दृढ़ता से विरोध करने का आह्वान किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि युवा देश की अमूल्य विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रभारी सुनील कुमार, सुरेश कुमार, डॉ. रतन ठाकुर, डॉ. चमन, लेफ्टिनेंट डॉ. बलबीर सहित अन्य उपस्थित रहे।

शिक्षकों को आधारभूत साक्षरता व संख्याज्ञान का दिया प्रशिक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। शिक्षा खंड अर्की के बीआरसी परिसर में निपुण भारत कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय आधारभूत साक्षरता व संख्याज्ञान क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यशाला का शुभारंभ प्राथमिक शिक्षा खंड अधिकारी सीमा बाला ने किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रदेशभर में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम सामग्री, निपुण लक्ष्यों और निपुण आधारित कक्षा संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। कार्यशाला के दूसरे दिन गुणवत्ता शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से राजकुमार शर्मा ने भी प्रशिक्षण में भाग लिया।

उन्होंने कहा कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान विकसित करने में ऐसे प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं। मुख्य संसाधन व्यक्तियों योगिता, दीपिका शर्मा और अरुण ठाकुर ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने और प्रभावी शिक्षण-अधिगम गतिविधियों को कक्षा में अपनाने की व्यावहारिक जानकारी दी गई।

भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का जिला अधिवेशन 15 अक्तूबर के बाद

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला हमीरपुर की बैठक जिला संयोजक सतीश गौतम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों और आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई संदेश के साथ हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकोष्ठ का जिला अधिवेशन 15 अक्तूबर के बाद आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन की तैयारियों का जिम्मा जिला से मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सौंपा जाएगा। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी वर्ग के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। बैठक के अंत में सदस्यों ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में शंभू राम, बलबीर सिंह, बलदेव कपूर, देशराज भरवल, प्रवीण बेदी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

रैल में जन स्वास्थ्य शिविर के दौरान तीन हजार से अधिक लोगों का किया चैकअप

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा वीरवार को गांव रैल में शुरू किए गए जन स्वास्थ्य शिविर में चैकअप के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने बताया कि इस शिविर में लगभग 3025 लोगों का चैकअप किया गया।

उन्होंने बताया कि गाइनी यानि स्त्री रोग विभाग की ओपीडी में सर्वाधिक 348 महिलाओं ने चैकअप करवाया। जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञों ने 323, ऑरथो यानि हड्डी रोग के विशेषज्ञों ने 255, हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 211 और गैस्ट्रोएंटोलॉजी के विशेषज्ञों ने 190 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इसी प्रकार नेत्र रोग विशेषज्ञों ने 168, ईएनटी यानि कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञों ने 140, त्वचा रोग के विशेषज्ञों ने 131, बाल रोग 25, डेंटल 24, न्यूरोलॉजी 55, सर्जरी 46, पुलमोनोलाजी एवं छाती के रोग 35, एंडोक्राइनोलॉजी 61, नैफ्रोलॉजी 30, अन्य सुपर स्पेशियलिटी 63 और मनोचिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 10 लोगों की जांच की। स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कालेजों के 9 सुपर स्पेशलिस्ट, 12 स्पेशलिस्ट और 10 अन्य डॉक्टरों ने कुल मिलाकर 2115 लोगों की जांच की। इनके अलावा आयुष विभाग के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 910 लोगों की जांच की। जिला आयुष अधिकारी डॉ. तनूजा नागपाल ने बताया कि आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों ने 607 लोगों, होम्योपैथी के विशेषज्ञों ने 156 और योग एवं नेचुरोपैथी के विशेषज्ञों ने 42 लोगों का चैकअप किया। इस दौरान कपिंग क्रिया से 40 लोगों, अग्निकर्म 12, जलनेति 4, मर्म 20, जानवस्ति 10, कटिवस्ति 7, जलोका 2 और शिरोधारा क्रिया से 3 लोगों का उपचार किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शिविर में 5402 लोगों के विभिन्न प्रकार के टैस्ट भी किए गए। इनमें 87 लोगों के अल्ट्रासाउंड, 423 के शुगर टेस्ट, 1780 के एचबी टैस्ट, 73 के ईसीजी, 2414 की अन्य लैब जांच और 423 लोगों का बीएमआई और अन्य टैस्ट शामिल हैं। 63 महिलाओं की ब्रैस्ट कैंसर जांच और 24 लोगों की ओरल कैंसर की जांच भी की गई। लगभग 1635 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी प्रदान किया गया। 2 लोगों के मौके पर ही आयुष्मान कार्ड और 2 लोगों की आभा आईडी भी मौके पर ही बनाई गई। जबकि, 2 लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन का टीका भी लगाया गया।

नाराजगी खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत से मांगा समाधान

घुरकड़ी में तीन माह से बंद स्ट्रीट लाइटें, ग्रामीण परेशान

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। ग्राम पंचायत घुरकड़ी में पिछले करीब तीन माह से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के विभिन्न वार्डों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद हैं, जिससे रात के समय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत से खराब लाइटों की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार पिछली पंचायत के कार्यकाल में लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं, अब इनमें से कई लाइटें खराब हो चुकी हैं। उनका कहना है कि पूर्व पंचायत के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों का रखरखाव और उन्हें सुचारू रखना वर्तमान पंचायत की जिम्मेदारी है। ऐसे में खराब लाइटों की मरम्मत के लिए जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड नंबर एक में पहले से ही कम संख्या में स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। इनमें से भी अधिकांश के बंद होने से पूरे वार्ड में रात के समय अंधेरा छाया रहता है। इससे लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवाजाही में दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब खराब स्ट्रीट लाइटों का मामला पंचायत के समक्ष उठाया जाता है तो पिछली पंचायत द्वारा लगाई गई लाइटों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों पर राजनीति करने के बजाय पहले से उपलब्ध सुविधाओं को सुचारू करना जरूरी है।

उन्होंने पंचायत से खराब लाइटों का सर्वे करवाने, मरम्मत योग्य लाइटों को ठीक करवाने और खराब हो चुकी लाइटों के स्थान पर नई लाइटें लगाने की मांग की है।

वहीं, इस संबंध में पंचायत प्रधान उमेश दीक्षित ने कहा कि पिछली पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कहा कि पंचायत बदलने के बाद इनमें से कई लाइटें खराब हो गईं। उन्होंने बताया कि खराब लाइटों की पूरी जानकारी तैयार कर संबंधित स्तर पर भेज दी गई है। जल्द ही नई व्यवस्था के तहत स्ट्रीट लाइटें लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि पंचायत जल्द कार्रवाई कर समस्या का समाधान करेगी। उनका कहना है कि गांव में विकास कार्य करवाने के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधाओं का नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उनका लाभ लगातार मिलता रहे।

3100 दीयों की रोशनी से पीएम मोदी को जन्मदिवस की बधाई

भारतेन्दु संवाददाता, शाहपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शाहपुर में भाजपा जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री कमल कुमार शर्मा की अगुवाई में 3100 दीये जलाकर उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गईं।

इस दौरान दीयों की रोशनी के माध्यम से प्रधानमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की गई और राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कमल कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, आधुनिक बुनियादी ढांचे, मेक इन इंडिया, कौशल विकास, किसान कल्याण और गरीबों के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों से देश की विकास यात्रा को गति मिली है।

उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, विनिर्माण, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, रक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को भी उन्होंने विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। कमल शर्मा ने कहा कि 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य में आत्मनिर्भरता, नवाचार, युवाशक्ति, महिला सशक्तिकरण व किसान कल्याण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 3100 दीयों की रोशनी विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है।

गोल्फर लूसी खूबसूरत अंदाज में

30 साल की गोल्फर लूसी रॉबसन को गोल्फिंग स्किल्स और उनके खूबसूरत लुक्स के कारण फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण ही इंस्टाग्राम में उनके लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। गोल्फर होने के साथ ही साथ वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं।

एशियन गेम्स: भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में

जापान को 8 विकेट से हराया; शेफाली के 40 रन, श्री चरणी को 4 विकेट

एजेंसी, निशिन

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और बायें हाथ की स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर पिछली चैम्पियन भारतीय टीम ने अनुभवहीन जापान को शुक्रवार को आठ विकेट से हराकर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रवासी नेटवर्क जुड़ें।

श्री चरणी ने 10 रन देकर चार विकेट लिए, जो टी20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर दो विकेट चटकाए। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर आउट हो गई। भारत ने यह लक्ष्य पांच ओवर में हासिल कर लिया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। शेफाली ने 15 गेंद में नाबाद 40 रन बनाये जबकि रिचा घोष ने छह गेंद में 12 रन का योगदान दिया। जापान ने सलामी बल्लेबाज जी कमलिनी की और तीसरे नंबर पर उतरी भारती फुलमाली को आउट किया। इससे पहले श्री चरणी की अगुवाई में भारत के अनुभवी स्पिनरों ने जापानी बल्लेबाजों की अनुभवहीनता का पूरा फायदा उठाते हुए उन्हें 57 रन पर आउट कर दिया।

पहले गेंदबाजी का फैसला करने वाली भारतीय टीम ने जापान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने ही नहीं दिये और पूरी पारी में सिर्फ तीन चौके लगे। जापान के बल्लेबाजों को शीर्ष टीमों से खेलने या नियमित अभ्यास का मौका नहीं मिलता है और उनके लिये टर्न और

सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी भारतीय टीम

उछाल लेती पिच पर भारत के गेंदबाजों का सामना कर पाना काफी मुश्किल था। पावरप्ले में 24 रन ही बने, जिसमें दो चौके लगे। श्री चरणी ने सलामी बल्लेबाज हारूना इवासाकी (10) और कक्षान माइ यानागिडा को लगातार दो गेंदों पर पवेलियन भेजा। शेफाली ने 15वें ओवर में अयाका काती और 17वें ओवर में शिमाको काते के विकेट लिए। कुछ बल्लेबाज रन आउट भी हुए, जिससे जापान की मुश्किलें और बढ़ गई।

भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में रविवार को बांग्लादेश से भिड़ेगी, जबकि इसी दिन पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा।

बिचू देवी और रहमान को एफआईएच विश्व कप 'मैजिक स्किल' पुरस्कार

एजेंसी, लुसाने

भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर बिछू देवी खारीबम और पाकिस्तान के स्ट्राइकर अब्दुल रहमान ने हाल ही में नीदरलैंड और बेल्जियम में हुए एफआईएच विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए 'पोलिग्रास मैजिक स्किल' पुरस्कार जीते। विजेताओं का चयन प्रशंसकों के वोट के आधार पर किया गया। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के पलों के आधार पर नामांकन तय किये गए थे। यह पुरस्कार एफआईएच के वैश्विक सप्लायर पोलिटन द्वारा दिया जाता है। बिछू को इंग्लैंड के खिलाफ पूल चरण के मैच में आखिरी तीस सेकंड में शानदार तरीके से गोल बचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह मैच ड्रॉ रहा और इसके आधार पर भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। भारतीय टीम विश्व कप में पांचवें स्थान पर रही जो 1974 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बिछू को 52 प्रतिशत वोट मिले।

पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के रहमान को उसके शानदार 3डी कौशल के लिये यह पुरस्कार मिला जिन्होंने वेल्स के खिलाफ चार डिफेंडरों के बीच से गेंद को निकालकर गोल किया था। रहमान को 44 प्रतिशत वोट मिले। दक्षिण कोरिया के केंटिन मेलविले को 39 प्रतिशत वोट मिले।

स्पोर्ट्स विंडो

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के कोच बेन सॉयर का कार्यकाल समाप्त

एजेंसी, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने महिला टीम की मुख्य कोच बेन सॉयर के अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। चार साल तक टीम की जिम्मेदारी संभालने वाले सॉयर का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक था, लेकिन महिला क्रिकेट की उच्च प्रदर्शन संरचना की व्यापक समीक्षा के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बदलाव का निर्णय लिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, समीक्षा में महिला टीम के लिए एक नई 'परफॉर्मेंस लीड' भूमिका की जरूरत सामने आई है। इसके अलावा, रैचल पेटिट के पास मौजूद मैनेजर का पद भी समाप्त कर दिया गया है। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए अंतरिम मुख्य कोच और परफॉर्मेंस मैनेजर टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्थायी मुख्य कोच और परफॉर्मेंस लीड के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए न्यूजीलैंड टीम की घोषणा अक्टूबर की शुरुआत में की जाएगी। सॉयर ने जून 2022 में न्यूजीलैंड महिला टीम की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके कार्यकाल में टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता और सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में 2024 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया। जॉर्जिया प्लिमर, ईडन कार्सन और इज़ी गेज जैसी युवा खिलाड़ियों ने भी सॉयर के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा बनीं।

इंग्लैंड के जोस बटलर टी-20 में 15,000 रन बनाने पहले बल्लेबाज

एजेंसी, लंदन। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर टी-20 क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

36 साल के बटलर ने वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ा। पोलार्ड के नाम 14,994 रन हैं। बटलर ने यह उपलब्धि गुरुवार रात श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में हासिल की। उन्होंने इस मैच में 16 गेंद पर 30 रन बनाए। इस मैच को इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीता। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 145 रन बनाए। इंग्लैंड ने 12.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टॉम बैंटन ने 24 गेंद में नाबाद 52 रन बनाए। श्रीलंका ने पथुम निसांका की तेज शुरुआत के दम पर 5 ओवर में बिना विकेट खोए 55 रन बना लिए थे। निसांका ने 21 गेंद में 37 रन बनाए। इसके बाद श्रीलंकाई पारी लड़खड़ा गई। टीम ने बाकी 15 ओवर में 90 रन जोड़कर 9 विकेट गंवा दिए और 145 रन तक ही पहुंच सकी।

खिलाड़ी की उम्र 15 हो या फिर 30 वर्ष मौके का इंतजार करना पड़ेगा: गंभीर

एजेंसी, नई दिल्ली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका क्यों नहीं मिला। हेड कोच गौतम गंभीर ने वीरवार को इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी की उम्र 15 हो या 30 साल, अगर उसे मौके का इंतजार करना है तो इंतजार करना होगा। गंभीर ने कहा, 'वैभव के साथ बातचीत स्पष्ट थी कि उसे मौके का इंतजार करना होगा। जब मौका मिलेगा, तो लगातार मिलेगा। गंभीर ने कहा कि हम जानते हैं कि उसमें किस तरह की प्रतिभा है और वह क्या कर सकता है। लेकिन जो खिलाड़ी दो साल से लगातार अच्छा खेल रहा है, वह उस खिलाड़ी से आगे रहेगा जो टीम में नया आया है।

इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से दी मात

एजेंसी, कार्डिफ

लियाम डॉसन और टॉम बेंटन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वीरवार देर रात श्रीलंका को छह विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने आक्रामक शुरुआत की। पाथुम निसांका ने जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में तीन चौके जड़ दिए, जबकि लाहिरू उदारा ने भी बाद में तेजी पकड़ी। श्रीलंका ने पांचवें ओवर के आधे पड़ाव तक 50 रन पूरे कर लिए। इंग्लैंड के कप्तान ने पावरप्ले के अंतिम ओवर में लियाम डॉसन को गेंद सौंपी और बाएं हाथ के स्पिनर ने लगातार दो गेंदों पर विकेट लेकर श्रीलंका की रफ्तार पर अंकुश लगा दिया। अंतिम ओवर में आर्चर ने दो विकेट झटके और श्रीलंका ने सात रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए। पूरी टीम 20 ओवर में 145 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड ने भी तेज शुरुआत की। एनेयूरिन डोनाल्ड ने दुश्मंथा चमीरा के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की, जबकि जोस बटलर ने दिलशान मदुशंका के एक ओवर में चार चौके जड़े।

इसी दौरान बटलर टी20 क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने। इंग्लैंड ने 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। हसरंगा ने फ्री हिट पर मिडऑफ की ओर जा रही गेंद का पीछा करते हुए कैच भी छोड़ दिया, जो श्रीलंका के लिए निराशाजनक रात का एक और उदाहरण रहा।

अभिषेक शर्मा पावरप्ले में टी-20 के हाईएस्ट स्कोरर

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ने तीसरे टी-20 में अफगानिस्तान को 127 रन से हरा दिया। दिल्ली में खेले गए मुकाबले में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 108 रन बनाए। उन्होंने इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। अभिषेक टी-20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही उन्होंने ओवरऑल टी-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों में विराट कोहली की बराबरी की। दोनों के नाम 10 शतक हैं। इसके अलावा उन्होंने 30 गेंद पर शतक लगाकर रोहित शर्मा के फास्टेस्ट सेंचुरी का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अभिषेक ने दिल्ली में पावरप्ले के 6 ओवर में 22 गेंदों पर नाबाद 76 रन बनाए। यह पुरुष टी-20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। पुर्तगाल के कुलदीप घोलिया 74 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

शतरंज ओलंपियाड में भारत ने इंडोनेशिया को 2.5-1.5 से हराया

एजेंसी, समरकंद

शतरंज ओलंपियाड के दूसरे दौर में वीरवार को भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में जीत दर्ज की। ओपन वर्ग में भारत को इंडोनेशिया के खिलाफ 2.5-1.5 की जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि महिला टीम ने फिनलैंड को 3.5-0.5 से हराकर आसान जीत दर्ज की।

पहले दौर में आराम दिए जाने के बाद वापसी कर रहे आर. प्रज्ञानानंद ने शीर्ष बोर्ड पर काले मोहरों से इंडोनेशिया के सुशांतो मेगारांतो के खिलाफ लंबा मुकाबला खेला। खेल एंडगेम तक पहुंचा और 79 चालों के बाद दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ पर सहमति जताई। निहाल सरीन ने भारत को पहली सफलता दिलाई। सफेद मोहरों से आईएम आरिफ अब्दुल हाफिज के खिलाफ खेलते हुए, निहाल ने धीरे-धीरे दबाव बढ़ाया और अंतिम चरण में सामरिक बढ़त हासिल कर ली। हाफिज ने 37.एनसी5+ के बाद बाजी छोड़ दी। डी. गुकेश को काले मोहरों से आईएम सात्रिया दुटा चहाया के खिलाफ जीत का रास्ता नहीं मिला। मंकाबला 51.क्यूडी1+ के बाद ड्रॉ हुआ। विदित गुजराती और आईएम नायका बुधिधर्मा के बीच मुकाबला भी बराबरी पर समाप्त हुआ। सफेद मोहरों से खेल रहे विदित ने संतुलित स्थिति हासिल की और 34.एच3 के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अंक बांट लिए। इस तरह एक जीत और तीन ड्रॉ के साथ भारत ने मुकाबला 2.5-1.5 से अपने नाम किया। भारत ने पहले दौर में थाईलैंड को 3-1 से हराया था।

दिव्या, वंतिका और साविता ने दिलाई महिला टीम को

महिला वर्ग में भारत ने फिनलैंड के खिलाफ 3.5-0.5 से शानदार जीत दर्ज की। कोनेरू हम्पी को इस दौर में आराम दिए जाने के कारण वैशाली रमेशबाबू ने शीर्ष बोर्ड पर मोर्चा संभाला। उन्हें अनास्तासिया केइनानेन ने कड़ी चुनौती दी और 88 चालों के बाद मुकाबला ड्रॉ रहा। बाकी तीनों बोर्ड भारत के पक्ष में रहे। दिव्या देशमुख ने जोहाना पासिकांगस-तेल्ला को 38 चालों में हराया। वंतिका अग्रवाल ने सबसे तेज जीत दर्ज करते हुए सारा-ओलिविया सिप्पोला को केवल 22 चालों में मात दी।

एएआई ने शुरू किया यात्री सेवा अभियान

एजेंसी, नई दिल्ली

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने देशभर के अपने सभी हवाई अड्डों पर यात्री सेवा अभियान शुरू किया है। 17 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर, तेज और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ हवाई अड्डों पर स्वच्छता, सुविधा और आतिथ्य का माहौल मजबूत करना है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने गुरुवार को पुणे हवाई अड्डे पर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा सहित मंत्रालय और एएआई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पुणे हवाई अड्डे पर अभियान की शुरुआत स्वच्छता गतिविधियों के साथ हुई। इस दौरान स्वच्छता अभियान चलाने के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत पौधारोपण किया गया। इसके अलावा 'स्वच्छता ही सेवा' रैली भी निकाली गई। रैली के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने और सफाई के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया।

एएआई के अनुसार, 'यात्री सेवा अभियान' के तहत 'सेवा और संकल्प' थीम पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान में यात्रियों की पूरी यात्रा प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया जाएगा। इसमें हवाई अड्डों पर सुगमता, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और संपर्क सुविधाएं, रास्ता खोजने में सहायता तथा सामान से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा सुविधाओं, जरूरी यात्री सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं, प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण व्यवस्था को भी अभियान का हिस्सा बनाया गया है।

त्योहारी सीजन में सस्ती हो सकती हैं कारें

एजेंसी, मुंबई। भारत में त्योहारी सीजन के दौरान कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों को अतिरिक्त छूट और आकर्षक ऑफर मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। खासतौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित व्यवस्था में बदलाव की चर्चा है। यदि कंपनियों को कर लागत में राहत मिलती है तो इसका कुछ लाभ ग्राहकों तक पहुंचने की संभावना है।

ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए त्योहारी सीजन बिक्री बढ़ाने का महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान कंपनियां नकद छूट, पुराने वाहन के बदले बोनस और अन्य प्रोत्साहन देती हैं। आईटीसी व्यवस्था में बदलाव से कंपनियों की लागत और कार्यशील पूंजी पर दबाव कम हो सकता है। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर में कार खरीदारों को मौजूदा ऑफर के अलावा अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक सात अक्टूबर को प्रस्तावित है। इससे पहले अधिकारियों के स्तर पर संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

सेंसेक्स 20 अंक गिरा, निफ्टी 76 अंक चढ़ा

एजेंसी, मुंबई

घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 20 अंक की गिरावट के साथ 74,295 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंक चढ़कर 23,346 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान मीडिया, मेटल, फार्मा और रियल्टी क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा। इसके विपरीत आईटी और एफएमसीजी क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। क्षेत्रवार गतिविधियों के कारण प्रमुख सूचकांकों में अलग-अलग दिशा देखने को मिली।

इसी बीच बीगाईटेड डेवलपर्स के शेयर की बाजार में मजबूत शुरुआत हुई। कंपनी का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 11 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 154 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी शुरुआत करीब आठ प्रतिशत प्रीमियम के साथ 151 रुपये पर हुई। कंपनी के शेयर का निर्गम मूल्य 140 रुपये था। इस तरह सूचीबद्धता के समय निवेशकों की ओर से शेयर में अच्छी दिलचस्पी दिखाई दी।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी घरेलू बाजार को सकारात्मक संकेत मिले। एशियाई बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.66 प्रतिशत, जापान का निक्केई 1.38 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 0.60 प्रतिशत बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे पहले अमेरिकी बाजारों में भी तेजी दर्ज की गई थी। डाउ जोन्स 0.61 प्रतिशत, नैस्डैक 1.69 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 1.14 प्रतिशत की बढ़त रही।

हालांकि, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले सात दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 8,219 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। पिछले 30 दिनों में उनकी शुद्ध बिकवाली 18,813 करोड़ रुपये रही।

आईफोन 18 प्रो खरीदने के लिए दिल्ली-मुंबई में उमड़ी भीड़

एजेंसी, मुंबई

आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और डुओ की बिक्री शुरू होते ही दिल्ली और मुंबई में ग्राहकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नए आईफोन को खरीदने के लिए लोग रात से ही एप्पल स्टोर के बाहर कतार में खड़े नजर आए। दिल्ली के साकेत स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एप्पल स्टोर के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच गए थे। कई लोग 12 घंटे से अधिक समय तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे।

दिल्ली में ग्राहक अजय ने बताया कि उन्होंने आईफोन 18 प्रो मैक्स का एक टेराबाइट मॉडल पहले ही बुक कर लिया है। वह फिलहाल आईफोन 17 प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं और नए फोन में मिलने वाले फीचर्स को लेकर उत्साहित हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर सूरज चौहान भी नया फोन खरीदने पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह पहले आईफोन 17 प्रो खरीद चुके हैं और अब आईफोन 18 प्रो तथा प्रो मैक्स लेने आए हैं। उन्हें नए मॉडल के कैमरे और समग्र गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

मुंबई में भी नए आईफोन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। स्टोर के बाहर हजारों टेक प्रेमी रातभर कतार में खड़े रहे। नासिक से मुंबई पहुंचे हितेश पटेल ने बताया कि वह रात 10 बजे से लाइन में खड़े थे और उन्हें सुबह आठ बजे का पहला स्लॉट मिला। हितेश हर साल अपना फोन अपग्रेड करते हैं और फिलहाल आईफोन 17 प्रो मैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं।

पावरग्रिड

पावरग्रिड के बॉन्ड प्रस्ताव को निदेशक मंडल की मिली मंजूरी

बॉन्ड से 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी पावरग्रिड

एजेंसी, नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली पारेषण कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉन्ड जारी कर 5,000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी के निदेशक मंडल की बॉन्ड पर निर्णय लेने वाली समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि बॉन्ड निजी नियोजन के आधार पर जारी किए जाएंगे। ये असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी, भुनाने योग्य और कर योग्य होंगे। इस कदम के जरिये कंपनी अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाएगी।

पावरग्रिड के अनुसार, प्रस्तावित बॉन्ड का मूल निर्गम 1,000 करोड़ रुपये का होगा। इसके साथ 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त हरित विकल्प रखा गया है। इसका अर्थ है कि यदि बॉन्ड को लेकर मांग और बोलियां अधिक आती हैं तो कंपनी कुल 5,000 करोड़ रुपये

तक के बॉन्ड जारी कर सकती है। इस व्यवस्था से कंपनी को बाजार की मांग के अनुसार अधिक पूंजी जुटाने का अवसर मिलेगा।

इन बॉन्ड की अवधि 10 साल निर्धारित की गई है। आवंटन के चार साल पूरे होने के बाद भुगतान शुरू किया जाएगा। हालांकि, बॉन्ड पर कितना ब्याज दिया जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। ब्याज दर बाद में तय की जाएगी। बॉन्ड निजी नियोजन के तहत जारी होने के कारण कंपनी चुनिंदा निवेशकों के माध्यम से यह पूंजी जुटाएगी।

घोषणा के बाद शेयर बाजार में पावरग्रिड के शेयर में तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर दो रुपये यानी 0.76 प्रतिशत बढ़कर 265.50 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में तिमाही आधार पर गिरावट भी दर्ज हुई है। चालू वित्त वर्ष में 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में पावरग्रिड ने 9,795 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इस दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 3,411 करोड़ रुपये रहा, जबकि प्रति शेयर आय 3.67 रुपये दर्ज की गई।

पिछली तिमाही यानी 31 मार्च को समाप्त तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 4,553 करोड़ रुपये था और प्रति शेयर आय 4.90 रुपये रही थी। इस तरह तिमाही आधार पर राजस्व लगभग स्थिर रहने के बावजूद शुद्ध लाभ और प्रति शेयर आय में गिरावट आई। ऐसे समय में बॉन्ड के जरिये पूंजी जुटाने का निर्णय कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

पावरग्रिड देश के बिजली पारेषण ढांचे से जुड़ी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। बॉन्ड जारी कर जुटाई जाने वाली पूंजी से कंपनी को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। 5,000 करोड़ रुपये तक की प्रस्तावित राशि में से 1,000 करोड़ रुपये मूल निर्गम और 4,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त हरित विकल्प के तहत होंगे।